

सम्पादकीय

नर्सों में घुलता नशा

ड्रग्स तस्करी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। नशा को फैलता जाल बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ के लोगों को नशा की लत नहीं लगी हो। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। दिल्ली में पांच हजार करोड़ की कोकीन और थाइलैंड की मारिजुआना ड्रग्स की बरामदगी इस बात का संकेत दे रही है कि देश में या तो इसकी खपत कई गुणा बढ़ चुकी है या फिर भारत नशीले पदार्थों की आपूर्ति के किसी बड़े नेटवर्क का केन्द्र बन गया है। दिल्ली पुलिस ने अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। नशा की इस खेप को दिवाली, दशहरे से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना था। इसके लिए पूरी सप्लाई चेन तैयार रखी गई थी। नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी खेप अलग-अलग देशों से होती हुई भारत पहुंची थी। कोकीन की यह खरीद-फरोख्त पैसे से नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी के साथ की जाती थी। त्योहारों के दिनों में दिल्ली, मुंबई, गुजरात और देशभर में बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। इन कार्यक्रमों में नशा की खेप पहुंचाई जाती थी। किसी समाज और देश को भीतर से खोखला करना हो तो उसकी युवा शक्ति को नशा की गर्त में धकेलना काफी है। पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्यों में नशा की लत के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है। आज देश में कहीं से कोई भी व्यक्ति नशा का सामान खरीद सकता है। उसे ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। नशा का सामान बेचने वाले सौदागर दिनों दिन धनवान होते जा रहे हैं। जिस कारण से उनका पुलिस व प्रशासन पर पूरा प्रभाव रहता है। जिसकी बदौलत वह शासन, प्रशासन से मिलकर सरैआम धड़ल्ले से अपना धंधा करते रहते हैं। नशा की प्रवृत्ति के खिलाफ हमारा समाज भी जागरूक नहीं है। नशा की लत के चलते पंजाब जैसा संपन्न प्रांत नशेइशियों का प्रदेश कहलाने लगा था। वैसे ही स्थिति आज देश के अधिकांश प्रदेशों की हो रही है। नशा को लेकर पंजाब जब सुर्खियों में आया तो पूरे देश का ध्यान उस तरफ गया।

पुलिस, भारतीय नौसेना, एनसीबी, डीआरआई समेत कई एजेंसियां एक साथ मिलकर ड्रग्स के खिलाफ सख्त मुहिम चला रही हैं। इसके बावजूद गुजरात और मुम्बई के बंदरगाहों पर करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। भारत में सबसे अधिक ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान से आती है। यानी भारत का मुख्य स्रोत अफगानिस्तान है। इसके पीछे भी कारण है, अफगानिस्तान में काफी समय से वहां पर अफीम की खेती और तमाम नशीली दवाइयों का व्यापार होता आ रहा है। अब तो तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस तरह के व्यापारों में काफी तेजी देखी जा रही है। भारत समेत दुनिया भर में 80 से 85 प्रतिशत ड्रग्स की सप्लाई अफगानिस्तान से होती है। तालिबान इन्हें पैसों की बदौलत अपने आप को मजबूत कर रहा है। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों में तालिबान ने नाक में दम कर रखा है। वहीं इसमें पाकिस्तान की भी अहम भूमिका होती है। भारत के पंजाब, श्रीनगर और राजस्थान में सीमा के पास कई बार ड्रग्स और अफीम की खेप को पकड़ा जाता है। कई बार तो इसके लिए तस्कर सुर्ग तक खोंद डालते हैं।

मोदी का बार-बार महाराष्ट्र दौरा, क्या विधान सभा चुनावों की तैयारी है?

महाराष्ट्र के इस दौर में प्रधानमंत्री ठाणे में 32,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण-1 के आरे जेवीएलआर से बीकेसी को जोड़ने वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे। वह शाम करीब 6 बजे बीकेसी मेट्रो स्टेशन से आरे जेवीएलआर तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वह बीकेसी और सांताक्रूज स्टेशनों के बीच मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। बता दें कि मुंबई की यह अंडरग्राउंड मेट्रो एका लाइन-3 देश की पहली संपूर्ण भूमिगत मेट्रो है।

अशोक भाटिया

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र का बार-बार दौरा करके सियासी माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। महाराष्ट्र के बदले हुए सियासी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में यह तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह वाशिम, ठाणे और मुंबई में विकास की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी थी। इसके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी वाशिम में लगभग 23,300 करोड़ रुपये की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत की झांकी प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुल 56,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। मुंबई मेट्रो-3 प्रोजेक्ट का पहला चरण 12 किलोमीटर से अधिक लंबा है जो 10 स्टेशनों को कवर करेगा। इससे यात्रा में सुविधा होगी और मुंबई के ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ठाणे इंटीग्रेल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सपैंशन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई हवाई अड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रख रहे हैं। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर में करीब 2000 करोड़ रुपए की आठ अमृत (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन) परियोजनाओं की आधारशिला रख चुके हैं। इसके अलावा मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 90000 से अधिक घरों को भी हितग्राहियों को समर्पित किया और साथ ही सोलापुर में रायगर हाउसिंग सोसाइटी के 15000 घरों को भी लाभार्थियों को सौंपा। इन लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, श्रमिकेता, पावरलूम श्रमिक, कृषि बीनने वाले, बीड़ी श्रमिक और चालक शामिल हैं महाराष्ट्र के नासिक में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का अनावरण किया था और लगभग 15,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं की सौंपात दी थी। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और हजारों करोड़ के विकास योजनाओं को राब्य को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की राज्य की लगातार यात्राएं उनकी लोकप्रियता और उनकी सरकार के विकास संदेश का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अर्धांकतम सीटें जीतने की भाजपा की कोशिशों को दर्शाती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के ये दौरें कई हलचल से महत्वपूर्ण माना जा रहे हैं, पिछले 15 महीनों में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार महाराष्ट्र का दौरा किया है। प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करें तो उसका असर बड़ा होता है और गारंटी वाला होता है। भाजपा इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। शिंदे सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जून 2022 में



नागपुर गए थे। उसके बाद के 13 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर समृद्ध महामार्ग का उद्घाटन किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नागपुर मेट्रो के फेज-1 को देश को समर्पित किया और फेज-2 की नींव रखी। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और कुछ का उद्घाटन किया। मुंबई मेट्रो से सफर भी किया। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई को शिरडी और सोलापुर से जोड़ने वाली दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। सांताक्रूज-चेंबर लिंक रोड और कुरार अंडरपास का भी उद्घाटन किया। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री ने पुणे के एक कार्यक्रम में शिरकत की। तब उनके साथ हृदयचर्च शरद पवार भी स्ट्रेज पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई और पिंपरी-चिंचवड में एक एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया। 14 अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी के 141वें सत्र में हिस्सा लिया। 26 अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री ने अहमदनगर का दौरा किया। तीन दशक से अटके निलवडे डैम को जनाता को समर्पित किया। उसी दिन प्रधानमंत्री शिरडी मंदिर गए और श्रद्धालुओं के लिए बने शानदार एरिडी वेंटिंग रूम का उद्घाटन किया। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों रुपयों से नवी मुंबई में 'अटल सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के बार-बार महाराष्ट्र जाने पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने कई बार निशाना साधा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री को हर महीने राज्य में आना पड़ रहा है तो यह दिखाता है कि महाराष्ट्र में भाजपा किन्ती कमजोर हो गई है। हालांकि, भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी के जादू पर पूरा भरोसा है। राज्य भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बानवकुले ने कहा कि हम हमारे प्रधानमंत्री विकास के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारा संभार्य है कि ऐसा नेता मिला है जो जनाता और उनके उत्थान को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री और भाजपा जो भी वादे करते हैं, उन्हें रिस्कॉर्ड टाइम में पूरा किया जा रहा है। पार्टी के रूप में हम अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन तो करेंगे। इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिसंबर 2022 में नागपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने समृद्ध महामार्ग को

समर्पित किया था। इस योजना का लाभ विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में मिलने की उम्मीद है। उद्भव ठाकरे के सत्ता से बेदखल होने और शिंदे के अगुवाई में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला महाराष्ट्र दौरा था। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी सात बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं और शुक्रवार को सोलापुर का 8वां दौरा है। सोलापुर का इलाका कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे का गढ़ माना जाता है जिन्हें भाजपा अपने साथ मिलाने की कवायद में है। इस बात को सुशील कुमार शिंदे ने खुद कहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी के सोलापुर से विकास की सौंपात से नवाज कर विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण साधने का दांव चला है। फरवरी 2023 में मुंबई को शिरडी और सोलापुर के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों से जोड़ने वाली दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सांताक्रूज-चेंबर लिंक रोड और कुरार अंडरपास का उद्घाटन किया था, जिम्का उद्देश्य शहर में यातायात को कम करना था। सात महीने बाद अगस्त 2023 में, एक कार्यक्रम के लिए पुणे की यात्रा के दौरान पीए मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मंच साझा किया। मोदी ने एक मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम के लिए एक ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी थी। सितंबर में मोदी ने अहमदनगर जिले का दौरा किया और निलवडे बांध के बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को लोगों को समर्पित किया था, जो 5,177 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना थी और ये तीन दशकों से लंबित थी। उसी दिन, प्रधानमंत्री ने शिरडी मंदिर का दौरा किया और तीर्थयात्रियों के लिए अत्याधुनिक वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष सुविधा का उद्घाटन किया था। बताया जाता है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ताजड़ा झटका खा चुकी है। इसके देखते हुए बीजेपी इस बार विधानसभा चुनावों में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। 408 सीटों वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा के बाद महाराष्ट्र 283 सीटों वाली विधान सभा है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बड़ा चुनाव था, महा विकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीतीं जबकि महा युति को केवल 17 सीटें ही मिल सकीं।

**आज का राशिफल**  
हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अलग-अलग आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कोनेस देय है, जस आपके रिश्ते बृहद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। इन व सिर्फ हमारे पास है और जितने लक्ष्यों को सुलझाने वगत स्वभावतःक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जल व सह स्वभावतःक हवी संसात और बतौरतःक नैन प्रदान करेंगे।

**मेष**  
विरोधियों से विजय प्राप्त करेंगे। दिन के दौरान आकस्मिक घटनाओं में व्यस्त रहेंगे। आज आप शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। नौकरी-धंधे में उच्च अधिकारी या भागीदार के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा।

**वृष**  
शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। मित्रों, सौहार्दजनों से लाभ होगा। शरीर में थकान और बेचैनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। मन चिंता से व्याकुल रहेगा। आज यात्रा स्थगित रखने की सलाह दी जाती है। संतान के विषय में चिंता रहेगी।

**मिथुन**  
आप पूरे दिन शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। परिश्रम को अपेक्षा कम सफलता मिलने से निराशा रह सकती है। नौकरी और व्यापार के संबंध में थोड़ा चिंतित रहेंगे। काम की भागदौड़ में परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे।

**कर्क**  
व्यवसाय करने वालों को सरकार की तरफ से लाभ मिलने और नौकरीपेशा को उच्च अधिकारियों की कृपावृष्टि मिलेगी। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लंबे प्रवास का आयोजन संभव होगा।

**सिंह**  
विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान के अध्ययन या अन्य मामलों के पीछे धन खर्च या पूंजी निवेश होगा। कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का उत्तम समय है। सरकार से लाभ होने की संभावना है।

**कन्या**  
किसी के साथ गलतफहमी होने के कारण मनमुटाव हो सकता है। परिवारिक वातावरण खराब हो सकता है। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ निर्णय के कारण आज आप कोई भी काम त्वरित निर्णय लेकर पूरा करेंगे। परिणामस्वरूप मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे।

**तुला**  
गृहस्थ जीवन में सुख-शांति का अनुभव होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। आय में वृद्धि होगी। उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनी रहेगी। आज आपके हरेक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे।

**वृश्चिक**  
कोर्ट-कचहरी का कामों को आज टाल देना हितकर है। आज विविध क्षेत्र में लाभ मिलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात, रमणीय स्थानों पर प्रवास पर्यटन का आयोजन होगा।

**धनु**  
शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। परिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। उग्र वाणी और अहं के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है।

**मकर**  
पिता तथा अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा। मन आनंदित रहेगा। फिर भी स्वभाव में उदात्ता का असर आपकी वाणी पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामूली शिकायत रहेगी।

**कुंभ**  
गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। मान प्रतिष्ठ में वृद्धि होगी। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति होगी। अधिकारी और घर में बड़ों से लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। व्यापारियों को उधार दिया पैसा मिलेगा। संतान की प्रगति से मन खुश रहेगा।

**मीन**  
आज यात्रा को टालना हित में होगा। पाचन तंत्र संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से किसी को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। आज आप सभी काम दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से पूरा करेंगे। आंख संबंधी शिकायत पैदा होगी।

शरित्सयत

**बढ़ता राजस्थान**  
'काम करो तो ऐसे करो कि नाम हो जाए या फिर नाम करो तो ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए'  
नमस्कार मित्रों! हमारी आज शरित्सयत कॉलम के सुपर डुपर स्टार हैं बाबा कलाकंद के निदेशक युवा समाजसेवी और उद्योगपति अभिषेक तनेजा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीकर करते या याद करते ही मुंह में मिठास भुरल जाती है, मन स्वतः ही मुस्कान से भर जाता है। ऐसे ही शख्स है हमारे शेखू भैया, इनका जन्म 4 नवंबर सन 1982 को अलवर में हुआ। शिक्षा में इन्होंने बीकॉम कॅलीट कर सन 2002 में अपना पूतक व्यवसाय में कदम रखा। बाबा कलाकंद जिसे अलवर की सौंगत के रूप में जाना जाता था। उसमें पूरी शिहत के साथ जुट गए और लोगों के प्यार,बाबा साहब के विश्वास व आर्शिवाद और खुद पर भरोसे के साथ शुरू किया ब्रांड बाबा कलाकंद का सफर। भंडाघर कलाकंद शॉप से अपने करियर की शुरुआत की पिताजी और ताऊजी के आशीर्वाद से लोगों के



अभिषेक तनेजा (युवा समाजसेवी व निदेशक बाबा कलाकंद)

नहीं है। नेक कमाई फंडेशन के दो सिलाई केंद्र भी चल रहे हैं जिनमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आगामी सत्र में नेक कमाई चिकित्सा के क्षेत्र में भी नया मुकाम हासिल करेगा यह उनकी दिली इच्छा है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम ऐसे युवा नौजवान, हंसमुख, हृदयदर्द और मिलनसार व्यक्ति को सलाम करती है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।  
**रूपक शर्मा**

विशेष आलेख

मिलावटी आहार से बढ़ती बीमारियां

विजय गर्ग

पिछले कुछ समय में छोटे बच्चों और युवाओं में हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से मौत के मामले तेजी से बढ़े हैं। कवक यानी 'फंगस' और विषाणु से होने वाली खतरनाक बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। विश्व नाक स्वास्थ्य संगठन की रपट के मुताबिक 2022 में देश में कैंसर के 14.1 लाख नए मामले सामने आए, जिसमें नौ लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। रपट के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया भर में कैंसर की बीमारी और बढ़ेगी। कैंसर पर शोध की अंतरराष्ट्रीय संस्था आइएआरएसी के अनुसार पिछले वर्षों में मुंह, गला और स्तन कैंसर में बढ़ोतरी के अलावा पैंतीस प्रकार के कैंसर में वृद्धि हुई है। पेट, मलाशय, प्रोस्टेट, त्वचा और रक्त कैंसर एकाएक वृद्धि हेरान करने वाली है। देश में जहां लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, वहीं यह कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी का कारण भी बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2035 तक भारत में कैंसर से मरने वालों की संख्या पैंतीस लाख प्रति वर्ष तक पहुंच जायेगी। कैंसर का कारण मानव शरीर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि और उनका विभाजन है। रसायन युक्त भोजन सामग्री और खराब जीवन शैली भी इसकी वजह है 'सेंटर फ़ार साइंस एंड एनवायरमेंट' (सीएसई) की रपट के मुताबिक शहरों में रह रहे 93 फीसद बच्चे सप्ताह में एक दिन डिब्बाबंद खाद्य सामग्री खाते हैं, जबकि 53 फीसद बच्चे प्रतिदिन तुरंत आहार यानी 'जंक फूड' खाते हैं। शहरों से लेकर गांवों के गरीब बच्चों तक की दिनचर्या 'जंक फूड' से शुरू हो रही है। वर्ष 2011 से 2021 की अवधि में देश में 'जंक फूड' का कारोबार 13.37 फीसद की दर से लगातार बढ़ रहा है। इससे देश के ग्यारह फीसद बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं। लांसेट पत्रिका की शोध रपट 2022 के मुताबिक 1.25 करोड़ बच्चे अपेक्षित वजन से अधिक मोटे थे। यह संख्या आंकड़ों की तुलना में 25 गुना अधिक बढ़ रही है। इसकी वजह देश में बहुराष्ट्रीय कंपन मिलना है। विदेशी व्यापार को अनुमति मिलने के बाद कंपनियों को खानपान की सामग्री सहित सभी तरह के व्यापार की खुली अनुमति। से देश में प्रसंस्कृत डिब्बाबंद सामग्री का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। वर्ष 1990 के दशक देश में गरीब से लेकर अमीर और छोटी से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग डिब्बाबंद चीजों को तुरंत भूख मिटाने की खाद्य सामग्री मान चुके हैं। बड़ी संख्या में आम जन अब काम के दौरान घर से बना नाश्ता ले जाने के बजाय, बजार की खाद्य सामग्री पर आश्रित हो हो चुके हैं। देश में बीस वर्ष से अधिक उम्र के सात से अधिक वयस्क, जिनकी दैनिक भोजन सामग्री में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं, स्वयं को तंदुरुस्त नहीं मानते हैं डिब्बाबंद भोजन में अधिक नमक, शीतल पेय में कृत्रिम मिठास के साथ ५0प्रिजर्वेटिव-की अत्यधिक मात्रा यकृत, गुर्दे की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर आदि सहित कैंसर रोग के लिए जिम्मेदार हैं। कृत्रिम पेय पदार्थ, चाकलेट और डिब्बाबंद फलों के रस से मूत्र में संक्रमण की शिकायतें देश में तेजी से बढ़ी हैं। सीएसई के आंकड़े बताते हैं कि देश में



71 फीसद आबादी स्वस्थ आहार नहीं ले रही है। जिसकी वजह से देश में प्रतिवर्ष 17 लाख लोग मधुमेह, कैंसर, तपेदिक और हृदय संबंधी बीमारियों से मौत का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका के 'इंस्टीट्यूट फ़ार हेल्थ मैट्रिक्स एंड पोल्यूशन' की रपट के अनुसार सिगरेट और शराब के बाद विश्व में अधिक मौत तय मात्रा से अधिक नमक खाने से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति वयस्क प्रतिदिन 02 ग्राम से अधिक मात्रा की अनुमति नहीं देता है 'टाक्सिक्स लिंक' नामक गैरसरकारी संगठन के एक शोध में दावा किया गया है कि देश में बढ़ते कैंसर और दिल के रोग की एक वजह नमक और चीनी में मौजूद प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हैं। डिब्बाबंद सामग्री में चिंता का विषय नमक या शर्करा ही है। अमेरिका की एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के विरुद्ध वहां की हजारों महिलाओं ने इस आरोप के साथ मामला दायर कराया है कि उसके उत्पाद से 'मेसोथेलियोमा कैंसर' फैल रहा है। जबकि भारत में इन उत्पादों को उच्च गुणवत्ता का बत कर धड़ल्ले से बेचा रहा है शारीरिक सौंदर्य की उक को शरीर पर अधिक समय तक प्रसाधन टिकाऊ बनाने के लिए एस्बेस्टस उपयोग होता है। ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च की रपट के मुताबिक सौंदर्य सामग्री में एस्बेस्टस उपलब्ध तकनीक से पकड़ना आसान नहीं है। इसलिए कैंसर के पास अधिककम दो हजार दुकानों की निगरानी का जिम्मा होना चाहिए, लेकिन राज्यों में एक-एक खाद्य निरीक्षक पर पंद्रह हजार दुकानों तक की निगरानी का दायित्व है। वर्ष 2022 2 तक देश देश में मात्र 224 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं। जिसमें सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या सौ से ज्यादा नहीं है। प्रयोगशालाओं कमी के कारण समय पर जांच न होने से मिलावट करने वाले दंड क्रिया से बाहर हो जाते हैं।



## सम्पादकीय

## नई योजनाएं, पुराने सवाल क्या खेती का घाटा भर पाएगी सरकार की प्रोत्साहन योजना?

केंद्रीय मंत्रिमंडल की कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलाने से स्वाभाविक ही इस क्षेत्र में कुछ बेहतरी की उम्मीद जगी है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना नामक दो नई योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि इस क्षेत्र के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। कृषि कर्ज और फसल बीमा को सुविधाजनक बनाया गया है। किसानों की प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर छह हजार से दस हजार रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। इनके बीच दो नई योजनाएं शुरू होने से खेती-किसानों में कुछ बेहतरी की संभावना बन सकती है। सरकार ने इस वर्ष तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। वह वादा पूरा तो नहीं हो पाया, पर कुछ तरक्की के संकेत जरूर मिले हैं। देखा जाय, नई योजनाएं इस वादे को पूरा करने में कितनी और कहां तक मददगार साबित होती हैं। सरकारी दावों के बरकस जमीनी हकीकत कुछ अलग है। स्थिति यह है कि खेती लंबे समय से घाटे का उद्यम बन चुकी है। बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां किसानों को मानसून पर निर्भरता है। फिर, खेती में लागत काफी बढ़ गई है। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों आदि की कीमतें बहुत सारे किसानों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। लागत और लाभ में काफी अंतर है। कुछ फसलें लागत से भी कम कीमत पर बेची पड़ती हैं।

सरकार हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो करती है, मगर उस कीमत पर भी अनाज बाजार में नहीं बिक पाता। बिचौलिया उससे काफी कम कीमत पर फसल खरीदते हैं। नगदी फसल उगाने वाले किसानों को अक्सर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम की मार से फसलें चौपट हो जाती हैं, तो कभी बाजार में उतार और मांग कम होने के कारण उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। हर वर्ष किसानों को प्रतिरोध में फसलें सड़कों पर फेंकते देखा जाता है। इस स्थिति से पार पाने में ये योजनाएं कितनी सफल होंगी, यही उनकी कसौटी होगी।

सरकारों दावा क बरकस जमाना हकीकत कुछ अलग है। स्थिति यह है कि खेती लंबे समय से घाटे का उद्यम बन चुकी है। बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। बढ़ती आबादी के मदेनजर खाद्य सुरक्षा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव सबसे अधिक खेती-किसानों पर देखा जा रहा है। हर वर्ष अन्न उत्पादन बढ़ाने की राह में मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन की दरकार महसूस की जाती रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से स्वाभाविक ही इस क्षेत्र में कुछ

## आधुनिक जीवन की बड़ी चुनौती रिश्तों में उपेक्षा और विश्वास की कमी

संवाद और संचार किसी भी रिश्ते का बुनियादी आधार होता है। अगर रिश्ते में उपेक्षा बढ़ रही हो और विश्वास की कमी हो रही हो, तो सबसे पहले दोनों पक्षों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अपनी भावनाओं, चिंताओं और समस्याओं को एक-दूसरे के सामने रखना चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हों। हर अगले रोज थोड़ा ज्यादा मशीनी होती जिंदगी में यह एक सामान्य अनुभव है कि रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या फिर एक प्रेम संबंध, सभी रिश्तों की नींव विश्वास और आसुसी समझ पर टिकी होती है, लेकिन कई बार इन्हीं रिश्तों में उपेक्षा का दंश और विश्वास की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो संबंधों को कमजोर कर देती हैं। आजकल जिंदगी की भाग-दौड़ में लोगों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। किसी से उपेक्षित होना किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यह वह स्थिति है जब किसी एक व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसका साथी उसकी भावनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को महत्व नहीं दे रहा है। उपेक्षा धीरे-धीरे रिश्ते को अंदर से कमजोर कर देती है। कामकाजी जीवन, सामाजिक दायित्वों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इससे संबंधों में समय की कमी होने लगती है, जो आखिर उपेक्षा का कारण बनता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में इतना आत्म-केंद्रित हो जाता है कि वह अपने साथी की भावनाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता जाता है। वह अपने सपनों, इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके साथी को महसूस होने लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। एक बात यह भी है कि समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिसका असर कई बार स्पष्ट दिखने लगता है। मसलन, शादी के शुरुआती वर्षों में जो व्यक्ति अपने साथी के साथ अधिक समय

बिताता था, वह बाद में अपने करियर या अन्य गतिविधियों में इतना खो जाता है कि उसका साथी उपेक्षित महसूस करने लगता है। अपने कामकाज के लिए हम किसी अपने की उपेक्षा करके उसका दिल तो दुखा देते हैं, पर उसका प्रभाव गहरा होता जाता है। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है और उसे अपने आप में संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। उपेक्षा से व्यक्ति के भीतर अकेलेपन की भावना पनप सकती है, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है। लंबे समय तक उपेक्षा सहने से व्यक्ति रिश्ते में रुचि खोने लगता है और रिश्ते में दारण पड़ने लगती है। इस तरह के दार को दारने के लिए एक दूसरे पर विश्वास होना आवश्यक है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। यह वह धागा है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है, लेकिन जब इस धागे में दरार आ जाती है, तो रिश्ते का टूटना तय होता है। अक्सर देखा गया है कि कई बार व्यक्ति के अतीत में हुए धोखे और धोखाधड़ी के अनुभव उसे नए रिश्ते में विश्वास करने से रोकते हैं। उसे डर रहता है कि वही इतिहास दोहराया न जाए। और इस डर के कारण वह अपने साथी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता। असुरक्षा

हर अगले रोज थोड़ा ज्यादा मशीनी होती जिंदगी में यह एक सामान्य अनुभव है कि रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या फिर एक प्रेम संबंध, सभी रिश्तों की नींव विश्वास और आसुसी समझ पर टिकी होती है, लेकिन कई बार इन्हीं रिश्तों में उपेक्षा का दंश और विश्वास की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो संबंधों को कमजोर कर देती हैं। आजकल जिंदगी की भाग-दौड़ में लोगों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। किसी से उपेक्षित होना किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यह वह स्थिति है जब किसी एक व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसका साथी उसकी भावनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को महत्व नहीं दे रहा है।



की भावना भी विश्वास की कमी का एक प्रमुख कारण है। व्यक्ति को लगता है कि उसका साथी उसे छोड़ सकता है या धोखा दे सकता है। यह भावना उसे अपने साथी पर विश्वास करने से रोकती है और वह संदेह की दृष्टि से अपने साथी को देखने लगता है। कई बार छोटी-छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। जब दो लोगों के बीच संवाद की कमी होती है, तो वे एक-दूसरे के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये गलतफहमियां विश्वास की कमी का कारण बनती हैं। जब रिश्ते में विश्वास की कमी होती है, तो व्यक्ति को अपने साथी के हर कार्य पर संदेह होने लगता है।

वह साथी के फोन, संदेश, ईमेल आदि की जांच करने लगता है। यह संदेह और असुरक्षा की भावना धीरे-धीरे रिश्ते को अंदर से कमजोर कर देती है। विश्वास की कमी से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, जो धीरे-धीरे रिश्ते के टूटने का कारण बनती है। संवाद और संचार किसी भी रिश्ते का बुनियादी आधार होता है। अगर रिश्ते में उपेक्षा बढ़ रही हो और विश्वास की कमी हो रही हो, तो सबसे पहले दोनों पक्षों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अपनी भावनाओं, चिंताओं और समस्याओं को एक-दूसरे के सामने रखना चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हों और रिश्ते में मजबूती आए।

उपेक्षा से बचने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वह कुछ मिनट के लिए फोन पर बातचीत हो या संवेदना के खोए सूत्रों को फिर से जोड़ना। यह महत्वपूर्ण है कि एक-दूसरे के साथ समय बिताया जाए। आत्म-जागरूकता रिश्ते में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अगर किसी को रिश्ते में उपेक्षा बढ़ रही हो और विश्वास की कमी हो रही हो, तो उसे अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए। कारणों की खोज के बाद उसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दो लोगों के बीच कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन माफ़ी मांगने और माफ़ करने से रिश्ते में विश्वास की भावना फिर से स्थापित होती है। एक-दूसरे की सराहना करना भी रिश्ते को मजबूत करने का एक कारण बनता है। जब कोई अपने साथी के प्रयासों और योगदान को सराहता है, या उससे यह महसूस होता कि उसकी उपेक्षा नहीं हो रही है। यह रिश्ते में सकारात्मकता और प्रेम की भावना को बनाए रखता है। दरअसल, रिश्ते को निभाने में समझ, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास की कमी रिश्तों को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष समय पर इन समस्याओं को पहचानकर उनका समाधान करें, तो रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है।

## लोक से संवाद का अनूठा प्रयोग, शासक का संवाद लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी

आधुनिक लोकतंत्र की पहली शर्त है लोक का चुने हुए शासक से सीधा संवाद। इस संवाद के माध्यम और तरीके पर हमेशा से चिंतन होता रहा है। इन अर्थों में आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे 'मन की बात' कार्यक्रम को लोक संवाद की आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। रेडियो के इतिहास में 'मन की बात' संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित है। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का एक दृश्य है, जहां एक व्यक्ति न्याय की अपेक्षा में राजा दुष्यंत के महल में तीन बजे भोर में पहुंचता है। वह द्वारपाल से राजा से मिलने की अनुमति मांगता है। वह कुछ संकोच भी कर रहा है कि राजा कहीं विश्राम कर रहे होंगे। तब द्वारपाल उस व्यक्ति को समझाता है कि यह

आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं। ऐसा अधिकार उस राजतंत्रिक व्यवस्था में था, जिसे हम पुरातनपंथी मानते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की जटिलताओं के चलते आज के शासक से मिलना आमजन के लिए संभव ही नहीं है। कहीं-कहीं जनता दरबार जैसी संकल्पनाएं हैं भी तो उनमें भी दुष्यंत जैसा लोकतांत्रिक सोच नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र की पहली शर्त है, लोक का चुने हुए शासक से सीधा संवाद। इस संवाद के माध्यम और तरीके पर हमेशा से चिंतन होता रहा है। इन अर्थों में आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे 'मन की बात' कार्यक्रम को लोक संवाद की आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। रेडियो के इतिहास में 'मन की बात' संभवतः पहला

कार्यक्रम है, जो इतना नियमित है। हाल में इसने एक दशक का सफर पूरा कर लिया। सबसे अहम बात यह है कि यह कार्यक्रम तब रेडियो पर आया, जब संचार माध्यमों की क्रांति अपने उफान पर थी। इंटरनेट के विस्तार और विकास ने दो मांचों पर संचार माध्यमों को प्रभावित किया है। उसने खुद में सारे माध्यमों मसलन प्रिंट, रेडियो और टीवी को तो आत्मसात किया ही, खुद को सभी रूपों में एक साथ विस्तारित भी किया। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' के जरिये देश को संबोधित करना शुरू किया, जिसकी वजह से दूसरी पीढ़ी के माध्यम यानी पारंपरिक रेडियो की लोकप्रियता को नई गति मिली। हालांकि इसकी वजह से मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी रहे। उन्हें अक्सर यह उलाहना

भी सुनना पड़े कि उन्हें 'मन की बात' करनी चाहिए। सार्वजनिक माध्यम के जरिये जनता को संबोधित करने की पहली कोशिश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध की आहत की वजह से जहां अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था चरमराने लगी थी, वहीं जर्मनी के हिटलर प्रशासन और से खूब प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा था। ऐसे माहौल में रूजवेल्ट को लगा कि अमेरिकी लोगों को संतुलना देने और दुनिया को अफवाहों से बचाने के लिए उनके सामने सही बात रखी जानी चाहिए। इसके लिए रेडियो उन्हें ज्यादा प्रभावी माध्यम लगा, जिसके जरिये अपनी बात तुरंत लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। रूजवेल्ट ने इस कार्यक्रम का नाम फायरसाइड चैट दिया, जिसके जरिये उन्होंने

अमेरिका और दुनिया को अमेरिका के रुख से न सिर्फ परिचित कराया, बल्कि ध्वस्त होने के कगार पर पहुंची अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था को बचाने के लिए की जा रही अपनी सरकार की कोशिशों की जानकारी भी दी। फायरसाइड चैट के जरिये उन्होंने लोगों की राय बदल दी। 1933 में शुरू हुआ उनका यह रेडियो संवाद 1944 तक जारी रहा। हालांकि उसमें रुकावट भी आ जाती थी। इसकी तुलना में 'मन की बात' नियमित है। 'मन की बात' के पहले एपिसोड का प्रसारण तीन अक्टूबर, 2014 को हुआ, जिसका विषय एक दिन पहले ही शुरू हुआ 'स्वच्छता अभियान' था। उस दिन शुक्रवार था और दशहरा का पावन त्योहार भी। तब से लेकर मार्च 2015 तक महीने के आखिरी शुक्रवार को ही इसका प्रसारण होता

रहा, लेकिन बाद में महीने के आखिरी रविवार का दिन तय हुआ। तब से प्रसारण का यही दिन नियत है। इस कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव ला रहे स्थानीय नायकों का खूब उल्लेख होता है। बिहार की किसान चाची हों या कश्मीर का शिकारा चलाकर परिवार पालता बच्चा या फिर वाराणसी के गंगा घाट की सफाई का अभियान शुरू करने वाली छात्राएं हों, ऐसे तमाम लोगों की इस कार्यक्रम में चर्चा हुई है। इनके जरिये सामाजिक बदलाव लाने वाले लोगों को समाज के सामने प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में उस महीने विशेष के त्योहारों के जरिये भी सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों को प्रस्तुत किया जाता है। मेक इन इंडिया, लोकल के प्रति बोकल, बेटी

बचाओ-बेटी पढ़ाओ, खेती-किसानी में नवाचार, खिलाऊ उद्योग का विस्तार, स्टार्टअप, अंगदान की महत्ता जैसे तमाम विषय हैं, जिन पर प्रधानमंत्री ने खुलकर चर्चा की और उन पर लोगों का ध्यान भी गया है। जल संरक्षण, त्योहारों पर भारतीय वस्तुओं की खरीद, खादी का कम से कम एक वस्त्र जरूर खरीदने की अपील हो या फिर नवीकरणीय ऊर्जा की बात, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने वाले ऐसे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक दशक में खुलकर चर्चा की है। गत दिनों 'मन की बात' की एक सौ चौदहवीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने 'नारी शक्ति', अमेरिका से वापस आ रही सैकड़ों कलाकृतियों की चर्चा के साथ ही मातृभाषा में शिक्षा की चर्चा की। इसके ठीक पहले के एपिसोड में

उन्होंने प्रतिभाओं की राह में आने वाली बाधाओं में परिवारवाद को भी जिम्मेदार बताया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विषयों के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगते रहे हैं। लोक से शासक का संवाद लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है। इस लिहाज से देखें तो 'मन की बात' इसी संवाद प्रक्रिया का तरीका है, जो रूजवेल्ट के संवाद से कुछ अलग है। रूजवेल्ट ने राजनीति को जबाब के तौर पर फायरसाइड चैट का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी इसके जरिये समाज को ही सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव को लेकर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

## विश्व शांति के लिए खतरा बना ईरान, पश्चिमी एशिया में तनाव की आग और भड़की

इससे पहले इजरायल ने ईरान हमारा चीफ इस्माइल हानिया को भी डेर किया था, लेकिन तब ईरान ने इजरायल पर कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। इस बार लेबनान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोटों के जरिये हजारों हिजबुल्ला आतंकियों के घायल होने और कई के मारे जाने और फिर नसरुल्ला की मौत के बाद ईरान अत्यंत मजबूर दिखने लगा

खोमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी माडल मुस्लिम जनत के सामने पेश किया उससे तुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अरब जगत की तमाम सेक्युलर सरकारें और तानाशाह धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खोते गए और इस्लामिक कट्टरपंथी मजबूत होते गए। जो सुन्नी राजशाहियां इस लहर में बच भी पाईं। दबाव हटाने के लिए दूसरे देशों में सुन्नी जिहादी संगठनों का समर्थन किया। हिजबुल्ला के मुखिया हसन नसरुल्ला की इजरायली हमले में मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव की आग और भड़क गई है। नसरुल्ला की मौत के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला बोला। इजरायल ने इन मिसाइल हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। इससे पहले इजरायल ने ईरान में हमारा चीफ इस्माइल हानिया को भी डेर किया था, लेकिन तब ईरान ने इजरायल पर कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। इस बार लेबनान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोटों के जरिये हजारों हिजबुल्ला आतंकियों के घायल होने और कई के मारे जाने और फिर नसरुल्ला की मौत के बाद ईरान अत्यंत मजबूर दिखने लगा और उसके द्वारा समर्थित विभिन्न आतंकी गुटों के भीतर ही ईरान की इजरायल नीति को लेकर आवाजें उठने लगी थीं। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के चलते आयतुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में बनी कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार ने पूरे पश्चिमी एशिया में आतंकी संगठनों का जाल बिछाया। इस्लामिक जगत का नेतृत्व शिया वर्ग के हाथ में लेने के लिए खोमैनी ने नेतृत्व वाले ईरानी शासनंत्र ने पूरे विश्व के मुस्लिम मानस को प्रभावित करने वाले फलस्तीन के मुद्दे को चुना और इजरायल के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के लिए हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। शिया और सुन्नी इस्लाम के समीकरणों की एक खास बात यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान शिया भी बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम जनत में शिया अल्पसंख्यक हैं। इसलिए खोमैनी के कट्टरमुल्ला तंत्र के लिए यह आवश्यक था कि वह सुन्नी अतिवादियों के भी एक तबके को अपने साथ

ले। चूंकि अधिकांश सुन्नी अतिवादी शिया इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं और आर्थिक रूप से सुन्नी अरब देशों पर निर्भर रहे हैं, इसलिए ईरान के लिए यह चुनाव आसान नहीं था। ऐसे में सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड की फलस्तीन इकाई यानी हमस ईरान का औजार बनो। खोमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी माडल मुस्लिम जनत के सामने पेश किया, उससे तुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अरब जगत की तमाम सेक्युलर सरकारें और तानाशाह धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खोते गए और इस्लामिक कट्टरपंथी मजबूत होते गए। जो सुन्नी राजशाहियां इस लहर में बच भी पाईं, उन्होंने अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए दूसरे देशों में सुन्नी जिहादी संगठनों का समर्थन करना शुरू किया, जिसकी परिणति अलकायदा से लेकर तालिबान जैसे तमाम सुन्नी आतंकी संगठनों के उदय के रूप में हुई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तो खोमैनी के कट्टरमुल्ला शासन का सुन्नी संस्करण ही थी। तालिबान सरकार के 1996 में सत्ता में आने पर उसे तीन देशों से ही मान्यता मिली थी-सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। इनमें से पहले दो देशों का उद्देश्य ईरान से सटे अफगानिस्तान में खोमैनी के शिया इस्लामिक राष्ट्र जैसा ही एक प्रतियोगी सुन्नी शासनतंत्र खड़ा करना था, जिसका प्रमुख भी एक कट्टरपंथी मौलाना हो और जहां सुन्नी कट्टरपंथियों को इकट्ठा रखकर उनकी शक्ति को दूसरे देशों की ओर निर्देशित रखा जा सके। खोमैनी की इस्लामिक क्रांति का एक और प्रभाव यह भी हुआ कि दुनिया भर के अशांत मुस्लिम क्षेत्रों के लोगों को लगा कि हिंसा के माध्यम से सत्ता को पलटा जा सकता है। खोमैनी ने मुस्लिम जगत में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस भावना को खिलवावा भी दी और फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक के मुसलमानों को अपने भाषणों के जरिये उकसाया। ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सुन्नी देशों ने और बड़-बड़कर आतंकी संगठनों की सहायता की। इस प्रकार यह एक दुबकन बन चुका है, जिसके चलते लाखों लोग जान नचा चुके हैं।

मगर हकीकत यह है कि कुछ प्रचारित मामलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया लगता है। वे अब सामूहिक कत्लेआम करने से भी बाज नहीं आ रहे। अमेठी जिले में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या से जाहिर है कि राज्य में संगठित अपराधी हों या अपराधिक मानसिकता वाले लोग, उनके भीतर पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है।

अमेठी जिले में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या से जाहिर है कि राज्य में संगठित अपराधी हों या अपराधिक मानसिकता वाले लोग, उनके भीतर पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने कामयाब शासनकाल के प्रचार में सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में अपराध पर काबू पाने के लिए जो अभियान चलाए गए, उससे वहां अपराधिक मानसिकता वाले खोफ से भरे हुए हैं और अपराध रुक गए हैं। मगर हकीकत यह है कि कुछ प्रचारित मामलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया लगता है। वे अब सामूहिक कत्लेआम करने से भी बाज नहीं आ रहे। अमेठी जिले में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या से जाहिर है कि राज्य में संगठित अपराधी हों या अपराधिक मानसिकता वाले लोग, उनके भीतर पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है। खबर के मुताबिक, हत्या के आरोपी ने रायबरेली से अपनी मोटरसाइकिल से अमेठी पहुंच कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें उसने न केवल दंपति, बल्कि उनके दो छोटे बच्चों को भी लाइसेंस पीतल से गोली मार दी और फरार हो गया। हालांकि

## अमेठी में अपराधियों की हिम्मत के आगे फीकी यूपी पुलिस की सख्ती, योगी सरकार के दावों पर सवाल

इस मामले में एक से अधिक अपराधियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, मगर अपराधियों और अपराध का खाल्टा करने के सरकारी दावे के बरकस यह हत्याकांड क्या दर्शाता है? सवाल है कि सरकार और पुलिस अब जिस सख्ती का दावा कर रही हैं, उसमें ऐसी निरंतरता क्यों नहीं होती, जिससे अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा हो। गौरतलब है कि करीब डेढ़ महीने पहले महिला ने छेड़छाड़, विरोध करने पर पति से मारपीट, जान से मारने की धमकी और जातिसूचक टिप्पणियां करने को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में मुख्य रूप से उसी व्यक्ति के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अब स्वाभाविक ही ये सवाल उठ रहे हैं कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में समय रहते ठोस कार्रवाई की गई होती तो क्या चार लोगों की जान बचाई जा सकती थी? किसी अपराध के आरोपी को मुठभेड़ में मारे जाने की सुविधाएं इस हकीकत का जवाब नहीं हो सकती कि राज्य में आए दिन होने वाली अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी बेखौफ दिखने लगे हैं।

अमेठी जिले में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या से जाहिर है कि राज्य में संगठित अपराधी हों या अपराधिक मानसिकता वाले लोग, उनके भीतर पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने कामयाब शासनकाल के प्रचार में सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में अपराध पर काबू पाने के लिए जो अभियान चलाए गए, उससे वहां अपराधिक मानसिकता वाले खोफ से भरे हुए हैं और अपराध रुक गए हैं। मगर हकीकत यह है कि कुछ प्रचारित मामलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया लगता है। वे अब सामूहिक कत्लेआम करने से भी बाज नहीं आ रहे। अमेठी जिले में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या से जाहिर है कि राज्य में संगठित अपराधी हों या अपराधिक मानसिकता वाले लोग, उनके भीतर पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है। खबर के मुताबिक, हत्या के आरोपी ने रायबरेली से अपनी मोटरसाइकिल से अमेठी पहुंच कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें उसने न केवल दंपति, बल्कि उनके दो छोटे बच्चों को भी लाइसेंस पीतल से गोली मार दी और फरार हो गया। हालांकि

इस मामले में एक से अधिक अपराधियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, मगर अपराधियों और अपराध का खाल्टा करने के सरकारी दावे के बरकस यह हत्याकांड क्या दर्शाता है? सवाल है कि सरकार और पुलिस अब जिस सख्ती का दावा कर रही हैं, उसमें ऐसी निरंतरता क्यों नहीं होती, जिससे अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा हो। गौरतलब है कि करीब डेढ़ महीने पहले महिला ने छेड़छाड़, विरोध करने पर पति से मारपीट, जान से मारने की धमकी और जातिसूचक टिप्पणियां करने को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में मुख्य रूप से उसी व्यक्ति के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अब स्वाभाविक ही ये सवाल उठ रहे हैं कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में समय रहते ठोस कार्रवाई की गई होती तो क्या चार लोगों की जान बचाई जा सकती थी? किसी अपराध के आरोपी को मुठभेड़ में मारे जाने की सुविधाएं इस हकीकत का जवाब नहीं हो सकती कि राज्य में आए दिन होने वाली अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी बेखौफ दिखने लगे हैं।



संपादकीय

## सिद्धारमैया : इस्तीफे पर दोहरे मापदंड

मुझ जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा पद से इस्तीफा न देने का खुला ऐलान और दूसरे राज्यों में आरोपों में घिरे मुख्यसमंत्रियों से त्यागपत्र मांगने वाली कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस का सिद्धारमैया के बचाव से जाहिर है कि नैतिकता के संदर्भ में सभी राजनीतिक दलों के दोहरे मानदंड हैं। मसलन अगर विपक्षी पार्टी के सीएम पर आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी जाती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगे तो उसे बचाने की हरसंभव कोशिश की जाती है। सिद्धारमैया के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि जब 'आप' और 'बीजेपी' के मुख्यसमंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद नहीं छोड़ा तो सिद्धारमैया को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? कांग्रेस इसे भाजपा की चाल बता रही है। उभर अपने बचाव में सिद्धारमैया ने कहा कि मुझ पर मुझ लैंड स्केम में मुझ पर धन शोधन (मनी लाँड्रिंग) का आरोप लगाया गया है। यह मामला धन शोधन का किस आधार पर बनता है, यह मुझे नहीं पता। उन्होंने इस मामले में इंडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। दरअसल इंडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। इसे लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में पीएमएलए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्योंकि मुझ द्वारा जो जमीन जो ली गई है, उसके बदले मेरी पत्नी को भूखंड दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (इंडी) ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंडों को आवंटन करने की प्रक्रिया में कथित तौर पर अनियमितताओं को लेकर केस तथा सीएम और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी ने एमयूडीए को पत्र लिखकर 14 भूखंडों पर स्वामित्व पर कब्जा छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनके पति के सम्मान, प्रतिष्ठ, गरिमा और मानसिकता से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता झूठ बोलने में विश्वगुरु हैं। इसी संदर्भ में सिद्धारमैया ने सवाल किया कि क्या मेरे इस्तीफा देने के बाद यह मामला बंद हो जाएगा? केन्द्र की भाजपा सरकार की चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर ही जवाब दिया जाएगा। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस हाई कमान ने इस निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने विरोधियों द्वारा अपनाए जा रहे मोडलों का ही सहारा लिया है। कांग्रेस हाई कमान को लगता है कि यदि सिद्धारमैया के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो इसे भाजपा अपनी जीत के तौर पर पेश करेगी। वैसे सिद्धारमैया प्रकरण के पीछे कांग्रेस की अदरूनी खींचतान भी एक कारण है। पिछले साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उभ मुख्य मंत्री डी. के. शिवकुमार सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। कांग्रेस को बोकलगा वाट दिलवाने में उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें यह कहकर सीएम नहीं बनाया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे ओबीसी कुरुबा समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया की दूसरी बार लांटी लगी। कांग्रेस का एक खेमा राज्य में एएसपी/एसटी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। जिस पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर सिद्धारमैया को पार्टी ऐसे ही बचाती रही तो कांग्रेस भी भीतरी अस्थिरता बढ़ेगा। सवाल उठने लगा है कि जब डीके शिवकुमार पर जो नियम लागू हुआ, वो सिद्धारमैया पर लागू क्यों नहीं। उसी तरह जो भाजपा आज सिद्धार से इस्तीफा मांग रही है, वह अपने ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर नामी पहलवानों के यौन शोषण के मामले में चुपों साथे रही। अब वो सिद्धार से किस मुंह से इस्तीफा मांग रही है।

## पहल एक पेड़ मां के नाम का असर

10 पेड़ मां के नाम जिसमें पांच पेड़ आयुर्वेदिक पेड़ सम्मिलित किये गए, ऐसा सबकी अन्तश्चेतना का विषय बन गया तो यह देश जो वन क्षेत्र खो चुका है, उसकी भरपाई कर लेगा। यह देश हरित देश बन जाएगा। यह देश शुद्ध आक्सीजन और शुद्ध हवा से हमारे देश की बीमारियों को दूर करेगा। सबके लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण से भर देगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहज ही यह सब करते हैं। उनके स्वाभाव से ऐसी बातें

### प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

भारत बदल रहा है। सोच से बदल रहा है। संवेदना से बदल रहा है। विचार से बदल रहा है और प्रकृति से बदलाव के लिए प्रयत्नशील है भारत, ऐसा अब देखने को मिल रहा है। 80 करोड़ पौधे रोपे गए हैं देश में। एक पेड़ मां के नाम, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतःकरण से निकले अपनी भावना के रूप में प्रकट किया था। उन्होंने तो केवल 'एक पेड़ मां के नाम' कहा था। वह एक-एक कि भवना बन गया अब इस 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में यह नारा अभियान बन गया। सबने पेड़ लगाये। सबने प्रकृति में पानी सींचा। सबने प्रकृति के लिए अपना अवदान दिया।

यदि आने वाले समय में यह विषय 10 पेड़ मां के नाम जिसमें पांच पेड़ आयुर्वेदिक पेड़ सम्मिलित किये गए, ऐसा सबकी अन्तश्चेतना का विषय बन गया तो यह देश जो वन क्षेत्र खो चुका है, उसकी भरपाई कर लेगा। यह देश हरित देश बन जाएगा। यह देश शुद्ध आक्सीजन और शुद्ध हवा से हमारे देश की बीमारियों को दूर करेगा। सबके लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण से भर देगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहज ही यह सब करते हैं। उनके स्वाभाव से ऐसी बातें निकल जाती हैं। जब व्यक्ति समष्टि का हो जाता है तो ऐसा होता है। 5 जून, 2024 वैसा ही विश्व पर्यावरण दिवस था जैसा हर वर्ष आता है और इसे मना लिया जाता है। लेकिन इस साल दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया तो उन्होंने कहा 'एक पेड़ मां के नाम'। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया वह एक अभियान की शुरुआत का स्वरूप ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अभियान देश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने के साथ-साथ माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्पन्न भाव दर्शाने की एक अनूठी पहल है।

सतत विकास का इससे अच्छी पहल हो ही नहीं सकती थी। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान भारत की स्थायी और पर्यावरण के प्रति



जागरूक भविष्य के लिए प्रतिबद्धता है। पर्यावरण संरक्षण के आह्वान और माताओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ यह पहल नागरिकों को एक हरित पृथ्वी बनाने में अपना योगदान देने का सुअवसर है। इस अभियान की सफलता पूरे देश में लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की भावना है। यह अभियान न सिर्फ प्रकृति, जीवन-जंतु एवं मातृत्व की पोषण शक्ति के सम्मान का प्रतीक बन गया है, अपितु भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्थायी दुनिया का आश्वासन भी देता है।

80 करोड़ पौधा रोप दिए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मांओं तो सितंबर 2024 तक 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगा गए। निःसंदेह यह उपलब्धि सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों के सहयोग और प्रयासों का परिणाम है, लेकिन पहल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि हितधारकों में इसकेवल अपनी आचारिकता पूर्ण के लिए यह 80 करोड़ पौधे लगा दिया है, ऐसा नहीं है अपितु इसे व्यापक मिशन बना दिया और इसके विश्व रिकॉर्ड भी बन गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रादेशिक सेना की 128 इन्फैंट्री बटालियन और पारिस्थितिकी कार्य बल इकाई ने सिर्फ एक घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की तो वहीं एक

सकेगा। इस मायने में भी प्रधानमंत्री का एक वाक्य देश हित में हमारा मां बढ़ाने वाला बन गया है।

यह एक हरित भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण वाला नारा बन गया एक पेड़ मां के नाम। यह एक कल्पना के रूप में सम्मान बढ़ाने वाला विषय बन गया एक पेड़ मां के नाम। भारत में पेड़ों को लेकर किये गए आंदोलनों का अपना इतिहास है। उसकी अपनी पृष्ठभूमि है। महाराष्ट्र के मोहन धरिया को प्रकृति पुत्र कहा जाता था। सुन्दरलाल बहुगुणा को भी पेड़ों के लिए जाना जाता है। गौर देवी और चंडी भद्र को भी पेड़ के रखवाले के रूप में जाना जाता है। ऐसे लोग पृथ्वी के लिए वरदान होते हैं। आज अब एक पेड़ मां के नाम से निकली एक लहर जब देश में 80 करोड़ पेड़ों को रोपकर जनमुहिम में बदल चुकी है तो नरेंद्र मोदी का नाम भी आदर्श अध्यायों में अंकित हो रहा है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है। सम्पूर्ण विश्व में लड़ी जा रही है। भारत भी लड़ रहा है। लेकिन केवल यह लड़ाई हमारे भाषणों में ही और जमीनी स्तर पर न हो तो हमारे लिए यह एक भरम की स्थिति होती है कि हम मानें तो क्या मानें। लेकिन एक पेड़ मां के नाम तो जमीनी कार्य है। इस कार्य को अब सभी जानते हैं। देश में सबने पेड़ लगाया। देश में सबने पेड़ से अपनी पीढ़ी को बचाने में अपना योगदान दिया। इस मुहिम से 80 करोड़ पेड़ इसके गवाह हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि पेड़ों को लगे हैं, वे जी जायें। वे बचे रहें। वह प्रकृति में अपने हिस्से का आक्सीजन दें और इस पर्यावरणीय संतुलन को हासिल करने में मदद करें। यदि पेड़ न जिए तो इसमें उनकी गलती नहीं इसलिए पेड़ के लिए इंसानों को अपना कर्तव्य निरवाहन करना है और बाद में जो पेड़पूरी पृथ्वी को देंगे उसका आज भले अंदाजा न हो लेकिन आने वाले 50 से 500 साल तक उनसे जो मिलेगा उसे पीढ़ियां महसूस करेंगी। भारत में इस मुहिम की निरंतरता भी इसलिए आवश्यक है, इससे फायदा देश को ही होगा चाहे आज की पीढ़ी माने या न माने। सम्पूर्णता में देखें तो एक पेड़ मां के नाम की मुहिम से नरेंद्र मोदी ने निःसंदेह भारत का भला किया है, यह एक सम्पूर्ण सत्य है।

अध्यात्म

### राजा का मूर्ति प्रेम

एक राजा था जिसने शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देस-परदेस जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियाँ अपने राज महल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देख रेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें तीन मूर्तियाँ जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरन्त मृत्युदण्ड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरन्त अन्य दो मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देख कर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा, तब उस सेवक ने कहा - महाराज !! क्षमा कीजियेगा, यह मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं। अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है इसलिए मैंने ही अन्य दो मूर्तियों को तोड़कर उन दो व्यक्तियों की जान बचा ली यह सुनकर राजा की आँख खुली तो सबके मन में सम्मान बढ़ाने वाला विषय बन गया एक पेड़ मां के नाम। भारत में पेड़ों को लेकर किये गए आंदोलनों का अपना इतिहास है। उसकी अपनी पृष्ठभूमि है। महाराष्ट्र के मोहन धरिया को प्रकृति पुत्र कहा जाता था। सुन्दरलाल बहुगुणा को भी पेड़ों के लिए जाना जाता है। गौर देवी और चंडी भद्र को भी पेड़ के रखवाले के रूप में जाना जाता है। ऐसे लोग पृथ्वी के लिए वरदान होते हैं। आज अब एक पेड़ मां के नाम से निकली एक लहर जब देश में 80 करोड़ पेड़ों को रोपकर जनमुहिम में बदल चुकी है तो नरेंद्र मोदी का नाम भी आदर्श अध्यायों में अंकित हो रहा है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है। सम्पूर्ण विश्व में लड़ी जा रही है। भारत भी लड़ रहा है। लेकिन केवल यह लड़ाई हमारे भाषणों में ही और जमीनी स्तर पर न हो तो हमारे लिए यह एक भरम की स्थिति होती है कि हम मानें तो क्या मानें। लेकिन एक पेड़ मां के नाम तो जमीनी कार्य है। इस कार्य को अब सभी जानते हैं। देश में सबने पेड़ लगाया। देश में सबने पेड़ से अपनी पीढ़ी को बचाने में अपना योगदान दिया। इस मुहिम से 80 करोड़ पेड़ इसके गवाह हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि पेड़ों को लगे हैं, वे जी जायें। वे बचे रहें। वह प्रकृति में अपने हिस्से का आक्सीजन दें और इस पर्यावरणीय संतुलन को हासिल करने में मदद करें। यदि पेड़ न जिए तो इसमें उनकी गलती नहीं इसलिए पेड़ के लिए इंसानों को अपना कर्तव्य निरवाहन करना है और बाद में जो पेड़पूरी पृथ्वी को देंगे उसका आज भले अंदाजा न हो लेकिन आने वाले 50 से 500 साल तक उनसे जो मिलेगा उसे पीढ़ियां महसूस करेंगी। भारत में इस मुहिम की निरंतरता भी इसलिए आवश्यक है, इससे फायदा देश को ही होगा चाहे आज की पीढ़ी माने या न माने। सम्पूर्णता में देखें तो एक पेड़ मां के नाम की मुहिम से नरेंद्र मोदी ने निःसंदेह भारत का भला किया है, यह एक सम्पूर्ण सत्य है।

## दीर्घ जीवन एक दीर्घ अभिशाप न बन जाए

### ललित गर्ग

वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, उसकी आँखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलानी होगी। सुधार की संभावना हर समय है।

वृद्ध व्यक्तियों को सुखद एवं खुशहाल जीवन प्रदत्त करने के लिये हमें सर्वप्रथम तो उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने पर ध्यान देना होगा। बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से आवश्यक रूप से और सहज रूप में मिल सकने वाली पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, उनके लिए समाज को कम परिश्रम वाले हल्के-फुल्के रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्धों के कल्याण के कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, जो उनमें जीवन के प्रति उसाह उत्पन्न करें। अधिकांश युवाओं की सोच इस रूप में पुख्ता हो जाती है कि संयुक्त परिवार व्यक्तित्व उन्नति में बाधक होते हैं। चीजों की ललक में स्वहित रितने हाजी हो जाते हैं कि संवेदनहीनता मानवीय रिश्तों की महक को क्षण में काफूर कर देती है और तल्हा बुढ़ापा घुटनभरी संसों के साथ जीने को बाध्य हो जाता है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूँ ही नजरअंदाज किया

जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएँगे, जो इन लोगों के पास है। वृद्ध दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उन्हें परिवार में सम्मानजनक जीवन देंगे, उनके शुभ एवं मंगल की कामना करेंगे।

आज का वृद्ध समाज-परिवार से कटा रहता है और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुःखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को महत्व देता है। समाज में अपनी एक तरह से अहमित्य न समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज दुःखी, उपेक्षित एवं त्रासद जीवन जीने को विवश है। वृद्ध समाज को इस दुःख और कष्ट से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम बुजुर्गों एवं वृद्धों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के साथ-साथ समाज में उनके उचित स्थान देने की कोशिश करें ताकि उम्र के उस पड़ाव पर जब उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो जिंदगी का पूरा आनंद ले सके। वृद्धों को भी अपने स्वयं के प्रति जागरूक होना होगा, जैसाकि जेम्स गार्फिल्ड ने कहा भी है कि यदि वृद्धावस्था की झुर्रियाँ पड़ती हैं तो उन्हें हृदय पर मत पड़ने दो। कभी भी आत्मा को वृद्ध मत होने दो।

प्रश्न है कि आज हमारा वृद्ध समाज इतना कुटित एवं उपेक्षित क्यों है? अपने को समाज में एक तरह से निष्प्रायोज्य समझे जाने के कारण वह

सर्वाधिक दुःखी रहता है। वृद्ध समाज को इस दुःख और त्रास से छुटकारा दिलाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की बहुत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाने का निर्णय लिया। वृद्धों की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वप्रथम अर्जेंटीना ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। तब से लेकर अब तक वृद्धों के संबंध में अनेक गोष्ठियाँ और अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। वर्ष 1999 को अंतराष्ट्रीय बुजुर्ग-वर्ष के रूप में भी मनाया गया। इससे पूर्व 1982 में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' ने 'वृद्धावस्था को सुखी बनाइए' जैसा नारा दिया और 'सबके लिए स्वास्थ्य' का अभियान प्रारम्भ किया गया।

एक पेड़ जितना ज्यादा बढ़े होता है, वह उतना ही अधिक झुका हुआ होता है यानि वह उतना ही विमन्न और दूसरों को फल देने वाला होता है, यही बात समाज के उस वर्ग के साथ भी लागू होती है, जिसे आज की तथाकथित युवा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी बूढ़ा कहरक वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। आदमी जीवनमूल्यों को खोकर आखिर कब तक धैर्य रखेगा और क्यों रखेगा जब जीवन के आसपास सबकुछ बिखरता हो, खोता हो, मिटता हो और संवेदनाशून्य होता हो। आज के समाज में मध्यम वर्ग में भी वृद्धों के प्रति स्नेह की भावना कम हो गई है। डिजरायली का मार्मिक

कथन है कि यौवन एक भूल है, पूर्ण मृत्युव्यव एक संघर्ष और वार्धक्य एक पश्चाताप। वृद्ध जीवन को पश्चाताप का पर्याय न बनने दे।

वृद्धावस्था जीवन का अनिवार्य सत्य है। जो आज युवा है, वह कल बूढ़ा भी होगा ही, लेकिन समस्या की शुरुआत तब होती है, जब युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को उपेक्षा की निगाह से देखने लगती है और उन्हें अपने बुढ़ापे और अकेलेपन में बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, कटुक्तियाँ, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर-उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता।

वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुईं, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय उद्योगवादी बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। इसीलिये सिसरो ने कामना करते हुए कहा था कि जैसे मैं वृद्धावस्था के कुछ गुणों को अपने अन्दर समाविष्ट रखने वाला युवक को चाहता हूँ, उतनी ही प्रसन्नता मुझे युवाकाल के गुणों से युक्त वृद्ध को देखकर भी होती है, जो इस नियम का पालन करता है, शरीर से भले वृद्ध हो जाए, किन्तु दिमाग से कभी वृद्ध नहीं हो सकता। वृद्ध लोगों

के लिये यह जरूरी है कि वे वार्धक्य को ओढ़े नहीं, बल्कि जीएँ।

बड़े शहरों में परिवार से उपेक्षित होने पर बूढ़े-बुजुर्गों को 'ओल्ड होम्स' में शरण मिल भी जाती है, पर छोटे अल्डों और गाँवों में तो टुकड़ाने, तरसाने, सलाए जाने पर भी आजीवन चुट-चुट कर जीने की मजबूरी होती है। यद्यपि 'ओल्ड होम्स' की स्थिति भी ठीक नहीं है। पहले जहाँ वृद्धाश्रम में सेवा-भाव प्रथा थी, पर आज व्यावसायिकता की चोट में यहाँ अमीरों को ही प्रवेश मिल पा रहा है।

ऐसे में मध्यमवर्गीय परिवार के वृद्धों के लिए जीवन का उत्तरार्ध पहाड़ बन जाता है। विक्रम बहुओं के ताने, बच्चों को टहलाने-धुमाने की जिम्मेदारी की फिक्र में प्रायः जहाँ पुरुष वृद्धों की सुबह-शाम खप जाती है, वहीं महिला वृद्ध एक नौकरानी से अधिक हैसियत नहीं रखती। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराए रहे हैं, भरण-पोषण को तस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। पर कौन सोचता है, किसे फर्सत है, वृद्धों की फिक्र किसे है? भौतिक जिंदगी की भाग्यदौड़ में नई पीढ़ी नए-नए मुकाम दूढ़ने में लगी है, आज वृद्धजन अपने से दूर जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर कवीन्द्र-रवीन्द्र की पंक्तियाँ गुनगुनाने को क्यों विवश है- 'दीर्घ जीवन एकटा दीर्घ अभिशाप', दीर्घ जीवन एक दीर्घ अभिशाप है।

### आज का कार्टून



### मेष

जीवनसाथी को आप उपहार दे सकते हैं। सन्तान के व्यवहार से आपका मन गदगद हो जायेगा। घर का वातावरण काफी सुखद रहने वाला है।

### वृषभ

दूसरों की नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। आपका मन अशांत हो सकता है। सिरदर्द और माइग्रेन के रोगियों के लिये दिन शुभ नहीं है।

### मिथुन

कार्यक्षेत्र में आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में फँसे रहेंगे। जीवनसाथी के साथ आपके सम्बन्ध मधुर होंगे। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर एकाग्र रहेंगे।

### कर्क

कार्यक्षेत्र में दुविधापूर्ण स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखदायक रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

### सिंह

सम्पत्ति के क्रय-विक्रय से धन लाभ होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में आप निवेश कर सकते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षित रहेंगे। मन में कामुक विचार पनपते रहेंगे।

### कन्या

आपका मनोबल थोड़ा कमजोर हो सकता है। असंयमित भोजन के कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। शत्रु आपको नुकसान पहुँचाना चाहेंगे।

### शिशुफल

### तुला

व्यापार में नये अनुभव होने के योग बन रहे हैं। परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। आपके जनसम्पर्क में वृद्धि होगी। आपकी कार्यगणाली में सुधार होगा।

### वृश्चिक

कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। लोग स्वार्थवश आपसे सम्पर्क में रहना चाहेंगे। नया रोजगार शुरू कर सकते हैं।

### धनु

आपके कार्य अपेक्षाकृत देरी से पूरे होंगे। आप की उपलब्धियों से आपके सौमित्रों काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। बच्चों की शिक्षा को लेकर आप काफ़ी ध्यान देंगे। दाम्पत्य सम्बन्ध काफ़ी प्रगाढ़ रहने वाले हैं।

### मकर

आज आपको काफ़ी व्यस्त रहना पड़ेगा। किसी भी काम में ज्यादा मन नहीं लगा पायेंगे। अनजान लोगों पर ज्यादा विश्वास न करें। वर्तमान वातावरण को लेकर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए।

### कुंभ

अपनी बौद्धिक क्षमता का कुशल प्रयोग कर पायेंगे। आलस्य से आपको बचना चाहिए। मन में परोपकार की भावना रहेगी। यात्रा करने के योग बन रहे हैं।

### मीन

सरकारी कार्यों के लिये दिन बहुत शुभ है। अति महत्वपूर्ण कार्यों को आप समय पर पूरा करेंगे। परिवार में किसी कारण अशांति हो सकती है।

# राजनीति से मुक्त हों विज्ञान पुरस्कार

दिनेश सी. शर्मा

एक साहसिक और विरला कदम उठाते हुए, 175 वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने देश में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान झ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार झ के राजनीतिकरण पर निराशा व्यक्त की है। इस पुरस्कार की स्थापना पिछले साल केंद्र सरकार ने की थी। कुछ सप्ताह पहले, प्रथम पारितोषिक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाने के तुरंत बाद चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप की सुगंधाहट शुरू हो गई थी। हुआ यह कि चयन समिति द्वारा भेजे गए तीन वैज्ञानिकों के नाम पुरस्कार विजेताओं की अंतिम सूची से गायब थे। जबकि समिति के कुछ सदस्यों ने अनौपचारिक रूप से उन्हें यह खबर बता दी थी। लेकिन बाद में उनको करारा झटका लगा। आशंका जताई गई कि उक्त विचारार्थीन वैज्ञानिकों को उनके राजनीतिक विचारों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके रुख के कारण राष्ट्रीय सम्मान से वंचित किया गया।

24 सितंबर को पीएएस को लिखे पत्र में कहा : सरकार ने चयन मानदंडों में किया गया बदलाव अपने पोर्टल पर दर्शाया है और पुरस्कार समारोह से महज चंद्र दिन पहले अपलोड किए गए नए प्रारूप में एक नई लाइन जोड़ी गई है कि अब आपकी अध्यक्षता वाली चयन समिति अपनी सिफारिशें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रों को सौंपेगी। चयन प्रक्रिया में किया गया यह बदलाव राजनेताओं द्वारा चयन समिति का निर्णय खारिज करने या बदलने का मार्ग प्रशस्त करता है। झजबकि यह समिति व्यावहारिक रूप से भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। समिति में वैज्ञानिक अकादमियों के अध्यक्षों के अलावा वैज्ञानिक विभागों के सचिव भी सदस्य हैं। वैज्ञानिक समुदाय को इसका आभास पहले ही हो गया था। स्वंत्रप्रथम तो गृह मंत्रालय द्वारा समूचे वैज्ञानिक विभागों की बागडोर अपने हाथ में लेना और दर्जनों पुरस्कारों को समाप्त करना बेतुका था, जिसमें 1950 के दशक में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनगर पुरस्कार और अन्य स्वायत्त विज्ञान अकादमियों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल थे। श्रेष्ठ वैज्ञानिक कार्य को मान्यता देने को स्थापित किए गए पुरस्कारों और निष्पक्ष तरीकों को समाप्त करना तथा उनकी जगह एक नया सरकारी पुरस्कार शुरू करना,



जिसमें कोई नकद राशि नहीं है, एक कठोर झटका है। तिस पर, नई पुरस्कार प्रक्रिया विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है। अंतिम निर्णय एक राजनीतिक पदार्थिकारी पर छोड़ने का मतलब है कि पुरस्कार विजेताओं के चयन में गैर-शैक्षणिक विचारों की भूमिका रहेगी। पुरस्कारों से इतर, यह प्रसंग भारत में अकादमिक स्वतंत्रता और विज्ञान क्षेत्र के परिचालन के बारे में अहम सवाल उठाता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर पुरस्कार प्रकरण को भारतीय विज्ञान के लिए एक अस्वस्थ घटना ठहराकर सही किया है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि यह होने पर मंत्रियों द्वारा

अबाध वीटो का उपयोग करते हुए विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को दफनाकर देने वाला चलन कायम हो जाएगा। पत्र में यह आशंका भी जताई गई है कि सरकार को न सुनाने वाले शिक्षाविदों को न केवल पुरस्कारों से बल्कि वैज्ञानिक अनुदान, भर्ती, पदोन्नति आदि से भी महारूम रखा जा सकता है। यह वैज्ञानिक कार्य पद्धति के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि विज्ञान को किसी शाखा विशेष में एक वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त

विशिष्ट उपलब्धि को मान्यता देने में निष्पक्षता बनी रहेगी। आमतौर पर यह काम समकक्षों द्वारा की गई समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार झ जिसे अब बंद किया जा चुका है झ वह सर्वोच्च सम्मान था जोकि भारतीय विज्ञान जगत की विविध धाराओं में सबसे बढ़िया कर दिखाने वाले को पारितोषिक मान्यता प्रदान करता था। पुरस्कार विजेताओं की इस सूची का मतलब है- पिछले कई दशकों में भारत के चोटी के साईंसदान जिन्हें यह पुरस्कार मिला, उन्होंने आगे चलकर अपने-अपने संस्थान का नेतृत्व किया, नए संस्थान स्थापित किए, फंड देने वाली एजेंसियों और विज्ञान विभागों की अगुवाई भी की। यदि अपनी स्थापना के पहले ही साल में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की चयन प्रक्रिया पर इस प्रकार सवाल खड़े हो गये तो क्या वह लंबे तक कायम रही भटनागर पुरस्कार की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा।

यह प्रकरण पिछले कुछ वर्षों में पीएएस की भूमिका में निरंतर क्षरण को भी उजागर करता है। भले ही इस पद का सुजन 1999 में हुआ हो, लेकिन आजादी के बाद से ही भारत में विज्ञान संबंधी नीतियों पर परामर्श देने के लिए एक तंत्र रहा है, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में वैज्ञानिक कार्य के समन्वय के लिए राष्ट्रीय समिति बनाने से हुई थी। आगे चलकर, सरकार, मंत्रिमंडल और प्रधान मंत्री के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समितियां बनीं। इस परामर्श तंत्र के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक विभागों की स्थापना और पुनर्गठन, नए विज्ञान मंत्रालयों का निर्माण, अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक निचयों के साथ-साथ कई राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का विकास हुआ। एक स्वतंत्र विज्ञान परामर्श प्रणाली ने विज्ञान और नीति के बीच समन्वय और नए विचारों के समावेशन गृह के रूप में कार्य किया है। पीएएस की भूमिका में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामलों के साथ-साथ सामान्य रूप से विज्ञान-आधारित नीति समाधानों पर सलाह देना शामिल है। दोनों ही मामलों में, नीति निर्माण में विज्ञान समुदाय का मार्गदर्शन साथ रखना चाहिए। नीति निमाताओं का काम विज्ञान अनुदान और पुरस्कार से संबंधित मामलों को देखना नहीं है। यह पीएएस पर निर्भर है कि वह किस हद तक वह संतुलन साध सकता है। लेकिन, हाल के वर्षों में पीएएस के कामकाज की भूमिका को वैज्ञानिक विभागों के बीच समन्वय बनाने तक सीमित कर दिया गया है और किसी अन्य सरकारी एजेंसी की भांति काम सौंपा गया है। मसलन, हवाई अड्डों पर विविध डैशबोर्ड तैयार करना या प्रचार विज्ञानिक की व्यवस्था करना क्या पीएएस का काम है? उसे प्रौद्योगिकी और तकनीकी उत्पादों की क्रय-निविदाओं की जांच करने जैसे प्रशासनिक कार्य भी सौंप रखे हैं, यह 1960 और 1970 के दशक के लाइसेंस राज की याद दिलाता है, जब इसके चरम पर प्रौद्योगिकी विकास के महानिदेशक का काम कुछ ऐसा ही था। पीएएस पर जो एक अन्य जिम्मेदारी लाद रखी है वह है सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की डिजिटल सूची बनाना और ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए एक ई-मार्केट प्लेस बनाना ताकि सरकारी संयंत्र और निजी क्षेत्र को उनकी खरीद की सहुलियत हो। इस कार्य के रूटीन के काम अन्य एजेंसियों और विभागों द्वारा भी बखूबी संभाले जा सकते हैं। पीएएस कार्यालय को ऐसे कार्य सौंपने से सरकार को विज्ञान पर स्वतंत्र और स्वायत्त सलाह प्रदान करने के उसके प्राथमिक कार्य का क्षरण होता है।

# जेल में जातीय जहर जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता का अतिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में जेलों में जातिगत भेदभाव के साथ श्रम विभाजन पर रोक लगाने के लिये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत प्रभाव से जेल मैनुअल में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 15 का सरासर उल्लंघन बतलाया है। कोर्ट ने कहा कि रसोई व सफाई का काम जाति के आधार पर बांटा जाना अनुचित है। दरअसल, एक महिला पत्रकार द्वारा दायर जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जेल नियमावली जाति के आधार पर कामों के बंटवारे में भेदभाव करती है। खाना बनाने का काम ऊंची जाति के लोगों को देना व सफाई का काम निचली जातियों के कैदियों को देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। जो जेलों में जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है। कोर्ट का कहना था कि जाति के आधार पर कामों का बंटवारा औपनिवेशिक सोच का पर्यय है, जिसे स्वतंत्र भारत में जारी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है जेल नियमावली साफ तौर पर भेदभाव करती है। साथ ही कहा कि नियमावली में जाति से जुड़ी डिटेल्स का उल्लेख असंवैधानिक है। कोर्ट ने खरी-खरी सुनाते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जेल मैनुअल में तुरंत बदलाव करने को कहा है। साथ ही राज्यों को इस फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेच में जस्टिस जेजी पारीदवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। दरअसल एक पत्रकार सुक्रन्या शांता ने सबसे पहले यह मामला उठाया था। उनका कहना था कि देश के 17 राज्यों की जेलों में कैदियों के साथ यह भेदभाव हो रहा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीन महीनों में नियमों में बदलाव करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। छह महीने के भीतर केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि पत्रकार सुक्रन्या ने वर्ष 2020 में एक शोध रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें तीन मुख्य राज्यों का उदाहरण दिया गया था। जिसमें राजस्थान का उल्लेख किया गया था कि यदि कैदी नाई है तो उसे बाल व दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा, ब्राह्मण कैदी को खाना बनाने का काम मिलेगा और वार्ल्सिक कैदी को सफाई का काम दिया जाता था।

डॉ. रिपुदमन गुलाटी

डिजिटल युग के आगमन ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का युग शुरू किया है, जिससे हमारे रहने, काम करने और बातचीत करने के तरीके बदल गए हैं। जबकि ये नवाचार कई लाभ लाए हैं, इन्होंने गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के क्षरण के बारे में भी गंभीर चिंताएं उठाई हैं। लेकिन निगरानी का बढ़ता सिलसिला हमारी आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। निगरानी, जो कभी केवल कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित थी, ने अब ऑनलाइन व्यवहार की ट्रैकिंग करने से लेकर भौतिक आंदोलनों की निगरानी तक कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है। सरकारें, कॉर्पोरेट और यहां तक कि व्यक्ति अब हमारे जीवन के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र कर सकते हैं, जिससे हमारे गोपनीयता के अधिकार की सीमा और दुर्भावना की संभावना के बारे में प्रश्न उठते हैं। निगरानी कैमरे अब सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और स्टोरों से लेकर सड़कों के भीतर तक में आम हो गए हैं। निःसंदेह, ये कैमरे अपराध को रोक सकते हैं और जांच में सहायता कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों की निगरानी किस हद तक की जानी चाहिए, इसके बारे में भी प्रश्न उठते हैं। चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है, जिससे अधिकारियों को वास्तविक समय में व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम बनाया गया है। जबकि यह तकनीक कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकती है, इसने इसके दुरुपयोग की आशंका को भी बढ़ाया है। अध्ययन से पता चला है कि चेहरे की पहचान के एल्गोरिदम कुछ जनसांख्यिकी के खिलाफ प्रक्षपाती हो



सकते हैं, विशेष रूप से रंग के लोगों के खिलाफ। यह पूर्वाग्रह भेदभावपूर्ण परिणामों में ले जा सकता है, जैसे गलत गिरफ्तारी या निरोध। सार्वजनिक स्थानों में चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी और गोपनीयता के क्षरण के बारे में चिंताएं उठाता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि निगरानी कैमरों का प्रसार एक पैनोप्टिकन प्रभाव पैदा करता है, जहां व्यक्ति लगातार देखा जाना और निगरानी महसूस करते हैं, जिससे अभिव्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। निगरानी फुटजेंट का भंडारण और प्रतिधारण डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं उठाता है। पैनोप्टिकन प्रभाव एक सामाजिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि जब लोग लगातार निगरानी में महसूस करते हैं, तो वे अपने व्यवहार को बदलने और अधिक अनुपालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह शब्द जेरीमी बेंथम द्वारा डिजाइन किए गए एक कार्यात्मक जेल से लिया गया है, जहां एक केंद्रीय गार्ड टॉवर से सभी

कैदियों को देख सकता था, जबकि कैदियों को यह नहीं पता था कि वे देखे जा रहे हैं या नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार, जब लोग सोचते हैं कि वे निगरानी में हैं, तो वे अपने व्यवहार को समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए दबाव महसूस करते हैं। यह प्रभाव सत्ता के एक नये रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह लोगों को नियंत्रित करने और उनके व्यवहार को बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। निगरानी के लाभ निर्बंधवाद हैं। इसने अपराध, आतंकवाद और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगरानी प्रणालियों ने अपराधियों की पहचान करने, हमलों को रोकने और बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करने में मदद की है। इसके अलावा, उन्होंने ट्रैफिक प्रवाह में सुधार, संसाधन आवंटन का अनुकूलन और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है। हालांकि, निगरानी के संभावित नुकसान भी उठते ही घातक हैं। व्यक्तिगत डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रह रखना, मुक्त भाषण, संगति और अस्तोच पर एक

गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह एक निगरानी समाज भी बना सकता है जहां व्यक्ति लगातार निगरानी महसूस करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता में प्रतिबंधित महसूस करते हैं। इसके अलावा, निगरानी का उपयोग भेदभावपूर्ण या दमनकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से हाशिए के समूहों के खिलाफ। हाल के वर्षों में निगरानी के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन रहा है। इन कार्यक्रमों में फोन कॉल, ईमेल और इंटरनेट खोज जैसे व्यक्तिगत डेटा का व्यापक संग्रह और विश्लेषण शामिल है। जबकि समर्थक तर्क देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा भी है। निगरानी के लाभों और हानियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, स्पष्ट और लागू होने योग्य गोपनीयता कानून स्थापित करना आवश्यक है। इन कानूनों को निगरानी की सीमाओं को परिभाषित करना चाहिए, व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा का संग्रह और उपयोग नैतिक रूप से किया जाता है। सरकारों को भी अपनी निगरानी गतिविधियों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग और निरंकुशता को रोकने के लिए निरीक्षण के अभाव होना चाहिए। कानूनी ढांचे के अलावा, गोपनीयता जागरूकता और शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को अपने अधिकारों को समझने और अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त होना चाहिए। इसमें अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सचेत रहना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में सावधान रहना शामिल है। निःसंदेह, निगरानी के युग में जीवन और स्वतंत्रता को संतुलित करना एक जटिल चुनौती है।

# ईरान-इजरायल के बीच ऐलान-ए-जंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को ऐसे समझिए

कमलेश पांडे

दुनिया का थानेदार अमेरिका और उसका प्रबल प्रतिद्वंद्वी रूस (पूर्व सोवियत संघ का काबिल वारिस) के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी हुआ, हो रहा है अथवा होगा, वह कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अमेरिका-इंग्लैंड की युगलब्धि को संतुलित करने के लिए रूस-चीन का रणजोड़ रणनीतिक पूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसलिए हाल में ईरान-इजरायल के बीच शुरू हुए ऐलान-ए-जंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को इसी परिप्रेक्ष्य में जानने-समझने की जरूरत है। समझा जाता है कि जिस तरह से अमेरिका, यूक्रेन की पीठ थपथपा रहा है; ठीक उसी तरह से रूस, अब फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान को शह दे रहा है। क्योंकि उसकी स्पष्ट सोच है कि यूक्रेन में अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो की मदद तभी थमेगी, जब वह इजरायल के बचाव में मध्यपूर्व के देशों के साथ सीधे तौर पर उलझेगा। यही वजह है कि जब हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अपने प्रभाव वाले इलाके में इजरायल के सामने कमजोर पड़ने लगे तो हौसलाअफजाई के लिए उनके आका ईरान को इजरायल के खिलाफ सामने आना पड़ा। उधर जब अमेरिका भी इजरायल के साथ खुले मैदान में उतर गया, तो अब ईरान के तरफदारी में रूस की घोषणा की और सबकी निगाहें जमी हुई हैं। वैसे भी इजरायल पर एकांक बरसरी 200 ईरानी मिसाइलों के बाद अब इजरायली प्रतिक्रिया कितनी भयानक होगी, इस ओर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ऐसा इसलिए कि ईरान के हमले के

बाद भी इजरायल का हिजबुल्लाह पर एकांक थमा नहीं है। उसने लेबनान के बैरूत के दक्षिणी इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। मतलब लेबनान में फिर बमबारी की। ये हमले हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों पर किए गए। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने दो टुक कहा कि हमारा जवाबी ऑपरेशन प्लान तैयार है। हम तय करे कि जवाब कब देना है। जहां भी और जब भी होगा, हम ईरान पर हमला करेंगे। वहीं, ईरान के सेना प्रमुख ने धमकी दी कि अगर उनके देश पर हमला हुआ, तो वो इजरायल के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। इससे तब है कि बात अभी और बढ़ेगी। इसलिए पुनः यह सवाल मौजू है कि आखिर में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध की भयावह त्रासदी को झेलने के बावजूद समकालीन दुनिया स्थायी शांति की परिकल्पना करने के बजाय तीसरे विश्वयुद्ध की परिस्थितियों को बढ़ावा देने पर क्यों तुलु होई है? क्या उनका यह कथम उस लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा नहीं है, जो स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व की बात करते हुए नहीं अघाता है। सही मायने में तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी दुनियावी विरोधाभासों को उत्म करने या उन्हें सुलझाने की दृष्टि से पूरी तरह से विफल साबित हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक, शीत युद्ध कालीन करतूतों की बात यदि छोड़ दी जाए, तो समकालीन वैश्विक करतूतें यही झरारे कर रही हैं कि हथियारों के सौदागारों को जिंदा रखने के लिए दुनियाभर में जारी छद्मयुद्धों की बजाए रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध जैसे अन्य युद्ध भी बेहद जरूरी हैं। इसलिए हर ओर विरोधाभासों को

बढ़ावा दिया जा रहा है। सच कहूँ तो ये वही ताकतें हैं जो भारत-पाक युद्ध, भारत-चीन युद्ध, चीन-ताइवान युद्ध को लंबा चलाने देने की परिस्थिति पैदा करने में जब विफल हुई तो उन्हें अपने ही पड़ोस में नए-नए मोर्चे खोलने पड़े। क्योंकि दुनिया की फैक्ट्रियों में जब हथियार बनने लगे तो उनके खपत के लायक नित्य नया क्षेत्र चुनने की पहल तो सत्ताधीशों को करनी ही होगी। बहरहाल, अमेरिकन और रूसी नेतृत्व यही कर रहा है। चीनी और भारतीय नेतृत्व भी इसी उधेड़बुन में पड़ा है। आप मायें या न मायें, लेकिन अमेरिका-रूस गुट को आपस में भिड़ाकर और लंबे युद्ध में उलझाकर उन्हें कमजोर होने देने और खुद को दुनिया का नया थानेदार बनाने की जो चीनी चाल है, और उसके दृष्टिगत भारत की जो चुप्पी है, उससे अमेरिका-रूस दोनों की विगनी बंधी हुई है। शायद भारत भी चीन को पछड़कर यही मंजूबा पाले हुए है। सच कहूँ तो भले ही मुस्लिम आतंकवाद कभी अमेरिकी-ब्रिटिश एजेंडा रहा हो, लेकिन अब रूस-चीन गठबंधन भी इसी एजेंडे के आगे बढ़ाकर तेल के खेल में अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो को पटखनी देने की रणनीति अख्तियार कर चुका है। जिसका साइड इफेक्ट्स आज इजरायल के सौदागारों को जिंदा रखने के लिए दुनियाभर में जारी छद्मयुद्धों की बजाए रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध जैसे अन्य युद्ध भी बेहद जरूरी हैं। इसलिए हर ओर विरोधाभासों को

से अर्जित समृद्धि का सदुपयोग वह अपने मुल्क के नागरिकों को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के बजाए उन्मुक्त उपभोग, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद की भावना को पैदा करके उसको नियात करने में लगा दिया। क्योंकि उनके अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल बाँस को यही पसंद है। इससे इजरायल और भारत जैसे देशों की परेशानी बढ़ी, लेकिन वो यह भूल गए कि प्रकृति वही लौटती है, जो हमलोग बाँटे हैं। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, या बड़े इस्लामिक मुल्क, जब प्रकृति उन्हें छद्मयुद्ध, युद्ध और आतंकवाद की सीगात वापस करने लगी है तो अब ये देश उसे संभालने-झेलने में असमर्थ ही नहीं हैं, बल्कि भौचक्के भी रह जा रहे हैं। आपको ईरान-इराक युद्ध याद होगा। ईरान-अमेरिकी जंग भी याद होगी। तालिबान (अफगानिस्तान)-अमेरिका युद्ध ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। अमेरिका और सीरिया के बीच जो कुछ हुआ, या हो रहा है, वह सभी जानते हैं। जानकारों के मुताबिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक या मध्यपूर्व के देशों में अमेरिकी रणनीति यदि विफल हो रही है, तो उसके पीछे रूस की बहुत बड़ी भूमिका है। आज यदि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े मुल्क इस्लामिक आतंकवाद व कट्टरता की चपेट में हैं, तो इसके पीछे भी रूसी-चीनी अंतर्राष्ट्रीय शह ही है। दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी रणनीति बदली है और खुद को उम्मीद से ज्यादा मजबूत बनाया है, इसलिए वह अब अंतर्राष्ट्रीय सत्ता संतुलन का केंद्र बन चुका है। भारत भी अब हथियारों के सौदागारों की टीम में

शामिल होने को बेताब है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीनी चाल के दृष्टिगत ही भारत सरकार सोच-समझकर कोई कदम उठाती है। इसलिए अब दुनिया की घड़कन इस बात को सोचकर बढ़ रही है कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो भारत किधर होगा? क्या वह तीसरी दुनिया के देशों के साथ तटस्थ रहेगा, या फिर रूस से अपनी पुरानी यारी और अमेरिका से अपनी नई यारी निभाएगा! यही नहीं, जब दुनिया में महंगाई बम फूटेगा, तो उस स्थिति को भारत कैसे संभालेगा। वैसे तो ईरान और इजरायल दोनों भारत के करीब हैं, लेकिन इजरायल और भारत का उद्देश्य एक है-आतंकवाद का समूल सफाया। शायद यह होने का असली वक्त भी अब आ रहा है। भारत की रणनीति सफल होनी चाहिए कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद को खत्म किया जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आदि द्वारा प्रोत्साहित आतंकवाद जितनी जल्दी कुच्छता जाए, दुनिया उतनी जल्दी ही चैन की सांस ले सकेगी। इधर ईरान-इजरायल के बीच जंग के आसार के चलते कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने के आसार प्रबल हैं। इस हमले के बाद से कच्चे तेल के दामों में 4 फीसदी की तेजी आ गई है। ऐसे में दुनियाभर में महंगाई फिर से बढ़ने के आसार प्रबल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मिसाइल हमले से जुड़ी बातों के बीच गल 1 अक्टूबर मंगलवार की ही क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया। ब्रेंट वायदा 3.5% बढ़कर 74.2 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड 2.54 डॉलर

या 3.7% बढ़कर 70.7 डॉलर हो गया। कहना न होगा कि दुनियाभर में कच्चे तेल में होने वाले उतार-चढ़ाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जबकि युद्ध से ग्लोबल सप्लाय चैन भी टूट जाती है। ऐसे में आयात और निर्यात की गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं, जिससे महंगाई बढ़ने लगती है। पिछले साल रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब रूस के यूक्रेन पर अटक के बाद ग्लोबल सप्लाय चैन बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। वहीं, कच्चे तेल के दामों में भी जबरदस्त तेजी आई थी। वहीं, इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर शेरार बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी और डाओ स्पूचर्स समेत कुछ देशों के मार्केट लाल निशान के साक्ष्य कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में यदि यह जंग और बढ़ी तो कच्चे तेल में बढ़ोतरी से कई चीजें महंगी हो सकती हैं, जबकि शेरार बाजार में ऑयल सेंसिफिक स्टॉक पर तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल में तेजी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे- ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों में तेजी आने की संभावना है। वहीं, पेट और टायर शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि, इन कंपनियों की निर्भरता क्रूड पर होती है। ऐसे में क्रूड महंगा हुआ तो इन कंपनियों की इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। उधर, युद्ध और जियो पॉलिटिकल टेंशन के बढ़ने से सोने के भाव में तेजी देखने को मिलती है। ऐसे में ईरान के इजरायल पर हमले के बाद गैलड में खरीदारी देखने को मिल सकती है। दरअसल, युद्ध जैसे हालात में गैलड में निवेश को सुरक्षित माना जाता है।





# राजनैतिक दल हर बूथ पर नियुक्त करें एक-एक बीएलए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराने, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने में राजनैतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गयी। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिये गये।

## ● मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने की मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक



राजनैतिक दल हर बूथ पर एक बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करें ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के नाम और मोबाइल नंबर मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को किसी भी जानकारी की जरूरत होने पर आसानी से संपर्क किया जा सके। विशेष अभियान तिथियों के दौरान सभी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। उनके पास मतदाता सूची और सभी आवश्यक फॉर्म (जैसे- फॉर्म 6, 7 और 8) उपलब्ध होंगे, ताकि मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने संबंधी कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा, निवास परिवर्तन के लिए अब फॉर्म-6 के बजाय फॉर्म-8 का उपयोग करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जायेगा। 28 नवम्बर 2024 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। 09, 10, 23 और 24 नवम्बर 2024 विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित हैं। 24 दिसम्बर 2024 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

अर्हक तिथियों के बारे में भी चर्चा करते हुए बताया गया कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर 2025 को अर्ह होने वाले मतदाताओं के केवल फॉर्म-6 लिए जाएंगे, जिन पर अर्हता की निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी बताया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाये गये घर-घर सत्यापन के अंतर्गत चिन्हित किए गए मृतक/ शिफ्टेड/ रिपोर्टेड मतदाताओं के संबंध में फॉर्म-7 के माध्यम से कार्यवाही की गयी। मतदाता सूची में संशोधन या नामांकन के लिए मतदाता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के योगी के संकल्प को आईएफसी ने दिया समर्थन

## ● इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ग्लोबल एमडी मखतार डियोप ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का समर्थन करने और प्रदेश के बुनियादी ढांचे एवं कृषि तकनीक (एग टेक) में सहयोग करने के लिए उत्सुक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) के ग्लोबल एमडी मखतार डियोप ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में सहयोग को लेकर विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा हुई। खासतौर पर आईएफसी की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे और कृषि तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को लेकर उत्सुकता जाहिर की गई। बैठक में आईएफसी की ओर से प्रदेश में नमामि गंगो की तर्ज पर एक राज्यव्यापी जल कार्यक्रम विकसित किए जाने पर भी चर्चा की गई, जो वेस्ट डॉनट ट्रीटमेंट पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आईएफसी को सहयोग के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया।

मुलाकात के दौरान आईएफसी के ग्लोबल एमडी मखतार डियोप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का समर्थन करते हुए इसमें अपनी भागीदारी के प्रति उत्सुकता जाहिर की। इसके लिए विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और कृषि तकनीक (एगटेक) के माध्यम से फोकस किए जाने की आवश्यकता जताई गई। आईएफसी विगत कई वर्षों से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। भारत के पहले और सबसे बड़े बिजली क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडीग्रिड में आईएफसी ने 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिसकी मदद से भारत के ट्रांसमिशन सेक्टर का आधुनिकीकरण हो रहा है। वहीं, आईएफसी पीपीपी परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में भी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए आईएफसी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 शहर (कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज) हैं जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है, जो इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आईएफसी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप संयुक्त रूप से राज्य के लिए पूलड फाइनेंसिंग संरचना स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे में निजी पूंजी को आकर्षित किया जा सके। एक पूलड कमर्शियल फाइनेंसिंग संरचना उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय ताकत का उपयोग कर शहरी बुनियादी ढांचे की सामूहिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। आईएफसी के सहयोग से वर्ल्ड बैंक ग्रुप 100 शहरों के कार्यक्रम के समर्थन से, एक राज्य मध्यस्थ सरकारी गारंटी या क्रेडिट वृद्धि के साथ एक पूल आधार पर ऋण/बांड जुटा सकता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ डब्ल्यूबीजी-एडीजी 100 शहरों के कार्यक्रम का उद्देश्य 100 शहरों में

जल आपूर्ति, स्वच्छता और टोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में बैंक योग्य परियोजनाओं को वितरित करना है। यह कार्यक्रम अभी प्रारंभिक चरणों में है। आईएफसी ने 2007 से अब तक रसायन और उर्वरक, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, स्वास्थ्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 29 परियोजनाओं में लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। प्रदेश सरकार के पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के प्रयासों में आईएफसी ने जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत आईएफसी पीपीपी के रूप में ई-बसों की खरीदारी, संचालन और रखरखाव की सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आईएफसी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ प्रत्यक्ष सहभागिता में पीपीपी और एगटेक पर सलाह शामिल है। आईएफसी को झार्षी सोलर प्रोजेक्ट पर लेन-देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि ग्राहक को झार्षी में 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क परियोजना की संरचना और निवृत्त प्रक्रिया में सहायता की जा सके। इस परियोजना से सालाना कम से कम 1.1 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करने, लगभग 330 मिलियन डॉलर वित्तपोषण की सुविधा, ऊर्जा अंतर को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि की उम्मीद है।

# प्रदेश के 25 जिलों में खुलेंगे नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज, छोटे जिलों पर विशेष फोकस

## ● अयोध्या, बहराइच, कौशांबी, ललितपुर समेत 25 नर्सिंग कॉलेजों में अगले सत्र से शुरू हो जाएगी पढ़ाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में अगले बढ़ रही है। इसके तहत योगी सरकार मेंडिकल की यूजी और पीजी के सीटें बढ़ाने के बाद पैरामेडिकल की सीटों को सीटों में बड़े पैमाने में वृद्धि करने जा रही है। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 25 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी छात्र न सिर्फ सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर सकेंगे, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकेंगे। सीएम

योगी को पहले पर 20 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 5 जिलों में निर्माण कार्य स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वहीं, सीएम ने कार्यवाही संस्थाओं को कॉलेजों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि अगले एकेडमिक सेशन से पढ़ाई शुरू हो सके।

डीजीएमई किंगजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के छात्रों को मेंडिकल और पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने प्रदेश के 25 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है, जहां अगले एकेडमिक सेशन में पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

# मुख्यमंत्री आज महाकुंभ-2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लांच करेंगे

## ● प्रयागराज में महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण करने के साथ ही साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ-25 के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण करने के साथ वेबसाइट और ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। सीएम योगी ने महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य तरीके से आयोजित कराने के लिए खुद कमान संभाल ली है। ऐसे में वह रविवार को महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान अधिकारियों से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ अन्य बिंदुओं की गहन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जाहों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। वहीं जन

प्रतिनिधियों और साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसके बाद वह महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान सीएम योगी महाकुंभ से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण करेंगे और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसमें वह अधिकारियों से कार्यों की बिंदुवार चर्चा करेंगे। साथ ही दिशा-निर्देश देंगे। इसके बाद सीएम योगी महाकुंभ-25 के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण करेंगे। साथ ही महाकुंभ-25 की वेबसाइट और ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। इसके अलावा वह यहां पर जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों और साधु संतों के साथ मुलाकात भी करेंगे।

महाकुंभ-25 के लोगो का उपयोग महाकुंभ की वेबसाइट और ऐप के साथ अन्य प्रचार माध्यमों में किया जाएगा। यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वायु, रेल एवं सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंचने में मार्ग दर्शक का कार्य करेगा।

इसी के माध्यम से प्रयागराज में आवास, स्थानीय परिवहन, पार्किंग, चाटों तक पहुंचने के दिशा-निर्देश आदि की जानकारी मिल सकेगी। इसमें स्थानीय और आसपास के आकर्षणों और पर्यटन स्थलों का मार्ग दर्शन भी होगा। मेला स्थल में नेविगेट करने और धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभागिता के संदर्भ में विस्तृत जानकारी होगी। श्रद्धालुओं को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह और धार्मिक वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा, आपातकालीन स्थितियों के लिए एसओएस सुविधा, जिससे श्रद्धालु तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें।

# नवरात्र में 'धन-धान्य' से भरा उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ से अधिक किसानों का घर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

## ● प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंच गए 4985.49 करोड़, सीएम योगी ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार

शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि पर देश के साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों का घर भी 'धन-धान्य' से परिपूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इससे देश के 9.4 करोड़ किसानों के साथ ही उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। प्रदेश के किसानों के खाते में 4985.49 करोड़ रुपये पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को शारदीय नवरात्रि में यह उपहार दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया।

25 लाख 91,884 किसानों के खाते में 4985.49 करोड़ रुपये भेजे गए। वहीं देश के 9.4 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक भेजकर लाभान्वित किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव जीतने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 18 जून को 17वीं किस्त का वितरण किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट

'एक्स' पर पोस्ट भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अन्नदाता किसानों के जीवन को सुगम, स्वावलंबी और समृद्ध बनाने हेतु सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' की 18वीं किस्त जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि किसानों को आर्थिक संवर्धन प्रदान करती इस कल्याणकारी योजना की 18वीं किस्त के अंतर्गत हस्तांतरित 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के 9.4 करोड़ से अधिक कृषक लाभान्वित हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पावन शारदीय नवरात्रि के अवसर पर वरदान समान यह उपहार प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी कृषक भाई-बहनों की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी!

# भाजपा सरकार के म्हांगई रोक पाने में पूरी तरह से विफल: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार म्हांगई रोक पाने में पूरी तरह से विफल है। आज जनता खाने पीने की चीजों दाल, तेल, आटा से लेकर सब्जी, दूध सबके दाम आसमान छू रहे हैं।

भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने म्हांगई रोकने के लिए जनता से झूठे वादे किये। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव के समय वोट लेने के लिए जो भी वादे करती है, सत्ता में आने के बाद ठीक उसी के विपरीत आचरण करती है। आम जनता म्हांगई से त्रस्त है। पिछले दिनों एक बार फिर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के दाम बढ़ गए। तेलों, दालों और अन्य खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा असर गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। भाजपा सरकार में काला बाजारी और मुनाफा खोरी चरम पर है। किसान के खेत से पांच रुपये किलो बिकने वाला आलू आज



40 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह से म्हांग, लहसुन, टमाटर के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के जानबूझकर मुनाफाखोरी को प्रश्रय दे रही है। किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है लेकिन बिचौलिए मुनाफा कमकर मालामाल होते जा रहे हैं। आम आदमी इस म्हांगई और मुनाफाखोरी में लूट रहा है। सत्ता के संरक्षण में मुनाफाखोर जनता को लूट रहे हैं। सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप तमाशा देख रही है और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। आने वाले समय में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से मिल रहे हर खज्म का हिसाब लेगी।

# सपा की सरकार बनाने में नौजवान निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका: श्याम लाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

## ● सपा लोहिया वाहिनी ने किया आगाज-ए-इंकलाब सम्मेलन का आयोजन

आगाज-ए-इंकलाब सम्मेलन शनिवार को गांधी भवन प्रेक्षागृह, कैसरगंज में सम्पन्न हुआ जिसमें संगठन के सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रंटेल संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन में 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेने के साथ समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती के लिए दाम कम करने का निर्णय लिया गया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, नीतियों और उपलब्धियों से जनता को जोड़ने और पीडीपी को और मजबूत करने के लिए जातीय जगगणना करने के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा संघर्ष की भी निश्चय किया

पार्टी की सरकार बनाने के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी के नौजवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने आगाज-ए-इंकलाब को स्पष्ट संदेश दिया है कि 'लाल क्रांति से लोहिया वाहिनी बदलेगा परिवेश, यूपी में परिवर्तन खातिर पीडीपी जनययक अखिलेश।' लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राम करन निर्मल ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, म्हांगई, बेरोजगारी चरम पर है। नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। समाजवादी नौजवान समता, स्वतंत्रता और लोक कल्याण के लिए इंकलाब करेंगे। सम्मेलन में विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव, पूर्व एमएलसी डॉ. राजपाल कश्यप, संतोष जाटव, अमरेंद्र आर्य आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

# यूपी के सभी जिलों में नवम्बर माह में होगा कैरियर मेले का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सभी जनपदों में नवंबर माह के दौरान कैरियर मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कैरियर के विभिन्न विकल्पों के प्रति जागरूक करना, शिक्षा एवं रोजगार के नए अवसरों की जानकारी प्रदान करना है। कैरियर मेले में छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उचित कैरियर चुनने में मदद की जाएगी। मेले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, निजी और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नियोजकों भी भाग लेंगे। यहां पर कैरियर विशेषज्ञ युवाओं को उनके शैक्षिक और व्यावसायिक विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और उन्हें उच्च शिक्षा एवं रोजगार के विभिन्न

अवसरों से अवगत कराएंगे। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने इस कैरियर मेले को युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि कैरियर मेला युवाओं के लिए अपने भविष्य की योजनाओं को सशक्त बनाने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का एक बेहतरीन मंच होगा। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि वे इन मेलों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इसका लाभ उठाएं। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को कैरियर मेले के सफल आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, नवंबर माह में प्रत्येक जनपद में कैरियर मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां विभिन्न कैरियर संभावनाओं की तलाश एवं जागरूकता के लिए एक मंच उपलब्ध होगा।

# अयोध्या के कुम्हारों के जीवन में 'दीप' जला रही प्रदेश सरकार

## ● कमी कमाते थे 20 से 25 हजार, अब दीपोत्सव में ही बन जाते हैं लखपति

## ● आठवें दीपोत्सव में 25 लाख दीयों के प्रज्वलन का है लक्ष्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या



संवारे का बीड़ा उठाना। इसके बाद भगवान राम के वनवास से लौटकर आने की खुशी में मनाई जाने वाली दीवाली और दीपोत्सव कराने का ऐलान कर दिया। हर वर्ष राम की पैड़ी पर इसका आयोजन होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित होते हैं। दीयों की खरीदारी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुम्हारों को वरीयता दी। नतीजा यह है कि इन वर्ष दीपोत्सव का आठवां संस्करण होने जा रहा है। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में

दीयों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आठवां दीपोत्सव और भी भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 लाख दीयों का जनता का ऐलान किया है। अयोध्या के विद्याकुण्ड के निकट स्थित जयसिंहरपुर गांव में बड़े स्तर पर कुम्हार दीयों को बनाने में जुटे हुए हैं। यहां का 40 परिवार दीपोत्सव के लिए दीप बना रहा है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जीवन बदल दिया। दीपोत्सव में बिक्री होती ही है, लेकिन स्थानीय कुम्हारों के लिए की गई अपील के बाद लोग मिट्टी के दीयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जयसिंहरपुर गांव की लक्ष्मी प्रजापति बताती हैं कि योगी सरकार की योजना ने हमारे घर को रोशन कर दिया है। दीपोत्सव में दीयें बनाने का ऑर्डर मिलते ही पूरा परिवार जुट जाता है। 30 से 35 हजार दीयें बनाकर बेचे जाते हैं। जयसिंहरपुर गांव के राकेश प्रजापति बताते हैं कि

अभी हमें टेका नहीं मिला है, लेकिन विगत वर्षों में मिले आर्डर को देखते हुए हम लोगों ने दीये बनाने शुरू कर दिए हैं। सीएम के ऐलान के बाद हमारी आमदनी बढ़ी है। गांव की आशा बताती है कि हम लोग हर वर्ष 20 से 25 हजार दीये बनाकर दीपोत्सव के लिए देते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद शहर के लोग दीयो से अपना घर सजाते हैं। नहीं तो लोग चाइना की झालरों का प्रयोग करते थे। गांव के राजेश प्रजापति ने बताया कि ये सीएम योगी की ही देन है कि दीपोत्सव के बाद से प्रजापति की भी पहचान हो गई है। नहीं तो हमें कोई पहचानता नहीं था। अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अब तक 2 लाख से अधिक दीप तैयार कर लिए हैं। आठवें दीपोत्सव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अयोध्या नगरी एक नया कीर्तिमान रच देगी। दीपोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं।

# पूर्व प्रधानाचार्य समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीतियों एवं उसकी समावेशी विचारधारा से प्रेरित होकर जनपद मुजफ्फरनगर के सूर्य देव शण्कर कॉलेज के चेयरमैन एवं प्रिंसिपल एडवोकेट शिव कुमार पाल ने अपने समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह के समक्ष कांग्रेस पार्टी की प्रार्थमिक सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर दिनेश सिंह ने उनके गले में तिरंगा पट्टिका पहनाकर तथा कांग्रेस सदस्यता कार्ड देकर उन्हें

विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश के आमजनमानस को दुख दर्द को समाप्त तथा भविष्य उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया। उनके इस सार्थक प्रयास का ही नतीजा है कि आए दिन प्रदेश के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता तथा समाज में प्रतिष्ठित अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सकों द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जा रही है।



धरती



भारत डोगरा

हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं, जो खुल कर कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हाल का अनुभव बताता है कि मुख्यमंत्री वह नहीं बनता जो जोर-शोर से इसका डंका पीटा है।

अखिलेश शर्मा, पत्रकार @akhileshsharma1



विचार

8

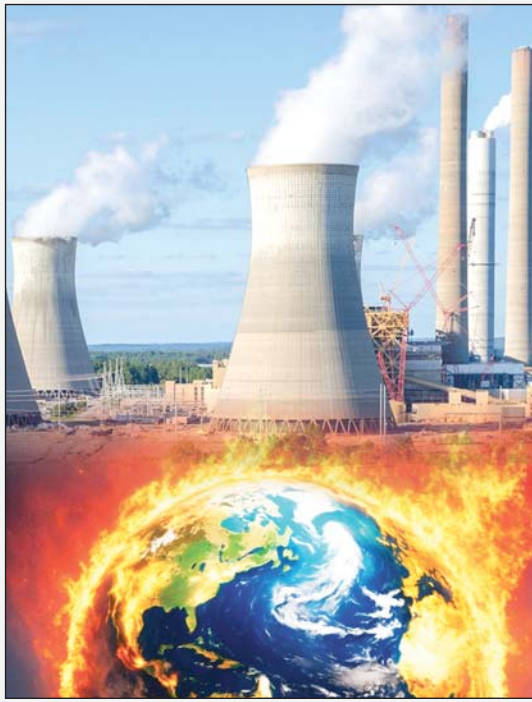
# हम जीवन मूल्यों का यथासंभव करें प्रसार

सभी शताब्दों में यह संभावना पहली बार सामने आने लगी कि तेजी से बदलती तकनीकी के दौर में मनुष्य निर्मित कारणों से वे हालात अस्त-व्यस्त हो सकते हैं जो धरती पर मनुष्य सहित लाखों जीवन रूपों के पनपने के अनुकूल अवसर उत्पन्न करते हैं। यह संभावना ग्रीनहाउस गैसों के अति उत्सर्जन से जुड़े जलवायु बदलाव, अनेक पर्यावरणीय गंभीर क्षति और महाविनाशक हथियारों के उत्पादन के संदर्भ से उत्पन्न हुई।

पर इन समस्याओं की समझ बनने के बाद भी बीसवीं शताब्दी के अंत तक इन्हें सुलझाने की दिशा में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि इस शताब्दी के अंतिम दो दशकों में ये समस्याएं और विकट हो गईं। अंतः 21वीं शताब्दी के आरंभ में जो पीढ़ी जी रही है वह बहुत नाजुक और संवेदनशील दौर में जी रही है जब धरती की जीवनदायिनी क्षमता ही खतरे में है। जब यह पता चल गया कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेज वृद्धि के कितने गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, तब से अब तक के समय के दौरान भी इस गंभीर खतरे को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में तो आरंभ से ही पता था, पर तो भी पिछले 79 वर्षों (1945-2024) के दौरान परमाणु हथियारों के खतरे को बुनियादी तौर पर समाप्त करने का कोई असरदार उपाय नहीं हुआ है। चूंकि

इस तरह के गंभीर खतरे हमारे और भावी पीढ़ियों, के हमारे बच्चों के भविष्य को बेहद अंधकारमय बना रहे हैं, अतः जरूरी हो गया है कि दुनिया भर के लोग लोकतांत्रिक और अहिंसक राह पर चलते हुए इन खतरों के समाधान के लिए व्यापक एकता स्थापित करें। धरती पर लाखों अन्य तरह के जीव हैं। इन बेजुबान जीवों को उनकी किसी गलती के बिना ही गंभीर खतरे में डाल दिया गया है। इस विषय पर हॉररवर्ड के जाने-माने विशेषज्ञ प्रो. एडवर्ड ओ. विलसन ने कुछ समय पहले टाइम पत्रिका में लिखा था, जीव-विज्ञानी प्रायः स्वीकार करते हैं कि यदि हम मनुष्य के आगमन (होमो सेपियंस) के आरंभिक दिनों की तुलना आज की दुनिया से करें तो प्रजातियों के लुप्त होने की गति सौ गुणा बढ़ चुकी है।

वर्ष 1992 में विश्व के 1575 वैज्ञानिकों ने (जिनमें उस समय जीवित नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों में से लगभग आधे वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे) एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, हम मानवता को इस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है? पृथ्वी और उसके जीवन की व्यवस्था जिस तरह हो रही है उसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है। अन्यथा बहुत दुख-दर्द बढ़ेगा और हम सबका घर यह पृथ्वी इतनी बुरी तरह तहस-नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नहीं



जा सकेगा। आगे इन वैज्ञानिकों ने कहा कि वायुमंडल, समुद्र, मिट्टी, वन और जीवन के विभिन्न रूपों सभी पर तबाह हो रहे पर्यावरण का बहुत दबाव पड़ रहा है और 2100 तक पृथ्वी के विभिन्न जीवन रूपों में से एक तिहाई लुप्त हो सकते हैं। मनुष्य की वर्तमान जीवन-पद्धति के अनेक तौर-तरीके भविष्य में सुरक्षित जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं, और इस जीती-जागती दुनिया को इतना बदल सकते हैं कि जिस रूप में जीवन को हमने जाना है, उसका अस्तित्व ही कठिन हो जाए।

इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि प्रकृति की इस तबाही रोकने के लिए बुनियादी बदलाव जरूरी है। ऐसी महत्वपूर्ण चेतावनियों के बारे में यही कहा जा सकता है कि वे सच सिद्ध हो रही हैं और विश्व के सभी जीव पेशी से गंभीर खतरों की ओर धकेले जा रहे हैं। इसके बावजूद सबसे समृद्ध और सक्षम समाजों में लारवावाही, विलासिता, भोगवाद और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने पर कोई व्यापक प्रयास नहीं हो रहा है।

अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि बहुत से दुख-दर्द का मूल कारण मनुष्य के लालच में और अपनी जरूरतों से कहीं अधिक साधन हड़पने की प्रवृत्ति में है। यही अन्याय, विषमता, दूसरों के लिए वै-भाव की ओर ले जाती है। एक मनुष्य का लालच किसी गांव में जमीन हड़पने का जानलेवा झगड़ा करा सकता है, तो लाखों मनुष्यों का मिला-जुला लालच दो देशों में युद्ध क्यों नहीं करा सकता है? जब युद्ध की संभावना बढ़ती है, तभी हथियारों की होड़ भी बढ़ती है, और यह अधिक से अधिक विनाशक हथियारों की ओर ही ले जाती है। मनुष्य यदि चाहे तो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपना शेष सारा सामर्थ्य दूसरों की (अभावग्रस्त मनुष्यों और अन्य सब जीवों की) सेवा में लगा सकता है, या सब तरह के जीवन के आधार, जो प्रकृति है, के संरक्षण में लगा सकता है। पर लालच के कारण वह अधिक खाने-पीने, नशा करने, बड़े भवन बनाने, हर तरह के भोग-विलास करने की ओर बढ़ता है, और जब लाखों लोग यही भोग-विलास एक साथ करने का प्रयास करते हैं तो इससे उस क्षेत्र के वनों, भूमि, हवा, पानी पर अधिक दबाव पड़ता है, और पर्यावरण का विनाश होता है। अतः यदि लालच, दूसरों के संसाधन हड़पने और भोग-विलास की दौड़ पर हम रोक लगाए

और उसके स्थान पर सादगी, सेवा, समता, स्नेह और संतोष के आदर्शों को प्रतिष्ठित करें तो इससे हमारे अपने और आसपास के जीवन में दुख-दर्द के मूल कारण दूर होंगे और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान की नींव भी तैयार होगी। इन सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों का जैसे-जैसे हमारे जीवन में ह्रास हो रहा है वैसे-वैसे हमारे अपने जीवन का और आसपास का दुख-दर्द बढ़ रहा है, और दुनिया की सबसे गंभीर समस्याएं और विकट हो रही हैं। सवाल यह है कि इन सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक जीवन मूल्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार, मुहल्ले और स्कूल में कैसे प्रतिष्ठित करें। हम यह कर सकते तो विश्व की सबसे गंभीर और बुनियादी समस्याओं को हल करने की नींव भी अपने आप तैयार होने लगेगी। इसमें कई वर्ष लगेगे। पर एक सत्य तथ्य निरंतर प्रयास जारी रहा तो एक अर्ध पीढ़ी तैयार होने लगेगी जो महाविनाशक हथियारों और जलवायु बदलाव जैसी सबसे खतरनाक समस्याओं के समाधान को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेगी।

इन जीवन-मूल्यों को पहले हमें स्वयं अपनाना होगा, फिर आगे प्रयास परिवार स्तर पर हों। आदर्श परिवार की परिभाषा केवल यहां तक सीमित नहीं है कि सब सदस्य मिल-जुल कर रहें। इससे आगे परिवार को वह प्रशिक्षण केंद्र बनना चाहिए जहां सब सदस्य बेहतर समाज और दुनिया बनाने में अपनी भूमिका की तैयारी करें। यही स्थिति स्कूल की है। एक स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यकन यह नहीं है कि वहां से कितने डाक्टर, इंजीनियर, उच्च अधिकारी या नेता निकलें। उसका सबसे बुनियादी मूल्यकन तो यह है कि वहां शिक्षित कितने बच्चों ने सादगी, संतोष, सहयोग, समता, स्नेह, सेवा, करुणा के सबसे बुनियादी जीवन-मूल्य ग्रहण किए, कितनों ने आपसी सहयोग से सबकी भलाई के लिए कार्य करने को अपना उद्देश्य बनाया। जहां भी और जितना संभव हो, हम इन जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए कार्य करते रहें। इसके लिए मुहल्ले और गांव स्तर के प्रयास आरंभ करें जो आगे चल कर ऐसे अन्य प्रयासों से जुड़ते जाएं, झरने नदियों में मिल कर सागर की ओर बढ़ते रहें।

अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि बहुत से दुख-दर्द का मूल कारण मनुष्य के लालच में और अपनी जरूरतों से कहीं अधिक साधन हड़पने की प्रवृत्ति में है। यही अन्याय, विषमता, दूसरों के लिए वै-भाव की ओर ले जाती है। एक मनुष्य का लालच किसी गांव में जमीन हड़पने का जानलेवा झगड़ा करा सकता है, तो लाखों मनुष्यों का मिला-जुला लालच दो देशों में युद्ध क्यों नहीं करा सकता है? जब युद्ध की संभावना बढ़ती है, तभी हथियारों की होड़ भी बढ़ती है और यह अधिक से अधिक विनाशक हथियारों की ओर ही ले जाती है। मनुष्य यदि चाहे तो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपना शेष सारा सामर्थ्य दूसरों की (अभावग्रस्त मनुष्यों और अन्य सब जीवों की) सेवा में लगा सकता है या सब तरह के जीवन के आधार, जो प्रकृति है, के संरक्षण में लगा सकता है

## बदमाशी की सेल

मीडिया



सुधीश पंचेरी

पिछले दिनों कई भीषण जानलेवा कार एक्सीडेंट्स हुए हैं तो उनके लिए अक्सर ऐसी कारणों के ऐसे विज्ञापन हमें दोषी नजर आने लगते हैं। एक ओर बहुत से लोग तेज कारों को वेचते हैं। दूसरे बहुत से लोग, कुछ कारों को 'बैड आस' कह कर वेचते नजर आते हैं

काला सूट पहने, हेकड़ी से भरा एक हीरो एक नई कार की 'टेस्ट ड्राइव' करके आता है कि सेल्समैन पूछता है कि 'टेस्ट ड्राइव' कैसी रही? हीरो हिकारत से भर कर कहता है: 'बैड आस'। हीरो अपनी 'एपल वॉच' को टच करता है तो 'कार' तुरंत पुराती हुई स्टार्ट हो जाती है। सेल्समैन धक्का कर पीछे हट जाता है। 'बैड आस' अंग्रेजी का मुहावरा है, जिसका मतलब है बदमाश, रफ टर्क, धमंजी, दुलतीमार, घटिया, हरामी...जाहिर है कि ये सारे विशेषण 'दुर्गुणायक' हैं, 'नकारायक' हैं जो किसी खननायक के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं। यही विशेषण एक कार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 'बैड आस' इसीलिए 'नकारायक कैचलाइन' है जो कार के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे ही ब्रांड की कार फिल्म 'एनिमल' में दिखाती है जिसमें बैट कर, 'बैड आस' कहने वाला हीरो बीच सड़क पर एंटी मारता है जहां 'एनिमल' का 'असली हीरो' खड़ा है। 'बैड आस' कहने वाला हीरो फिल्म में गुंगा बना है। बोल नहीं सकता जबकि एनिमल का असली हीरो 'बैड आस' को अपने बाप पर जानलेवा हमला करने का अपराधी मानता है। इसलिए उसे खत्म करने आया है। यों ये दोनों चरेरे या मर्मेर भाई हैं।

दोनों के बीच जम के फाइट होती है। तभी मालूम होता है कि 'बैड आस' कहने वाला ही दुरासल, गुंगा है। बोल नहीं सकता। फाइट के अंत में 'एनिमल' का असली हीरो, 'बैड आस' कहने वाले हीरो को जान से मार देता है...इस प्रसंग से अब तक साफ हो गया होगा कि 'बैड आस' का मतलब क्या है और कार को 'बैड आस' क्यों कहा जा रहा है। इसका कारण 'मारकेटिंग रणनीति' है। अब तक महंगी कारों को उनकी गुणवत्ता को बता कर बेचा जाता था कि यह कम तेज या मालेज देती है, सीटें आरामदेह हैं, 'सुरक्षा बैलून' युक्त हैं और बॉडी मजबूत है। कोई कहता कि ये कार ले ले लो। इसमें इतनी जगह है कि पूरा परिवार फिकनक मनाते जा सकता है। इसके 'शोक एब्सॉर्बर' इतने बहिया हैं कि धक्के महसूस ही नहीं होते। इतने गिपर हैं, कुछ ही देर में टॉप स्पीड ले लेती है, और ब्रेक बेहद 'भरोसेमंद' हैं। और चूंकि हर कार ऐसी ही पॉजिटिव सूचनाओं और उपयोगिता बताते हुए बेची जाती है। और इस तरह कुछ पहले तक एक

कार से दूसरी कार में फर्क करना मुश्किल दिखने लगा था, लेकिन अब मारकेटिंग वालों ने एक कार को दुर्गुणायक विशेषण से नवाजा है ताकि लोगों का इस कार की ओर ध्यान जाए। उसे उसकी 'बदमाशी' के लिए खरीदा जाए। कई कारें इन दिनों 'थ्रिल' के लिए भी बेची-खरीदी जाती हैं। कुछ मजबूती के लिए, कुछ अपनी तेजी के लिए बेची जाती हैं जबकि आम शहर के भीतर कार की अधिकतम स्पीड चालीस से साठ किमी. प्रति घंटे की होती है, लेकिन जब कार का कोई 'मारकेटर' कहता है कि इसमें 'थ्रिल' है, कि जरा सी जाते हैं 'ब्रेक' लगा सकती है, कि पहाड़ों पर फरटि से दौड़ सकती है तो कोई क्या कर सकता है। एक ओर शहर के भीतर चालीस से साठ किमी. प्रति घंटे की स्पीड की सीमा, उधर 'हाईवे' पर अस्सी से सौ किमी. की सीमा और फिर कार को 'फरटि' से चलाने के लिए उकसाना...पूरा पैकेज है।

पिछले दिनों कई भीषण जानलेवा कार एक्सीडेंट्स हुए हैं तो उनके लिए अक्सर ऐसी कारणों के ऐसे विज्ञापन हमें दोषी नजर आने लगते हैं। एक ओर बहुत से लोग तेज कारों को वेचते हैं। दूसरे बहुत से लोग, कुछ कारों को 'बैड आस' कह कर वेचते नजर आते हैं और जब वे किसी को कुचक्य कर, किसी से टकरा कर लोगों को आहत कर डालती हैं तो अफसोस करते हैं कि द्रव्य ये क्या हुआ! ऐसी हर कार महंगी होती है जिसके लिए बहुत सा पैसा खर्च करने वाले ही 'स्पीड किंग थ्रिल' एंजाय कर सकते हैं। जितनी स्पीड उतना ही थ्रिल, जितनी 'बैड आस' उतनी ही आकर्षक और कार के बदमाश होने के कारण आपके बदमाशिय होने का गर्व कि देखा कि इनकी कार कितनी दुष्ट भयावनी है। इस तरह आजकल की कार मारकेटिंग 'बैड आस' की 'बदमाश' तक को आदर्श की तरह पेश करती है और जब ऐसी कोई कार किसी को मारती-उड़ती चली जाती है तो कोई भी कह सकता है कि सब 'बैड आस' की कारस्तानी है वही इसकी जिम्मेदार है। 'बैड आस' कार का स्टार्ट के शोक ही जोर से 'गुर्रन' उसकी 'गुणवत्ता' की निशानी बताई जा रही है। मानो किसी की दुष्टता, किसी का बुरापन, हरामीपन जैसे दुर्गुण ही उसके सट्टण हों! कार बेचना न हुआ बदमाशी का आदर्शिकरण हुआ! क्या इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए?

## दोस्ती चाहती हैं आक्रामक प्रजातियां

जलवायु



डॉ. सत्यवान सौरभ

लैंडान के मामले में देखा गया है, जिसे ब्रिटिश दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। लैंडान का तेजी से प्रसार हुआ है, जो जिम कॉवर्ट नेशनल पार्क आदि जैसे कई राष्ट्रीय उद्यानों में देसी वनस्पतियों को मात देकर और कृषि फसलों और स्थानीय जैव-विविधता को खतरा है

आक्रामक प्रजातियों को अक्सर परिस्थितिक तंत्र के हानिकारक विघटनकारी के रूप में देखा जाता है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ आक्रामक प्रजातियां पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सकती हैं। हालांकि वे मूल जैव-विविधता के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं, लेकिन नई परिस्थितियों में जल्दी से अनुकूलन करने की उनकी क्षमता कभी-कभी परिस्थितिक तंत्र को स्थिर करने या कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने में मदद कर सकती है। विश्व प्राणी समुदाय में आक्रामक प्रजातियों को अक्सर कार्बन संचयन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। विश्व प्राणी समुदाय में आक्रामक प्रजातियों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, जिससे देशी परिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक स्तर पर गलत धारणा बन जाती है। इस श्रेणी में गैर-देशी 'खरबूतवार' से लेकर कीड़ों और जलीय आक्रमणकारियों तक की कई प्रजातियों को गलत समझा जाता है। अक्सर उनका गलत प्रबंधन किया जाता है। पहचानना महत्वपूर्ण है कि जानबूझकर या अनजाने में पेश की गई अधिकांश प्रजातियां देशी परिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा नहीं करती हैं। आक्रामक प्रजातियों वे पौधे, कीड़े और जलीय जीव हैं, जो अपने वर्तमान आवासों के मूल निवासी नहीं हैं। अक्सर नये परिस्थितिकी तंत्रों में फैल जाते हैं, जिससे स्थानीय जैव-विविधता बाधित होती है। इन प्रजातियों को गैर-देशी या पेश की गई प्रजातियां भी कहा जाता है। आक्रामक प्रजातियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली आक्रामिक आगमन प्रजातियां अक्सर अचानक और अनजान तरीके से आती हैं, जैसे कि जेबरा मसल, जिसे ब्लैक सी से दूसरे क्षेत्रों में जहाजों में बैलस्ट पानी के माध्यम से पहुंचाया गया था, जहां यह तब से स्थानीय बुनियादी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है। दूसरी आक्रामक प्रजातियां जानबूझकर पेश की जाती हैं, जैसा कि लैंडान के मामले में देखा गया है, जिसे ब्रिटिश दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। लैंडान का तेजी से प्रसार हुआ है, जो जिम कॉवर्ट नेशनल पार्क आदि जैसे कई राष्ट्रीय उद्यानों में देसी वनस्पतियों को मात देकर और कृषि फसलों और स्थानीय जैव-विविधता को खतरा है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि के साथ ही आक्रामक प्रजातियों

के साथ हमारे संबंध भी विकसित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने में आक्रामक प्रजातियों के कार्बन पृथक्करण में इनकी भूमिका है। कुछ आक्रामक पौधों की प्रजातियों में महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए: प्रोसोपिस स्पाइरोकार्पा भारत में आक्रामक प्रजाति, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जो निम्नोक्त भूमि में कार्बन भंडारण में योगदान करती है। स्पार्टाना अल्टरनिएफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजाति तटीय मिट्टी को स्थिर कर सकती है, कठोर रोक सकती है और समुद्र के बूढ़े स्तर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा कर सकती है। कुछ आक्रामक प्रजातियां जैसे साइबेरियाई एल्म, अधिकांश सूखा-प्रतिरोधी हैं एवं जहां देशी प्रजातियां विफल हो जाती हैं, वहां वनस्पति आवरण प्रदान करती हैं, जिससे परिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण देशी पौधों की कमी होने पर आक्रामक पौधों की प्रजातियां परमाणुओं के लिए खाद्य संसाधन प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए: पूर्वी अमेरिका में लोनीसेरा जैपॉनिका (जापानी हनीसकल) कुछ मौसमों के लिए: दक्षिण अफ्रीका में आक्रामक नीलगिरी के पेड़: स्थानीय प्रजातियों के लिए आवास की मुहैया करवाते हुए, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में मदद की है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वन्य क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण पहल का समर्थन करता है। समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए आक्रामक प्रजातियों के प्रसार एवं प्रभाव को टूट करने के लिए निरंतर निगरानी प्रणाली स्थापित करना। आक्रामक प्रजातियां महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लाभ प्रदान कर सकती हैं, जैसे परिस्थितिक तंत्र को स्थिर करना एवं कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना।

## क्या नौकरी की कीमत जिंदगी है

वर्क प्लेस



सोनम लववशी

पुणे की 26 वर्षीय एना, अर्नस्ट एंड यंग (ईआई) जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थीं। अपने स्कूल और कॉलेज की टॉपर थीं और कम उम्र में सीए क्वालिफाई करके इस बड़ी कंपनी का हिस्सा बनीं। उनके माता-पिता का सपना था कि उनकी बेटी एक अच्छे संस्थान में काम

करे और भविष्य को उज्वल बनाए। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह कंपनी उनके लिए अवसरों का द्वार नहीं, बल्कि उनकी जान लेने का कारण बनगी। अत्यधिक कार्यभार और मानसिक दबाव के चलते एना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सवाल उठता है, क्या काम के दबाव से किसी की मौत हो सकती है?

एना की मां ने ईवाई के अध्यक्ष को पत्र लिख कर अपनी बेटी की मौत के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने बताया कि एना को इतना काम सौंपा जाता था कि वह चैन से सो भी नहीं पाती थीं। देर रात तक मैनेजर कॉल करके रिपोर्ट तैयार करने का दबाव डालते थे। सवाल उठता है, क्या कंपनियों को कर्मचारियों पर इतना दबाव डालने का अधिकार है कि वे मानसिक-शारीरिक रूप से टूट जाएं? आखिर, ऐसे में कहां गए संवैधानिक अधिकार और मानसिक दबाव ग्या नैतिकतावादी दृष्टिकोण? जिस तरीके के सवाल या यूं कहें आरोप एना की मां कंपनी पर लगा रही हैं, तो यह वक्त है सचेत हो जाने का, क्योंकि कोई भी कंपनी या काम किसी से ज़ुब्र रहे हैं। एना की मौत ने इस अवसर कंपनियों इस बात को अनदेखा कर देती हैं। कि कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का दबाव न सिर्फ उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी शारीरिक सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। वर्कप्लेस स्ट्रेस को नियंत्रित करने का परिणाम किना भयावह हो सकता है, यह एना की दुखद मौत से यह तो स्पष्ट हो ही गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में लंबे समय तक काम के दबाव के चलते 7 लाख 45 हजार लोगों की मौत हो गई। 55 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने से स्ट्रेक का खतरा 35 प्रतिशत और कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 17 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। क्या कंपनियों का टॉक्सिक वर्क कल्चर कर्मचारियों की सेहत के लिए घातक हो सकता है? आज खासकर कॉरपोरेट जगत में कर्मचारियों पर काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि उनकी निजी जिंदगी और सेहत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। भारत जैसे देश, जहां वर्किंग ऑवर्स का औसत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, में कर्मचारी मानसिक और शारीरिक तनाव से जूझ रहे हैं। एना की मौत ने इस टॉक्सिक कल्चर को उजागर किया है, जहां कर्मचारियों को आराम और मानसिक शांति से वंचित किया जा रहा है। अक्सर युवा कर्मचारी अपने बांस या सीनियरों को काम के दबाव के बारे में बताते हैं हिचकिचाते हैं। डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए। एना की मौत ने सवाल खड़ा किया है कि क्या वर्कप्लेस पर तनाव और टॉक्सिक वर्क कल्चर को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियों की आवश्यकता नहीं है? जरूरी है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर को समाप्त किया जाए।

प्रकृति



पकज चतुर्वेदी

नहीं, बल्कि मौसमी तपिश लोगों को बेहाल किए हैं। यहां इस मौसम के तापमान से कोई 6.6 डिग्री अधिक गर्मी दर्ज की गई है और हालात लु जैसे हैं। कुपवाड़ा में 33.3, पहलगाम में 29.5 और गुलमार्ग में 23.6 तापमान असहनीय सा है। हिमाचल प्रदेश में सितम्बर के महीने में जून सी गर्मी है। ऊना समेत प्रदेश के पांच जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है।

संभलने का वक्त है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर सबसे संवेदनशील नैसर्गिक स्थल-हिमाचल की गोद में गहरा होता जा रहा है। गर्मी से लोगों की सेहत पर तो बुरा असर हो ही रहा है, लगातार गर्मी ने पानी की मांग बढ़ाई है और संकट भी। गर्मी से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता घटी है। प्लास्टिक बोतलों में बिकने वाला पानी हो या आम लोगों द्वारा सहेज कर रखा गया जल, तीखी गर्मी ने प्लास्टिक बोतल में उबले पानी को जहर बना दिया। पानी का तापमान बढ़ना तालाब-नदियों की सेहत खराब कर रहा है। एक तो वाष्पीकरण तेज हो रहा है, दूसरा पानी अधिक गरम होने से जल में विकसित होने वाले जीव-जंतु और

## बढ़ती गर्मी और दुश्वारियों का दौर

कांगड़ा, मंडी, चंबा और बिलासपुर में भी तापमान 35 डिग्री पर पहुंच रहा है। सामान्य तौर पर सितम्बर माह में हल्की सर्दी का दौर शुरू हो जाता है लेकिन इस बार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। शिमला में भी तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है जो सामान्य से कहीं अधिक है।

यह संभलने का वक्त है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर सबसे संवेदनशील नैसर्गिक स्थल-हिमाचल की गोद में गहरा होता जा रहा है। गर्मी से लोगों की सेहत पर तो बुरा असर हो ही रहा है, लगातार गर्मी ने पानी की मांग बढ़ाई है और संकट भी। गर्मी से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता घटी है। प्लास्टिक बोतलों में बिकने वाला पानी हो या आम लोगों द्वारा सहेज कर रखा गया जल, तीखी गर्मी ने प्लास्टिक बोतल में उबले पानी को जहर बना दिया। पानी का तापमान बढ़ना तालाब-नदियों की सेहत खराब कर रहा है। एक तो वाष्पीकरण तेज हो रहा है, दूसरा पानी अधिक गरम होने से जल में विकसित होने वाले जीव-जंतु और

वनस्पति मर रही हैं। तीखी गर्मी भोजन की पौष्टिकता की भी दुश्मन है। तीखी गर्मी में गेहूँ के दाने छोटे हो रहे हैं, और उनके पौष्टिक गुण घट रहे हैं। तीखी गर्मी में पका हुआ खान जसदी बुड़-सुड़ रहा है। फल-सब्जियां जल्दी खराब हो रही हैं खासकर गर्मी में आने वाले वे फल जिन्हें केमिकल लगा कर पकाया जा रहा है, इतने उच्च तापमान में जहर बन रहे हैं, और उनका सेवन करने वालों का बिल बढ़ रहा है।

इस बार की गर्मी की एक और त्रासदी है कि इसमें रात का तापमान कम नहीं हो रहा, चाहे पहाड़ हो या मैदानी महानगर, बीते दो महीनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक अधिक रहा है। खासकर सुबह चार बजे भी लू का अहसास होता है और इसका कुप्रभाव यह है कि बड़ी आबादी की नींद पूरी नहीं हो पा रही। खासकर स्लम, नालों आदि के किनारे रहने वाले मेहनतकश लोग उनींद से सारे दिन रहते हैं, और इससे उनकी कार्यक्षमता पर तो असर हो ही रहा है, शरीर में भी कई विकार जा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि वातानुकूलित संयंत्र से वे इस गर्मी की मार से सुरक्षित हैं, तो यह बड़ा भ्रम है। लंबे समय तक एयर कंडीशनर वाले कमरों में रहने से शरीर की नस-नाड़ियों में संकुचन, मधुमेह और जोड़ों के दर्द का खमियाजा ताजिंदगी भोगना पड़ सकता है।

मार्च-24 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने भारत में एक लाख लोगों के बीच सर्वे कर एक रिपोर्ट में बताया है कि गर्मी-लू के कारण गरीब परिवारों को अमीरों की तुलना में पांच फीसद अधिक आर्थिक नुकसान होगा



संस्कृत: अष्टौ प्रियेभ्यो वक्ष्ये जगत्कवचम् यौ, अथ अष्टौ अष्टौ वक्ष्ये त्वं त्वं कण-कण के वेषः इति वक्ष्ये कुर्वते यौ

# भंवर में फंसी सेबी चीफ

अपने मजबूत नेतृत्व और सुधारवादी रुख के लिए जानी जाने वाली भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच आरोपों के भंवर में पहले ही बुरी तरह फंसी हुई हैं लेकिन अब उनका संकट और भी बढ़ गया है। क्योंकि सरकारी खर्च पर संसदीय निगरानी रखने वाली लोक सेवा समिति (पीएसी) ने उन्हें और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को 24 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। अब पीएसी अमेरिकी शार्टसेलर हिंडनबर्ग रिस्क द्वारा बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों से सम्बन्धित सवाल पूछेगी। समिति के सदस्य अडाणी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के खिलाफ आरोपों की जांच में सेबी की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े करेंगे। लोक सेवा समिति के विपक्षी सदस्यों ने जहां माधवी पुरी को बुलाने की मांग की थी, वहीं भाजपा सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि पीएसी सेबी या किसी अन्य नियामक संस्था के प्रदर्शन की समीक्षा तभी कर सकती है जब संसद द्वारा वित्त का दुरुपयोग किया गया हो लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली टीएसी ने पहली छमाही के लिए 24 अक्टूबर की बैठक का एजेंडा पेश कर दिया है, जिसमें सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल है। सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ एक के बाद एक लगे वित्तीय कदाचार और हितों के टकराव के आरोपों से उनका और सेबी की विश्वसनियता खतरे में पड़ चुकी है।

पीएसी ने संसदीय कानून द्वारा बनाए गए निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा को एक विषय के रूप में शामिल किया है। आरोपों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग ने माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाए कि अडाणी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी पुरी और उनके पति की हिस्सेदारी है और यह भी कहा गया कि अडाणी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत है। इसके बाद एक और आरोप लगा कि माधवी पुरी ने अपने सात साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टंसी फर्म से भारी-भरकम कमाई करना जारी रखा जो किसी नियामक अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन था। अगस्त 2024 में जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने संकेत दिया कि माधवी पुरी के पास अडाणी समूह के संस्थापक के भाई विनोद अडाणी द्वारा नियंत्रित फंडों में व्यक्तिगत हिस्सेदारी थी। माधवी पुरी का संबंध बरमुडा और मॉरिशस जैसे टेक्स हैवन देशों में स्थित फंडों से था जिससे अडाणी की जांच में सेबी की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सेबी चीफ पर 2017 से 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 1680 करोड़ हासिल करने के आरोप लगाए थे।

कांग्रेस ने दावा किया था कि बुच ने सेबी चीफ रहते इतनी सैलरी नहीं पाई जितने उन्हें प्राइवेट बैंक से मिल रही थी। हालांकि बैंक ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बैंक उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहा था। यद्यपि माधवी पुरी और उनके पति सब आरोपों को निराधार बताते रहे हैं लेकिन तृणमूल सांसद महुआ मोड्रान ने माधवी पुरी के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उन्होंने अनुचित आचरण किया और भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालते हुए भ्रष्टाचार में शामिल हुई। महुआ ने जांच के लिए सीबीआई और ईडी को मामला भेजने की मांग की। संसद की लोक सेवा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मॉटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोक सेवा समिति को काफी अधिकार प्राप्त हैं। संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही शासन की धुरी है। संसद के जनप्रतिनिधियों की समिति जो लोक सेवाओं की जांच करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक सेवा समिति को अपना विवेक दिखाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह संसाधनों को बढ़ाने के बेहतर तरीके खोजने में मदद करती है।

कई दशकों से पीएसी का रिकॉर्ड सराहनीय रहा है। पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन और तीन भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी, पी.वी. नरसिम्हा राव और इन्द्र कुमार गुजराल ने भी अपनी सेवाएं पीएसी में दी हैं। क्योंकि केन्द्र सरकार में पिछले 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसलिए संसदीय समितियों में भी सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व रहा है। हालांकि अब दृश्य बदल गया है। विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा अधिक मजबूत है। 2जी घोटाले में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएसी के सामने पेश होने की पेशकश की थी। इससे पीएसी का महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर नियामक से उम्मीद की जाती है कि वह ईमानदार और निष्पक्षता से काम करेगा। अगर नियामक तंत्र ही भ्रष्टाचार का शिकार है तो निवेशकों के हितों की रक्षा कौन करेगा। भारत का पूंजी बाजार दुनिया के पांच शीर्ष बाजारों में से एक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन जुटाने का बड़ा माध्यम है। बाजार में आम लोगों के निवेश को देखते हुए यह जरूरी है कि सेबी की साख कायम हो। पीएसी को भी सेबी की कार्यप्रणाली को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। सेबी की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए ताकि नियामक तंत्र पर लोगों का भरोसा कायम हो।

आदित्य नारायण चोपड़ा  
Adityachopra@punjabkesari.com

## सच जेलों के अंदर घुटता है...

अब सच्चे लोगों का हाल कुछ यूं बेदर्द नजर आता है, सच जेलों के अंदर घुटता है और झूठ बेखौफ पैरोल पाता है, इस राजनीतिक उठा-पटता में अक्ष कौन किसका फुफादार बन पाता है, क्यों मतदाता हर बार के चुनाव के बाद खुद को ठगा हुआ पाता है...!!



गौता पाषा

## राकांपा नेता की चाकू घोंपकर हत्या

मुंबई, (भाषा) अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक नेता की दक्षिण मुंबई में अज्ञात लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि शुकवार देर रात भायखला के म्हाडा कॉलोनी इलाके में सचिन कुर्मी (43) पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि कुर्मी को जेजे अस्पताल

ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि हमले में दो से तीन लोग शामिल थे। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के लिए टीम गठित कर दी गयी है।

## 5 सितारा होटल में रथियन बाला संग पकड़े गए मंत्री जी



**मिर्च मसाला**  
त्रिदीव रमण  
gossipguru.in

‘उम्र ढल कर सफेद हुई हैं, पर न जाने बावरा मन क्यों अब भी अर्जियां लिखता है इश्क है, आग है, बदन है, तपन है इस पर भला कौन अपनी मर्जियां लिखता है?’



यह कोई दो रोज पहले की ही तो बात है जब कांग्रेस की उत्साही प्रवक्ता सुप्रिया श्रीसे ने एक्स पर एक प्रतीकात्मक पोस्ट करते हुए इशारा-इशारा में बताया, भाजपा-राजस्थान-दिल्ली-ली मेरिडियन-रूस तो सि या सी हलकों में स च मु च को ह रा म कर गया। रहीं सही क स र आर जे डी के हैंडल से डाली गई एक पोस्ट

ने पूरी कर दी जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा ही था। आइए अब मामले की तह में लौटते हैं। इस प्रदेश के इस उत्साही मंत्री जी के कहे-अनकहे किस्से से पूरा सोशल मीडिया अटा पड़ा है। हाल में ही एक ‘इन्वेस्टमेंट’ यात्रा का हवाला देते हुए मंत्री जी अपने कुछ मुंहलगे अधिकारियों के साथ कोरिया व जापान की यात्रा पर निकल गए, उस यात्रा में भी निवेश से कहीं ज्यादा इनके 75 हजार के जूतों व 35 हजार के चश्मे की चर्चा रही।

अभी पता नहीं चल पाया है कि मंत्री जी इन दोनों देशों से अपने संबंधित राज्य के लिए कितना विदेशी निवेश ला पाने में कामयाब रहे, पर मेहनत पूरी की उन्होंने। इतनी कि जंग लोट कर स्वदेश आए तो थक कर चूर हो चुके थे, सो तन-मन में नई स्फूर्ति जगाने की चाह में नई दिल्ली के एक चर्चित पंचतारा होटल में एक कमरा बुक करा एक चर्चित रथियन बाला की सेवाएं प्रारंभ कर लीं। संयोग से यह रथियन बाला कुछ कारणों से पहले से ही दिल्ली पुलिस के ‘सर्विलांस’ पर थी, सो बाला के पीछे-पीछे दिल्ली पुलिस भी मंत्री के कमरे तक पहुंच गयी और कक्षावर्तों के असाधार उन्हीं ‘रंगे हाथों’ पकड़ भी लिया गया, तब मजबूरन मंत्री जी को अपना परिचय उजागर करना पड़ा।

बात पुलिस कमिश्नर तक जा पहुंची, कमिश्नर साहब ने तुरंत सीएम ऑफिस में अपने एक परिचित अधिकारी को फोन कर पूछा-‘क्या यह वाकई राज्य का कोई मंत्री है?’ ‘जवाब हां’ में था। बात खुली तो दूर तक गई, राज्य के सीएम ने तुरंत फोन कर कमिश्नर साहब से मनुहार-कौ-प्लीज, पहचान उजागर मत करना, राज्य की बदनामी होगी पुलिस फाइल में ऐसा ही हुआ, पर खबरों के तो पंख होते हैं जाने किस रोशनदान से बाहर निकल कर उसने खुले आसमान में परभाव भर ली। बात भाजपा शीर्ष तक पहुंच गई है, ऊपर से आदेश प्राप्त होने के बाद श्री नड्डा ने भी राज्य के सीएम को तेल कर मंत्री जी का कात्ता चिटा कर सकने को

खरि-खरि बात  
-वीरेंद्र कपूर

पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमस द्वाारा महिलाओं और बच्चों सहित 1200 से अधिक इजराइली नागरिकों की नृशंस हत्या तथा 200 से अधिक इजराइलियों के अहपरण से शुरू हुआ युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा में हमस के आतंकियों पर और लेबनान में हमस के सहयोगी हिजबुल्लाह पर किए गए इजराइल के प्रतिरोधात्मक हमले से अब कहीं अधिक बड़ी आग भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। ईरान को 1 अक्टूबर को इजराइल के विरुद्ध 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के लिए दंडित किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि जब हमस ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइली रक्षा बलों (आईडीएफ) को आश्चर्यचकित कर दिया था और एक संगीत समारोह में आनंद ले रहे निर्दोष पुरुषों और महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी थी, तब से वह और उसका साथी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल की निरंतर गोलाबारी का शिकार बन रहे हैं।

अपनी शानदार खुफिया जानकारी के दम पर आईडीएफ ने अपने दुश्मनों पर बहुत बड़ी मार की है। लेबनान स्थित शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के कारिस्थानों ने हसन नसरल्लाह की हत्या से बड़ी कोई मार नहीं है, जिसने पिछले साल गाजा पर हमले के बाद से ही इजराइल को रॉकेट हमलों से परेशान कर रखा है। युद्ध में स्वयं उतरने के प्रति अनिच्छुक और लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों जैसे अपने समर्थकों को हथियार प्रदान करने ही संतुष्ट रह रहे ईरान को आश्चर्यचकित करने लगे हैं। युद्ध में स्वयं उतरने के लिए हमला करने के लिए बाध्य होना पड़ा लेकिन इस हमले के बाद भी ईरान की कमजोरी

कहा है, मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में मंत्री जी की छुट्टी हो जाए। पर मंत्री जी जिस गरीब व उपेक्षित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी उस वोट बैंक को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, सो जो भी होगा फूक-फूक कर कदम रखा जाएगा।

वैसे भी पार्टी हाईकमान को पता चला है कि मंत्री जी बहुत पहले से राज्य के सीएम के सिरदर्द बने हुए हैं। अपने कुछ पसंदीदा अधिकारियों का कांकस बना कर वे मोटी मलाई काट रहे हैं, उनका बार-बार की दुबई यात्रा को भी इसी संदर्भ से जोड़ कर देखा जा रहा है। जब सीएम को मंत्री जी के ‘उगाही अभियान’ का पता चला तो उन्होंने मंत्री जी के एक बेहद चहेते अधिकारी का उनके विभाग से बाहर ट्रांसफर कर दिया, पर मंत्री जी का जलवा देखिए अधिकारी की कुछ दिनों बाद ही उनके पुराने विभाग में वापसी हो गई। पर ताजा घटनाक्रमों में मंत्री जी की उद्दात भावनाओं की वापसी संभव नहीं लगती क्योंकि अबकि बार बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी में शुचिता व नैतिकता की भावना बनाए रखना चाहती है।

### पवन कल्याण : ग्वेरा से गोलवलकर तक

आंध्र की राजनीति में हिंदुत्व के नए पुरोधे बन कर उभरे हैं एक्टर पवन कल्याण, जो इतफाक से आंध्र के उप मुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अभी सोशल मीडिया पर तिरुपति बालाजी के लड़ु विवाद के बीचोंबीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जहां वे मंदिर की सीढ़ियां साफ करते नजर आ रहे हैं और चहूँ ओर उद्घोष हो रहा है ‘हिंदू खतरे में हैं!’

पवन पर ताजा-ताजा जा पिछले दिनों ‘विश्व हाथी दिवस’ पर एक पोस्ट सामने आया, जिसमें कहा है- भारत में हमारे लिए हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास के अभिन्न अंग हैं, यह बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। दरअसल एक अंग्रेजी दैनिक में रिपोर्ट छपी कि फरवरी 2024 में हर 5 साल बाद होने वाली हाथियों की गणना की रिपोर्ट तैयार होकर प्रिंट भी हो गई, पर इसे यह कहते हुए रिलीज नहीं किया गया कि नार्थ-ईस्ट से डटा आया ही नहीं। वैसे भी भारत में एक तिहाई हाथियों का आबादी नार्थ-ईस्ट में ही बसर करती है। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट को सांख्यिक न किए जाने के पीछे वे आंकड़े हैं जो चुगली खाते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हाथियों की आबादी 20 फीसदी तक घट गई है। अब उक्त दावे का क्या होगा?

उच्च स्तरीय संस्कृत-तेलुगु संस्कारों वाले हैं जो ज्यादातर कोनासीमा ब्राह्मणों की जाति है, पर इस क्षेत्र में कापू समुदाय का भी खासा दबदबा है। हालांकि यहां इस क्षेत्र में संघ भी काफी पहले से सक्रिय है, पर वह यहां स्थानीय तौर पर कोई बड़ा भगवा नेता उभार नहीं पाया है, कल्याण इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इन्हीं मौजूदा समीकरणों को देखते हुए ही उन्होंने अपना गुरु ग्वेरा से गोलवलकर कर लिया है।

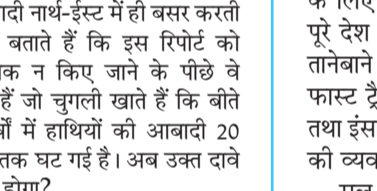
### नया सेबी चीफ कौन ?

मौजूदा सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर कांग्रेस ने चौतरफा हमला जारी रखा हुआ है, इसकी तपिश इतनी ज्यादा है कि भगवा शीर्ष के गिरावों पर भी सीसा है। संसद के शीकाकालीन सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां कर रखी हैं। केंद्र चाहता है कि कांग्रेस के तमाम हमलों को धत्ता बताते हुए बुच अपना कार्यकाल पूरा करें। व्हिसलब्लोअर हिंडनबर्ग ने माधवी व उनके पति धवल बुच के एक उद्योगपति

कनेक्शन पर स वा ल उठाए थे। कहते हैं एक उद्योग ग्रुप ने नए सेबी चीफ के लिए अपने एक बैंक के पूर्व अधिकारी का नाम चलाया है। समद रहे कि देश के एक बैंक ने इस उद्योग समूह को भारी कर्ज दिया हुआ है। आस्ट्रेलिया में कोयला खदान संचालित करने में दुनियाभर के पर्यावरणविदों के विरोध को देखते हुए जब कोई भी वित्तीय संस्था इस ग्रुप को लोन देने को तैयार नहीं थी तो ऐसे में उक्त बैंक इस समूह के लिए तारणहार बनकर आया और कर्ज देने को राजी हो गया। अब यही उद्योग समूह अपनी पसंद के सेबी चीफ के लिए डेट गया है।

### ...और अंत में

आंकड़ों के खेल में उलझाने में भाजपा का भी कोई सानो नहीं। अभी पिछले दिनों ‘विश्व हाथी दिवस’ पर एक पोस्ट सामने आया, जिसमें कहा है- भारत में हमारे लिए हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास के अभिन्न अंग हैं, यह बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। दरअसल एक अंग्रेजी दैनिक में रिपोर्ट छपी कि फरवरी 2024 में हर 5 साल बाद होने वाली हाथियों की गणना की रिपोर्ट तैयार होकर प्रिंट भी हो गई, पर इसे यह कहते हुए रिलीज नहीं किया गया कि नार्थ-ईस्ट से डटा आया ही नहीं। वैसे भी भारत में एक तिहाई हाथियों का आबादी नार्थ-ईस्ट में ही बसर करती है। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट को सांख्यिक न किए जाने के पीछे वे आंकड़े हैं जो चुगली खाते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हाथियों की आबादी 20 फीसदी तक घट गई है। अब उक्त दावे का क्या होगा?



आबादी नार्थ-ईस्ट में ही बसर करती है। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट को सांख्यिक न किए जाने के पीछे वे आंकड़े हैं जो चुगली खाते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हाथियों की आबादी 20 फीसदी तक घट गई है। अब उक्त दावे का क्या होगा?

## सूरत...एक अद्भुत अनुभव



**श्रीमती किरण चोपड़ा**  
उत्तरप्रदेश-पंजाब केसरी टैलेंट समारोह की चेरकर-बिहार-बिहार केसरी टैलेंट कवच मुख्य संतुलिका-चौधवार  
राष्ट्रीय-राष्ट्रीय समारोह प्रकलन, एकल संतुलिका-महाराष्ट्र लोक प्रकलन प्रकलन  
f/kiran Chopra01  
kiran Chopra@punjabkesari.com  
kiran Chopra@punjabkesari.com  
kiran Chopra@punjabkesari.com



अर्थात् जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। पिछले दिनों में एक जैन शिष्टमंडल के साथ तेरा पंथ के महान जैन संत आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन के लिए गुजरात के शहर सूरत गई थी। जैन समाज का अनुरोध आचार्य महाश्रमण जी के दिल्ली चार्टमस को लेकर था। दरअसल 2027 का चार्टमस दिल्ली में हो यह अर्ज करने के लिए जैन समाज के वरिष्ठों और प्रतिष्ठित प्रतिनिधि मुझे भी विशेष रूप से अपने साथ लेकर गए थे। मैंने जैन प्रतिनिधियों के स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखते हुए उनके साथ चलना स्वीकार किया था और स्लोगन दिया ‘दिल्ली से आए हैं दिल्ली लेकर जाएंगे’। आचार्य महाश्रमण जी ने 2027 का

दिल्ली चार्टमस स्वीकार कर लिया। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया है कि सूरत में जीवन बहुत ही अनुशासित, मर्यादित और उस संयम एवं धैर्यशीलता के साथ था जिसके लिए जैन समाज जाना जाता है। जिओ और जीने दो एवं अहिंसा परमो धर्म; सही मायनों में जैन धर्म का एक सबसे बड़ा मंत्र है जिसे वह जीवन में निभाते हैं। सामाजिक सुरक्षा को लेकर मेरी जहां कई जैन हस्तियों से बातचीत हुई तो वहां सब ने सूरत का उदाहरण दिया कि यहां रात के दो बजे भी महिलाएं सुरक्षित हैं। वे कहीं भी आ और जा सकती हैं। लोग भी बहुत मर्यादित हैं और महिलाओं की सबसे ज्यादा इज्जत करने वाले हैं। आज के जमाने में जब दिल्ली जैसे शहर में या देश के किसी भी हिस्से से महिलाओं के यौन शोषण या बलात्कार संबंधी खबरें सुनते हैं तो मन विचलित हो जाता है लेकिन हर किसी ने सूरत में नारी और सामाजिक सुरक्षा के मामले में दिल खोलकर नारी सुरक्षा और उसके सम्मान को प्राथमिकता की बात कही। लोगों ने बताया कि आजकल नगरात्रों में सूरत शहर में अनेकों स्थानों पर गरबा चल रहा है और ढाई-ढाई, तीन-तीन बजे तक डांडिया चलता है। लड़कियां और महिलाएं बेरोकटोक और बिना खौफ रात में आती-जाती हैं, इसे कहते हैं सुरक्षा। बिना किसी डर के वह कहीं भी आ-जा सकती हैं। नारी सुरक्षा के प्रति वहां लोगों के दिलों में सम्मान है। वहां पुलिस और अन्य सामाजिक संगठन हर कोई महिलाओं की बात सुनता है और उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। काश, यह सामाजिक सुरक्षा का मॉडल पूरे देश में सूरत जैसा हो जाए तो देश के सामाजिक रिश्तों और तानेबाने की सूरत भी बदल जायेगी। नारी अपराधों के मामलों में फास्ट ट्रैक व्यवस्था के बावजूद तारीख पर तारीख भी चलती है तथा इंसान सही वक्त पर नहीं मिल पाता और जल्दी न्याय दिलाने की व्यवस्था भी जरूरी है।

व्यव रूप से हम आर्य समाजी लोग हैं लेकिन मैं विशेष रूप से जैन समाज के समारोहों में बह-चढ़कर हिस्सा लेती हूं। आचार्य महाश्रमण जी स्वयं में एक बहुत ही सम्मानित, परमश्रधेय और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ परोपकार की मूर्ति हैं। बहुत ही संवेदनशील हैं। कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक जैन साध्वी कनक जी अस्पताल में भर्ती थीं और जैन संत आचार्य महाश्रमण जी भ्रमण पर थे लेकिन उन्होंने अपनी पैदल यात्रा का रूप बदला और जैन साध्वी कनक जी से उनकी कृपालक्ष्मी पूछने के लिए अस्पताल पहुंच गए। महिलाओं के प्रति सम्मान की यह भावना हर संत में नहीं है और अन्य बाबाओं के बारे में किस्से लोग अवश्य जानते होंगे। सच्चा संत वही है जो नारी सम्मान और सुरक्षा की बात करे और जैन समाज के संत विशेष रूप से आचार्य महाश्रमण जी अनुशासन, विनम्रता का एक बड़ा उदाहरण हैं जो राष्ट्र के दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे कहते हैं नारी का सम्मान लेकिन इस मामले में देश में नारी के प्रति पुरुषों की मानसिकता ही विकृत है जिसे बदलना होगा। सूरत से इस भावना को एक रोल मॉडल के रूप में परिभाषित करना होगा। सामाजिक सुरक्षा का सूरत एक सचमुच उदाहरणीय मॉडल है जिसे पूरे देश को आत्मसात करना चाहिए। धर्म सभी अच्छे हैं और करोड़ों लोगों को अपने-अपने धर्म में आस्था है। सभी धर्म अनुसरणीय हैं लेकिन जैन धर्म तो अपने आप में अद्वैतारीय है। जो जिओ और जीने दो के सिद्धांतों के साथ-साथ अहिंसा से दूर रहने और क्षमा की बात करते हुए इसे जीवन में उतारने का आह्वान करता है। इस दृष्टिकोण से नगरात्रे हों या अन्य धार्मिक पर्व सामाजिक सुरक्षा तो जीवन में होनी ही चाहिए और उसके लिए हर किसी को अपना योगदान ठीक ऐसे देना चाहिए जैसे आचार्य महाश्रमण जी दे रहे हैं।

## पंजाब भूजपा में विद्रोह के आसार

नई दिल्ली, (एनटीआई): पंजाब की भगवा सियासत में तृफान की आहट है। अगर भाजपा शीर्ष ने जल्दी से सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं लिया तो यहां भाजपा में दोफाड़ हो सकती है। एक उद्योग उद्योगि सिंह के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए नेताओं की बेचैन करवटें बता रही हैं कि वे कभी भी भाजपा छोड़ अपने पुराने घर की राह पकड़ सकते हैं। पर उनके समक्ष सबसे बड़ी दिक्कत

बस यही है कि उनकी पुरानी पार्टी अब उनके लिए पहले की तरह बाँधे फैलाए खंडी नहीं है। केप्टन साहब अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से एक तरह से सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं, उनकी पत्नी परणीत भी को इस लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से पराजय का स्वाद चखना पड़ा। भाजपा ने केप्टन के खास लोगों से जो वायदा किया था उसे पूरा करने में वह उत्सुक नहीं दिखती।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

### पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय:-  
फोन अधिकारि: 011-30712200, 45212200.  
प्रसार अधिकारि: 011-30712224  
सिखानुपुत्र विभाग: 011-30712229  
समाचारक्रीय विभाग: 011-30712292-93  
न्यूजीन विभाग: 011-30712330  
फैक्स: 91-11-30712290, 30712384.  
011-45212383, 84  
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड,  
2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्प्लेक्स, नजदीक  
वजीरोपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035  
के लिए युद्धक, प्रकाशक तथा सम्पादक  
अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग  
प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्प्लेक्स, वजीरोपुर,  
दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस  
कॉम्प्लेक्स, वजीरोपुर, दिल्ली से  
प्रकाशित।







# नक्सलियों का सफाया

छत्तीसगढ़ के अबुल्लागढ़ इलाके में तीस से अधिक नक्सलियों को मार गिराने में मिली सफलता इसका परिचायक है कि केंद्र और राज्य सरकार नक्सली संगठनों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का परिचय इससे मिलता है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अब तक 180 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। यह संख्या इसलिए उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों में दो सौ के करीब ही नक्सली मारे जा सके। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ कहीं अधिक सख्ती का परिचय दिया जा रहा है। वैसे तो पिछले कांग्रेस सरकार भी नक्सलियों के खिलाफ सक्रिय थी, लेकिन वह अक्सर ढुलमुल नजर आती थी और वह भी तब, जब नक्सलियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया था। यदि नक्सलियों से निपटने में वे उनके प्रति सख्त रवैया बनाना हो और उन्हें यह संदेश भी देना होगा कि वे बंदूक के बल पर व्यवस्था परिवर्तन करने और संबिधान एवं लोकतंत्र खत्म करने का मुगालता छोड़ दें। चूंकि नक्सली बार-बार के आग्रह के बाद भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने से इन्कार कर रहे हैं, इसलिए उनका दमन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। नक्सली नेता और उनके समर्थक भले ही यह झूठा प्रचार करें कि नक्सली संगठन गरीब आदिवासियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे आतंक के बल पर उगाही करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए हैं। तथ्य यह भी है कि वे जिन आदिवासियों के हितों को दिखाने का दिखावा करते हैं, उन्हें ही विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने का कुचक्र रचते हैं। वास्तव में वे निर्धन आदिवासियों के सबसे बड़े शोषक हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नक्सली संगठनों के खिलाफ जो सख्ती दिखाई गई है, उसके चलते एक बड़ी हद तक उनकी कमर टूटी है। इतना ही नहीं, उनके दायरे को सीमित करने में भी सफलता मिली है। उन्हें पूरी तरह निष्प्रभाव करने का अभियान चलते रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में यह देखने में आ चुका है कि सुरक्षा बलों के दबाव के चलते वे कुछ समय के लिए निष्क्रिय होकर फिर से अपनी ताकत जुटा लेते हैं। अब उन्हें फिर से संगठित और ताकतवर होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ की तरह उसके पड़ोसी राज्य भी नक्सलियों का खात्मा करने के लिए कमर कसें और केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग करें। ऐसा करके ही मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने के लक्ष्य को पाया जा सकता है। अब जब नक्सलियों की ताकत घटती जा रही है, तब यह देखने की भी जरूरत है कि उन्हें आधुनिक हथियार कहां से मिल रहे हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गत दिवस सुटभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास से एके-47 जैसे हथियार मिले हैं।

# बाढ़ की त्रासदी

बाढ़ से लोग फिर प्रभावित हैं, जो हर वर्ष को निर्यात बन चुकी है। तटबंध भी टूटे, घर, बाग-बगीचे भी नदियों की भेंट चढ़े। इस प्राकृतिक आपदा से लोग पूरी तरह परिचित हैं, हालांकि पूर्व व्यवस्था के कारण बहुत जगहों पर प्रभाव थोड़ा कम कहा जा सकता है, लेकिन इसकी मार से इस वर्ष भी लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। जलस्तर में हो रही कमी राहत की बात है, लेकिन कटाव का खतरा चिंता की बात है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान होकर गुजरने वाली कोसी और कमला बलान नदी को जद में हरिनाही गांव के दर्शन भर घर आ चुके हैं।

**बाढ़ जैसी आपदा को कैसे कम किया जाए, इस पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है।**

ये कुछ उदाहरण भर हैं। पश्चिम चंपारण में भी फसल लगे खेत कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। इस समय पर्व-त्योहार का समय भी है, सो बाढ़ इसके उत्साह पर पानी फेर रही है। लोग सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। बच्चों के स्कूल बूट गए हैं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए व्यवस्था की है। उन्हें राहत सामग्री आदि पहुंचाई जा रही है। इसमें स्थानीय तंत्र को और सजगता व गति लाने की आवश्यकता है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। बाढ़ के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। इसलिए इन जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और चुस्त करने की जरूरत है, ताकि किसी भी अग्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न नहीं हो पाए। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में आम जन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी है, ताकि पीड़ितों तक सहायता पहुंच सके। यह सराहनीय है कि कई जगहों पर वे मुस्लैवी से सहायता प्रदान भी कर रहे हैं। एक दूसरे की पीड़ा में सहायता के लिए दौड़ पड़ना ही बिहार का एक सकारात्मक भाव है, जिसमें समाज सहयोग के लिए खड़ा हो जाता है।

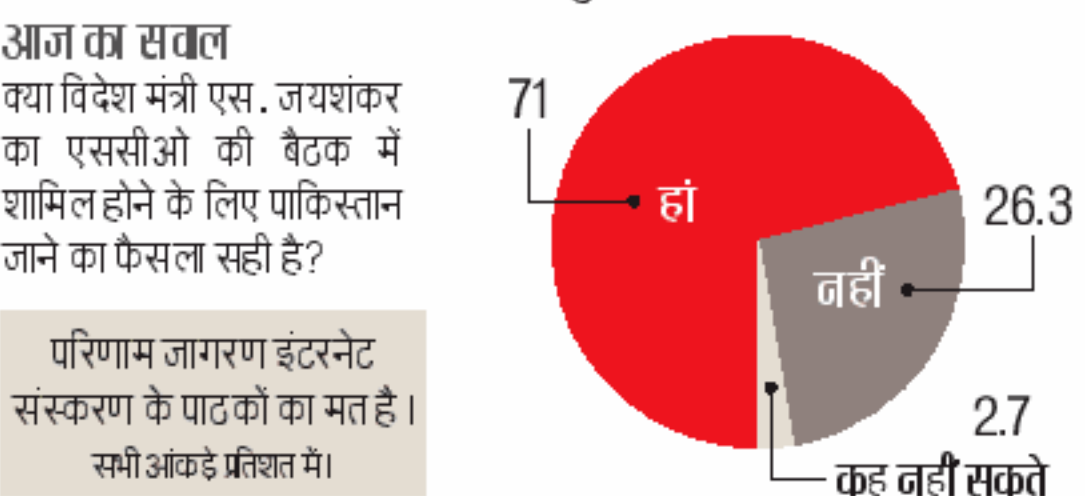
## कह के रहेंगे माघ जयी



**...लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपका पार्टी छोड़ना और संबिधान बचाने के लिए लौट आना वाकई साहसिक रहा।**

## जागरण जनमत कल का परिणाम

**व्या वैवाहिक दुष्कर को अपराध की श्रेणी में रखने से विवाह संस्था को नुकसान होगा?**



जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा संचालित मत संग्रहण (विचार/पु. बंगाल)-विद्युत प्रकाश रिपोर्ट, स्थानीय संपादक - अलोक मिश्रा \* दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073 E.mail : patna@patjagran.com, R.N. NO. BIHNN/2000/30397 \* इस अंक में प्रकाशित सम्पन्न सामग्री के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.एच. जी. एच.के. अंतर्गत उत्तरवर्ती पत्रिका जीपीसी रिपोर्ट, नं. R-10/NP-18/14-16 सम्पन्न विवाद पत्रिका चयन के अर्थ में होता है। वर्ष 25 अंक 175

# युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया



संजय गुप्त

**यदि पश्चिम एशिया के जलतल और खराब हुए तो इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में एह रहते लाखों भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़ सकती है**

इजरायल की ओर से हिजबुल्ला के सरगना नसरुल्ला को मार गिराए जाने और लेबनान में सक्रिय इस संगठन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के जवाब में ईरान ने उस पर मिसाइलें दागकर पश्चिम एशिया की हालत और अधिक बिगाड़ने का ही काम किया है। अब यह लगभग तय है कि इजरायल ईरान को निशाना बनाएगा। वह ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वह इजरायल का नाभौमिशासन मिटा देगा। इसकी भी प्रबल आशंका है कि इजरायल ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाएगा। यदि ऐसा होता है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ना तय है। इससे विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण संकट का सामना कर रही है। यदि यहाँ के हालात खराब हुए तो इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में रह रहे लाखों भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़

सकती है। स्पष्ट है कि इससे भी भारत की समस्याएं बढ़ेंगी।

पश्चिम एशिया तबसे तनाव और युद्ध की आशंका से घिरा है, जबसे पिछले साल सात अक्टूबर को फलस्तीन के गाजा इलाके में सक्रिय आतंकी संगठन हमला किया था। इस हमले में हमलासे आतंकीयों ने 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों को मार दिया था और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। इजरायल के लिए यह बहुत अधिक आघातकारी था। इजरायल ने हमलासे सबक सिखाने के लिए गाजा में हमलों की झड़ी लगा दी। इन हमलों में हमलासे के तमाम आतंकीयों के साथ आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार अब तक 40 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायल के हमलों के दौरान ही लेबनान के ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला ने भी इजरायली ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके चलते इजरायल ने हिजबुल्ला को भी निशाने पर ले लिया। इससे चिढ़कर ही ईरान ने इजरायल को अपना निशाना बनाया। ऐसा करके उसने इजरायल को खुद पर हमले का मौका दे दिया है। इजरायल के जवाबी हमले की आशंका से ग्रस्त ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भले ही इस्लामी जगत को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं और मुसलमानों को इजरायल के खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन यह सफ है कि कतर को छोड़कर अन्य इस्लामी देश और विशेष रूप से अरब जगत के सुन्नी देश इस संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं। इजरायल और इस्लामी देशों के बीच



अधेश राणव

अविश्वास और तनाव का रिश्ता नया नहीं है। इजरायल और इस्लामी देशों में तभी ठन गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 1948 में फलस्तीन कहे जाने वाले क्षेत्र में एक नए राष्ट्र के रूप में जुनिया भर में बिखरे यहूदियों के लिए इजरायल की स्थापना की गई। इजरायल से तमाम संघर्ष के बाद अधिकांश अरब देश इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ईरान और कतर जैसे देश अभी भी हमला और हिजबुल्ला के जरिये इजरायल को निशाना बनाने की नीति पर चल रहे हैं।

इजरायल और इस्लामी देशों के बीच तनाव और युद्ध के लंबे इतिहास के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हर हाल में इजरायल का साथ देना परसंद करते हैं। इन देशों ने पिछले एक साल में इजरायल और हमलासे के बीच संघर्ष विराम के लिए तमाम प्रयत्न किए, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि हमलासे बंधकों को रिहा करने

के लिए तैयार नहीं हुआ। इजरायल की ओर से ईट का जवाब पत्थर से देने की कठोर नीति अपनाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देश उस पर लगाम इसलिए नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है और ऐसा देश अपने शत्रुओं के प्रति नरम रवैया नहीं अपना सकता। इजरायल के आक्रामक रुख को देखते हुए विश्व के अनेक देशों की यह अपेक्षा उचित ही है कि वह संयम का परिचय दे, फलस्तीन को अलग देश के रूप में स्वीकारे और हमलासे पूर्व हिजबुल्ला जैसे संगठनों को हथियारों के बल पर खत्म करने का इरादा छोड़े, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब ईरान जैसे देश भी इस मुगालते से बाहर आए कि वे इजरायल का अस्तित्व मिटाने में सफल हो जाएंगे। ईरान इजरायल के लिए खतरा बने हमलासे और हिजबुल्ला का ही साथ नहीं देता, बल्कि सक्रिय अरब की नाक में दम किए यमन के हाउती लड़ाकों की भी सहायता करता है। यही काम कतर

# एक अदद सम्मान के लिए



**हास्य-व्यंग्य** वह एक सामान्य दिन नहीं था। मैं देर से सोकर उठा था। अभी अलसप्ता ही था कि खास मित्र का फोन आ गया। कुछ असामान्य घटित होता है तो वह पहली सूचना मुझे ही देते हैं। इस आशंका से मैं एकबारगी सहम उठा। मैंने उठते-उठते काल रिसीव की। उधर से मित्र की भारी सी आवाज कानों में पड़ी, 'यार, इस बार भी मिश्रा बाजी मार ले गया। न जाने साहित्य को कौन-सा ग्रहण लग गया है। साहित्य को गिरने से अब तो मैं भी नहीं बचा सकता।' यह कहकर उन्होंने गहरी सांस ली।



रंजित

**जब बड़े लेखक अपने सम्मान की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं तो आम जन की क्या स्थिति होगी? इस पर एक खेतपर आना चाहिए**

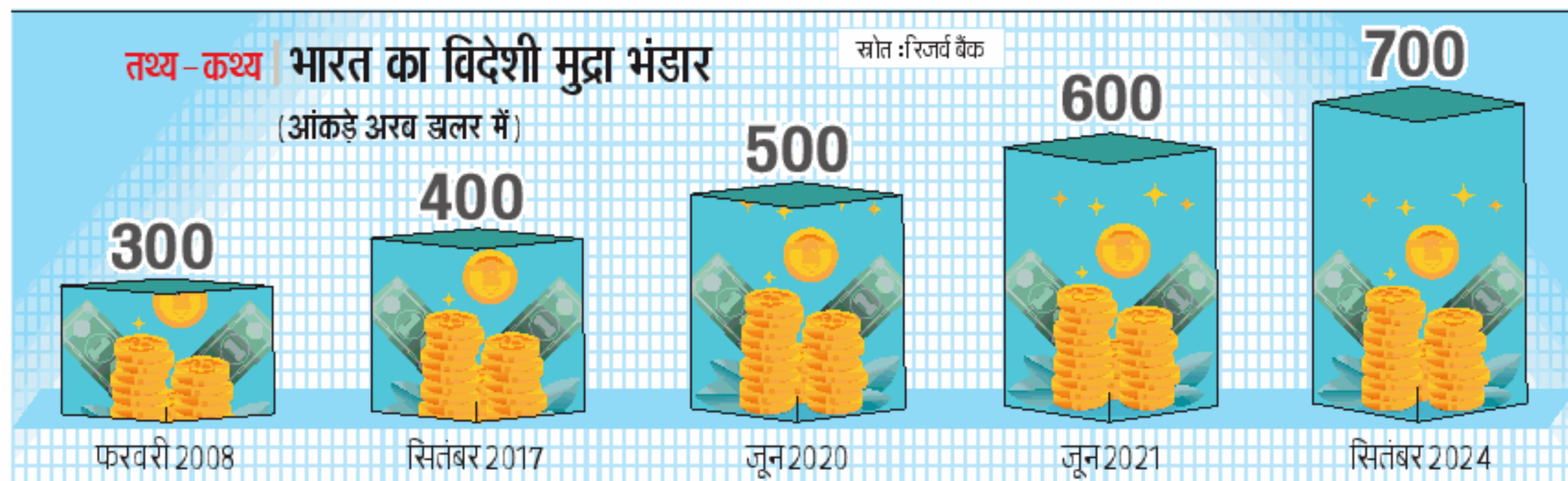
थी, सो बोल दिया, 'क्रिंतु यह हुआ कैसे? इस बार तो हमने सही फील्डिंग जमाई थी। चयनकर्ताओं की नियमित खैर-खूब भी रखते थे। एक की तो हवाई-टिकट के ऐसे हमों ने दिए थे और दूसरे के मोबाइल को भी बार-बार रिचार्ज कराया था। फिर भी! मुझे तो राकली पर संदेह है। वह मुझे से तबसे जलता है जबसे उसकी प्रेमिका से विवाह कर लिया। वह अभी तक भरे गले पड़ी है। मुझे कभी सम्मान नहीं नसीब हुआ, न जीवन में, न लेखन में। इस शुकला ने ही मुझे से प्रतिशोध लिया है।

'तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे ही अनजान और भोले बने रहोगे तो जीवन भर 'सम्मानहीन' का खिताब तुम्हारे पास ही रहेगा। इस बार बड़ा खेला हुआ है। आखिरी क्षणों में रस्तोगी और खन्ना खेल गए। तुम्हारा नाम काटने के लिए देवेंद्र मिश्रा के साथ चले गए, जबकि तुम्हें लाए थे इन्हें साहित्य में। जब दोनों कहानी में नहीं घुस पाए तो कविता का दरवाजा खटखटाया। वहाँ भी दाल नहीं गल पाई तो समीक्षक बन गए। अब ये ही तुम्हें सिखा रहे हैं। रही बात चयनकर्ताओं को सधने की, वहाँ

भी मिश्रा तुमसे बाजी मार ले गया। एक के बेटे को आहूपाएल में सेलेक्ट करा दिया और दूसरे की बेटी के विवाह में खान-पान का पूरा प्रबंध किया। इसे कहते हैं मैंनेजमेंट। अब शायद तुम्हें अक्ल आए।' इतना कहकर उन्होंने आखिरी से बहुत पहले वाली सांस ली।

मुझे 'अटैक' आते-आते बचा, बिल्कुल 'सम्मान' की तरह। मेरी कहीं भी पूछ नहीं है। एक उसे देखो। कल का आया हुआ लड़का है। कभी संघर्ष नहीं किया। आते ही छा गया। साहित्य में अंधेरा उसी की वजह से है। एक हम हैं कि पहले दिन से ही संघर्षरत हैं। पहले छपने के लिए किया, अब सम्मान के लिए कर रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि लिखने से ज्यादा पैतरे आने चाहिए। मेरे पास तितन बजट था, उसमें कोई ढंग का पैतरा हो भी नहीं सकता था। यह लगातार तीसरी बार हुआ है जब मेरा सपना टूटा है। कवि पाश ने कहा भी है, 'सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का टूट जाना।' निश्चित ही उन्हें मेरी दशा का पूर्वानुमान हो गया होगा। यह भी कोई लोकतंत्र है? एक ही आदमी सारे सुख लिए जा रहा है। कोई कब तक संघर्ष करेगा भाई! हम जैसे बड़े लेखक अपने सम्मान की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? इस पर भी एक श्वेत-पत्र आना चाहिए।' मैंने मन ही मन में कहा। 'अब ज्यादा सोचो नहीं, दिल्ली का एक हवाई-टिकट बुक कर दो। इस मिश्रा का तोड़ तलाशता हूँ।' इतना कहकर बिना मेरा जवाब सुने उन्होंने फोन काट दिया। मुझे इस बार भी अटैक नहीं आया।

response@jagran.com



## मंत्री पद का प्रचार

हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता की आस लगाए बैठी है और कांग्रेस इस बार अपनी बारी का दावा कर रही है। इस बीच दोनों दलों के कई ऐसे उम्मीदवार हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ें तो अच्छा, लेकिन चाहते थे कि नेतृत्व से थोड़ा बल मिल जाए, तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी।

चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे उम्मीदवारों ने अपने-अपने दल के बड़े नेताओं पर बार-बार यह दबाव बनाने की कोशिश की कि प्रचार मंच से वे इतना भर घोषित कर दें कि जीत गए तो मंत्री बनाए जाएंगे। उम्मीदवार उन्हें यह भरोसा देते थे कि इतना भर बोल देने से वे चुनाव जीत जाएंगे। दरअसल कई चुनावों में इसका असर दिखा भी है, लेकिन बड़े नेताओं को इसका अहसास तो होता ही है कि कहां बोलना है और कहां नहीं।

## राजनीति की उलटबांसी

कर्नाटक के नेताओं का तो जलवा ही अलग है। बोलने पर आ जाएं तो कुछ भी बोल सकते हैं। अनुशासनहीनता या बेवजह बयानबाजी पर सामान्यतया हर्षकमान से नीचे के नेताओं को चेतावनी मिलती है, लेकिन कर्नाटक में उलटा भी हो रहा है।

## राजरंग

भाजपा के विधायक बसन्तगोड़ा पाटिल यतनाल ने हाल में हाईकमान को ही अल्टीमेटम दे दिया कि दिसंबर तक प्रदेश अध्यक्ष बदल दें, वरना वह कुछ निर्णय ले लेंगे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने साथ कुछ और विधायकों के होने का भी जिक्र कर दिया है। इसमें शामिल अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, फिर भी वह अल्टीमेटम देने की हिम्मत दिखा रहे हैं।

## जलेबी का जलवा

यूं तो आज के दौर में राजनीति पर समाज में कड़वाहट घोलने का ही आरोप है, लेकिन मोटे का व्यापार करने वालों की शिकायत शायद कुछ कम हो गई होगी। जलेबी बनाने वाले तो जरूर नेताओं के शुकुगुजार होंगे। बीते दिनों हरियाणा में राहुल गांधी ने जलेबी को एक्सपोर्ट करने का बिजनेस आइडिया दे डाला। भगवा खेमे वालों ने उलझी जलेबी का वह छोर पकड़कर सियासी तड़का लगा दिया कि गरम-गरम खाई जाने वाली जलेबी के एक्सपोर्ट का क्या तुक? जब आंच वरिष्ठ नेता के ज्ञान पर आई तो सियासी वार के लिए तथ्यों की तलाश में दुब्रे रहने वाले कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जलेबी बनाने की विधि, फैक्ट्री में उसके निर्माण और कौन-कौन से ब्रांड किस तरह की जलेबी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके शोध में दुब्र गए। फिलहाल इंटरनेट मीडिया पर जलेबी के ब्रांड छाप हुए हैं और नेता

'पाक कला विशेषज्ञ' बने दिख रहे हैं।

## मंत्री जी की क्लास

अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में लेने वाले मंत्रियों और नेताओं को फिलहाल जयंत चौधरी से सीखने की जरूरत है। जो मंत्रालय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब खुद ही मैदान में उतर गए हैं। दरअसल उनके पास जिन दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, उनमें कौशल विकास और शिक्षा है। इनमें शिक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों साक्षरता के शत प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2030 तक देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना है। इस अभियान में कोई भी स्वेच्छिक रूप से जुड़कर निरक्षर लोगों को पढ़ाने में मदद दे सकता है। ऐसे में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने युवाओं से इससे जुड़ने की अपील के साथ खुद आगे बढ़कर निरक्षर लोगों को पढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने पोर्टल पर पूर्वी दिल्ली के साक्षरता केंद्र के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। जल्द ही वह निरक्षर लोगों को पढ़ाते हुए दिखेंगे। देखना होगा कि मंत्री जी की क्लास में किस-किस को पढ़ाने का मौका मिलता है।

## पोस्ट



हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा में ऐसे कई नेता हैं, जो खुल कर कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वे मुख्यमंत्री बनें, लेकिन हाली अनुभव बताता है कि मुख्यमंत्री वह नहीं बनता, जो जोर-शोर से इसका उका पीटा है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश की जेलों तक में जातिभेद के आधार पर काम बंटवारा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ सख्त फैसला दिया है। क्वार्ड।

फैलाश सत्यार्थी@k\_satyarthi

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने इतिहास में पहली बार 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। जब दुनिया में खलबली मची हुई है, तब भारत सरपट विकास के पथ पर दौड़ रहा है।

बालियान@Baliyan\_x

गृह मंत्रालय ने अरबबारों में डिजिटल अरेस्ट पर जागरूकता के लिए फुल पेज विज्ञापन दिया है। यह नई टेक्नोलॉजी की बदलती चुनौतियों का परिचायक है। सरकारी को साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा।

सुधीर चौधरी@sudhirchaudhary

## जनपथ

इजरायल-ईरान या रूस और यूक्रेन, क्यों खराब है आजकल इन देशों का त्रेण? इन देशों का त्रेण विश्व को नर्क बनाए, चाह रहे थे रिड्ड सड़े शव पर मंडराएं! छेड़ रहें ईरान थोक में दाम मिशाइल, क्यों बैठेंगे शत भला यूएस-इजरायल!!

- ओमप्रकाश तिवारी

चंद्रमा ने कहा, आपके कारण ही मानव जाति लुप्त हुई थी और अब आपको ही उस भूल का परिमार्जन करना होगा। इसके लिए आप दसों प्रचेतस भाइयों को मारिशा से विवाह करके पृथ्वी को पुनः आबाद करना होगा।



## एक स्त्री ने किया दस पुरुषों से विवाह

पृथु के प्रपौत्र प्राचीनवर्हि का विवाह समुद्र की कन्या से हुआ था। उनके दस पुत्र हुए, जो सामूहिक रूप से 'प्रचेतस' कहलाते थे। वे सब विष्णु के भक्त थे। जल्द ही, प्राचीनवर्हि के सामने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का समय आ गया। परंतु प्रचेतस में से कोई भी यह उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं था। उन सबने यही कहा, 'नारायण का आह्वान करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है।' प्राचीनवर्हि निरंतर प्रचेतस से आग्रह करता रहा। आखिर प्रचेतस ने एक प्रस्ताव रखा। वे बोले, 'हम नारायण का आह्वान करेंगे। यदि उन्होंने हमें शासन करने की अनुमति दी, तो ठीक है अन्यथा हम अपनी आध्यात्मिक खोज जारी रखेंगे।' प्राचीनवर्हि ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

प्रचेतस भाई नारायण की साधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या के दस हजार वर्ष बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने प्रचेतस को कहा, 'महान राजा पृथु के वंशज होने के नाते शासन करना आपका कर्तव्य है।' प्रचेतस भाइयों ने देखा कि उनके चारों ओर केवल घना जंगल था। कई दिनों तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। हर जगह फर्कंद उग आई थी। तब सूर्य ने प्रचेतस भाइयों को बताया कि जिन दिनों वे तपस्या में लीन थे, पृथ्वी शासक विहीन हो गई और सभ्यता का अंत हो गया। भूलोक पर हर जगह वनस्पति उग आई है। यह सुनकर प्रचेतस हाथ पकड़कर एक वृत्त बनाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने मुख खोल दिए। उनके मुँह से प्रचंड ज्वाल निकली, जिसने सारे वृक्ष जला डाले। तभी उन्होंने सुना कि चंद्रमा उनसे रुकने की विनती कर रहा था। उसने कहा, 'मैं वनस्पति का पोषण करता हूँ। आपको अनुपस्थिति के कारण सब ओर जंगल उग आए हैं। परंतु इसमें वन का दोष नहीं है। उन्हें जलाना अनुचित है।'

किंतु प्रचेतस भाइयों ने चंद्रमा के आग्रह को नहीं माना। वे बोले, मानव जाति के विलुप्त होने के बाद, उनके लिए प्रजनन करना संभव नहीं है। उनकी मृत्यु के साथ मनुष्यता का अंत हो जाएगा। इसलिए वे सब नष्ट कर रहे हैं।

तब चंद्रमा ने कहा, 'तब भी आपका वंश समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब भी एक प्राणी जीवित है। वही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा।' प्रचेतस भाइयों ने किसी की आहट सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा, तो पाया कि पीछे एक स्त्री खड़ी थी।

'यह कौन है?' प्रचेतस ने चंद्रमा से पूछा। 'इसका नाम मारिशा है। यह महर्षि कंडू की पुत्री है। ऋषि कंडू और एक अप्सरा के संयोग से मारिशा का जन्म हुआ था। अप्सरा से उत्पन्न होने के कारण यह जीवित बच गई और वृक्षों ने ही इसका पालन-पोषण किया है। सृष्टि ने मारिशा को वचाकर आपके वंश की रक्षा की है। इसी के गर्भ से मनुष्य पुनः जन्म लेंगे। भूलोक ने अपनी भूमिका निभाई और अब आपको भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। आपके कारण ही मानव जाति लुप्त हुई थी और अब आपको ही उस भूल का परिमार्जन करना होगा। इसके लिए आप दसों प्रचेतस भाइयों को मारिशा से विवाह करके पृथ्वी को पुनः आबाद करना होगा।'

तब मारिशा ने कहा, 'पूर्वजन्म में मेरा विवाह एक राजा से हुआ था। योगप्रसन्न होने के कारण राजा की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। फिर मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनसे दो वरदान मांगे। एक, मेरा पुत्र ब्रह्मचर्यव्रत जैसा हो, और दूसरा यह कि मुझे अगले दस जन्मों में दस स्वयंवर पति मिलें। ईश्वर ने मुझे पहला वरदान प्रदान कर दिया, किंतु दूसरे में थोड़ा संशोधन कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि एक ही जीवन में मेरे दस पति होंगे। आपके माध्यम से वह दूसरा आशीर्वाद भी सत्य हो गया है।' चंद्रमा ने मारिशा से कहा, 'आपका पुत्र सचमुच ब्रह्मचर्य के समान होगा, क्योंकि वह स्वयं सृष्टिकर्ता का पुत्र होगा। उसे दक्ष कहा जाएगा। प्रचेतस भाइयों से आपके संयोग के फलस्वरूप, प्रजापति दक्ष का जन्म होगा।' दत्तानल और तूफान भी रुक चुका था। इस तरह दसों प्रचेतस भाइयों ने मारिशा से विवाह कर लिया और सृष्टि के विस्तार का कार्य आगे बढ़ाया।

दोस्तों तक सांस्कृतिक प्रसारण की जटिल व्यवस्था में गहरी दिलचस्पी जगाती है। किताब यह भी बताती है कि कैसे भारतीय नाविकों ने उच्च गति वाले मोटरखे के समुद्री समकक्ष तैयार करने के लिए मानसून के अपेक्षाकृत पूर्वानुमानित पैटर्न का उपयोग करना सीखा। यह वह दौर था, जब भारत और अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच लोग इतनी तेजी से यात्रा कर सकते थे कि अफगानिस्तान में धार्मिक चतलने वाले अंडों के कारवां को भी शर्म आ जाए। 'गोल्डन रोड' में एक चीनी विश्व जुआनजंग का भी वर्णन है, जिसने 6,000 मील की यात्रा कर 17 वर्ष भारत में विताकर बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल की। किताब का मुख्य विषय उत्तर मध्य काल यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के इर्द-गिर्द घूमता है, जब हिमालय द्वारा मानसून की खोज की गई थी और जो लाल सागर और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से व्यापार को गति प्रदान करता था। ऐतिहासिक घटनाओं को डेलरिपल ने कहाँ के रूप में पेश कर किताब को पठनीय बना दिया है।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य और जानवर ही बातचीत करते हैं। शोध बताते हैं कि पेड़-पौधे न सिर्फ बातचीत करते हैं, बल्कि आसन्न खतरे की स्थिति में जड़ों, विद्युत संकेतों, भूमिगत कवक और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के नेटवर्क के माध्यम से अपने साथियों को कुरालता से संदेश भेज सकते हैं।

## पेड़-पौधों का भी अपना इंटरनेट होता है



पेड़-पौधों के बीच ज्यादा संचार जमीन के नीचे होता है, जिसे 'वुड वाइड वेब' कवक नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया जाता है। माना जाता है कि 80 फीसदी से अधिक पौधे आपस में जुड़े हुए हैं।

आज सुबह मेरी छह साल की बेटी हमारे शयन-कक्ष में आई और एक किताब से कहानी पढ़ने लगी। वह एक-एक शब्द पढ़ते हुए पूरा वाक्य बना रही थी। कभी-कभी वह अटक जाती थी और कुछ मजेदार शब्दों को समझने के लिए मदद मांगती थी, लेकिन किताब खत्म करने के बाद उसने हमें बर्फ में फंसे एक भालू की कहानी सुनाई। मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है, चाहे वह किसी बच्चे के साथ हो, बुजुर्ग के साथ हो, किसी अपने के साथ हो या फिर अजनबी के साथ। मुझे लगता है कि मनुष्य एक प्रजाति के तौर पर इसलिए ही कामयाब हो सका, क्योंकि वह बातचीत कर सकता है। खतरा आने पर वह बोलकर चेतावनी दे सकता है और जटिल सूचनाओं का भी आदान-प्रदान कर सकता है। जानवर भी ये काम करते हैं। भले ही हम उनकी बोली न समझ पाएं, लेकिन उनके समूह के दूसरे जीव उस आवाज को समझ लेते हैं।

लेकिन क्या आपको पता है कि मनुष्यों और जानवरों की तरह पेड़-पौधे भी, जो भले ही निष्क्रिय लगते हों, बातचीत करते हैं। यह विचार कोई नया नहीं है। कुछ वर्ष पहले आई हॉलीवुड की फिल्म 'अवतार' के लिए भी पेड़-पौधों की यही शक्तियाँ प्रेरणा बनी थीं। लेकिन विज्ञान कहता है कि वनस्पतियों के बीच होने वाली यह बातचीत हमारी कल्पना से भी जटिल हो सकती है। दरअसल, ये पर्यावरणीय संवाद वेहद संवेदनशील और संतुलित होते हैं। कल्पना करें कि अगर वैश्विक नेटवर्क सिस्टम अचानक टूट जाए, तो हमारी दुनिया कितनी अस्त-व्यस्त हो जाएगी। यही बात पौधों के मामले में भी लागू होती है। यह समझने के लिए कि जो जीव बोल नहीं सकते, वे एक-दूसरे को सूचना कैसे देते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों में एक मूक संचार प्रणाली भी होती है। इसमें हमारी दृष्टि, गंध, श्रवण, स्वाद और स्पर्श की भावना शामिल है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक गैस कर्बोनाइट्रस गैस में मरकेप्टन नामक रसायन मिलती है, जिससे दुर्गंध में 'सड़े अंडे' जैसी गंध आती है, जो हमें रिसाव के बारे में चेतावनी देती है। यह भी सोचें कि हमने सांकेतिक भाषा कैसे विकसित की, जबकि कई लोग हॉटों की भाषा भी समझ लेते हैं। इन इंद्रियों के अलावा, हमारे पास संतुलन और शरीर की मुद्रा बनाए रखने की क्षमता, शरीर के अंगों की सापेक्ष स्थिति और ताकत का बोध, तापमान में बदलाव का बोध और दर्द को महसूस करने की क्षमता भी है। पौधे सूचना प्रसार के लिए अपनी इंद्रियों का

उपयोग अपने तरीके से करते हैं। हममें से ज्यादातर लोग ताजा कटी घास को गंध से परिचित हैं। घास के पौधों द्वारा छोड़े जाने वाले वाष्पशील या रासायनिक पदार्थ, जिन्हें हम उस गंध से जोड़ते हैं, एक तरीका है, जिससे वे आसपास के दूसरे पौधों को बताते हैं कि कोई शिकारी (लॉनमूवर) मौजूद है, जिससे पौधे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बदलाव करते हैं। श्रवण संकेतों का उपयोग करने के बजाय पौधे रासायन-प्रेरित संचार का उपयोग करते हैं। हालांकि, पौधों का संचार वाष्पशील पदार्थों तक ही सीमित नहीं होता है। हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधे आपस में कितने बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं और वे अपनी जड़ों, विद्युत संकेतों, भूमिगत कवक और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के नेटवर्क के माध्यम से अपने साथियों को वेहद कुरालता से संदेश भेज सकते हैं।

पौधों के आसपास की निगरानी करने वाली गंध की खोज की गई। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक अपेक्षाकृत नया वैज्ञानिक अनुशासन है, जो अध्ययन करता है कि पौधों में और उनके साथियों के बीच विद्युत संकेतों का संचार कैसे किया जाता है। प्रीयोगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की प्रगति के साथ हमने पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान के इस क्षेत्र में त्वरित विकास का अनुभव किया है। वैज्ञानिक उल्लेखनीय खोजों के कगार पर हैं, क्योंकि हाल ही में हुई प्रगति के कारण आधुनिक ग्रीनहाउसों में पौधों के भीतर और उनके बीच विद्युत संकेत संचार को एकीकृत किया जा सका है, जिससे फसलों की सिंचाई पर निगरानी और नियंत्रण किया जा सकेगा या पौष संक्षेपी कामियों का पता लगाया जा सकेगा। वैज्ञानिक एक्यूंपेक्वर सुर्यों के समान छोटे विद्युतीय जांच उपकरणों को डालकर यह जांच करते हैं कि विद्युतीय संकेतों में परिवर्तन, पौधों के प्रदर्शन से किस प्रकार जुड़े हैं, जैसे कि जल, पोषक तत्वों का परिवहन और प्रकाश को महत्वपूर्ण शर्कराओं में परिवर्तित करना। शोधकर्ताओं ने मोबाइल फोन से विद्युत संकेत भेजकर पौधों के व्यवहार को भी प्रभावित किया है, जिससे वे बीनस फ्लाइटपैट में पतियों को खोलने या बंद करने जैसी बुनियादी प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। जल्द ही हम अपनी फसलों की भाषा को पूरी तरह समझने में सक्षम हो जाएंगे।

पौधों के बीच बहुत ज्यादा संचार जमीन के नीचे होता है, जिसे 'वुड वाइड वेब' नामक बड़े कवक नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया जाता है। कवक का यह नेटवर्क पेड़-पौधों को जमीन के नीचे जोड़ता है, जिससे वे पानी, पोषक तत्व और सूचना जैसे संसाधन साझा करते हैं। इस प्रकृति के जरिये पुराने पेड़ छोटे पेड़ों को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और कौटों जैसे खतरों के बारे में एक-दूसरे को चेतावनी दे सकते हैं। यह पेड़-पौधों के लिए एक भूमिगत इंटरनेट की तरह है, जो उन्हें एक दूसरे का समर्थन करने और एक-दूसरे से संवाद करने में मदद करता है। यह नेटवर्क व्यापक है, माना जाता है कि 80 फीसदी से अधिक पौधे आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी संचार प्रणालियों में से एक बनाता है। इंटरनेट की तरह ही कवक नेटवर्क पौधों को पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए तैयार होने की खातिर सहजीवी कवक का उपयोग करने की अनुमति देता है।

हालांकि, मिट्टी में रसायनों की मिलावट, वनों की कटाई या जलवायु परिवर्तन के चलते इन नेटवर्कों में पानी और पोषक तत्वों के चक्र प्रभावित होने के कारण संचार बाधित हो सकते हैं, जिससे पौधे कम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और आपस में कम जुड़े रहते हैं। इन नेटवर्क को बाधित करने के प्रभावों पर अभी तक बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है। लेकिन संचार में बाधा उन्हें अधिक असुरक्षित बना सकती है, जिससे दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र को रक्षा और उसे बहाल करना ज्यादा कठिन हो सकता है। बच्चों की मदद करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह सुनिश्चित करना कि हम पौधों के बीच संचार को बाधित न करें। आखिरकार, हम अपनी भलाई और अस्तित्व के लिए पौधों पर ही निर्भर हैं।

## डॉल्फिन से सीखें सामाजिकता का पाठ

कौन है जो सूर्य किरणों को देखकर प्रसन्न नहीं होता? *नेयधीयचरितम* में श्रीहर्ष सूक्त व उषा का मनोरम वर्णन करते हैं- अरुणकिरणो वहनी लाजानुडूनि जुहोति या, परिणयति तां संध्यामेतामवैमि मणिर्दिवः। इयमिव स एवाग्निभ्रान्तिं करोति पुरा यतः, करमपि न कस्तस्यैवोक्तः सकौतुकमीक्षितुमा॥

सूर्य उषा से विवाह कर रहे हैं, जो तारों को भुने हुए चावल के रूप में अग्नि (सूर्य के तेज) में आहुति रूप से अर्पित कर रही है। जैसे वह सूर्य के फेरे लेगी, वैसे ही सूर्य भी अग्नि के चारों ओर फेरे लेंगे। ऐसा कौन है, जो उसके हाथ पर बंधे वैवाहिक धागे को देखने के लिए उत्सुक नहीं है?

प्रस्तुति: शास्त्री कोसलेंद्रवदास

क्या आपने कभी डॉल्फिन के समूह को एक साथ तैरते हुए देखा है? उनके बीच का तालमेल समर्पित करने वाला होता है। इससे उनके मन की भीतरी व्यवस्था का भी पता चलता है। वे उदास हैं या दुखी, उत्साहित हैं या नीरस, ये सब उनकी सामूहिक तैराकी में झलकता है। जैसे मनुष्य आशावादी और निराशावादी होते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। हाल के अध्ययनों से तो यही पता चलता है कि कुछ जानवर बाहरी और भावनात्मक स्थिति के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक फैसले ले सकते हैं। इस घटना को संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इसका प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। इसमें सबसे पहले पशु को सिखाया जाता है कि कुछ संकेत प्रकट होने पर क्या होगा। मसलन, अगर हम कमरे के बाएं कोने में एक कटोरा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। जब कटोरा दाएं कोने में होता है, तो इसका मतलब है कि उसे



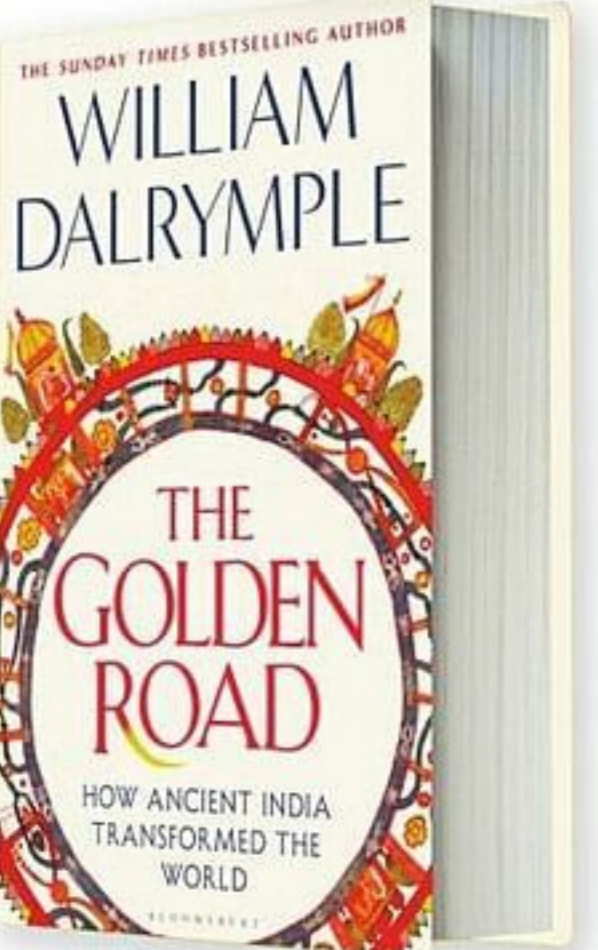
इसाबेला क्लेम

डॉल्फिन के समूह को तैरते देखना मोहित करता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान अचंचित भी करता है।

कोई इनाम नहीं मिलेगा, या कुछ बुरा होगा। ताकिक रूप से, जानवर सकारात्मक संकेत की ओर तेजी से भागेगा और नकारात्मक संकेत की ओर बहुत धीमे। कटोरे को कमरे के बीच में रखने पर अगर कोई जानवर कटोरे की ओर तेजी से दौड़ता है, तो उसे ज्यादा 'आशावादी' माना जाता है, क्योंकि उसे अज्ञात घटना से कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद होती है। हालांकि, इन परीक्षणों को पहले कभी डॉल्फिन पर नहीं आजमाया गया था। मैंने यह पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया कि क्या डॉल्फिनों में भी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होता है। हमने आठ डॉल्फिनों को लक्ष्य को छूकर वापस लाटना सिखाया। डॉल्फिनों ने

सीखा कि अगर लक्ष्य को पूल के एक तरफ रखा जाए, तो उन्हें उनकी पसंदीदा मछली मिलेगी। अगर लक्ष्य पूल की दूसरी तरफ होगा, तो उन्हें सिर्फ प्रोत्साहन ही मिलेगा। परिणामों से पता चला कि वास्तव में डॉल्फिनों में आशावाद और निराशावाद के स्तर अलग-अलग थे। लेकिन सबसे दिलचस्प जानकारी यह मिली कि डॉल्फिन हर परिस्थिति में सामाजिक व्यवहार में संलग्न होती हैं। हमने देखा कि जो डॉल्फिन बार-बार एक साथ तैरती थीं, वे सबसे अधिक आशावादी निर्णय भी लेती थीं। चार महीनों तक रोजाना अध्ययन के बाद हमने पाया कि आशावाद के स्तर भावनात्मक स्थितियों से जुड़े हैं। भावनात्मक स्थितियाँ संभवतः समूह के भीतर होने वाले सकारात्मक सामाजिक व्यवहार से प्रेरित होती हैं। इसे अध्ययन के अनुसार, तालमेल पूर्ण तैराकी के स्तर का उपयोग भावनात्मक स्थिति के संकेतक के रूप में किया जा सकता है, और इस प्रकार यह जानवरों की सामाजिक विश्वसिलता की निगरानी और सुधार करने में मदद कर सकता है।

अध्ययन कक्ष  
द गोल्डन रोड हाउ एन्वांट इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ल्ड  
लेखक: विलियम डेलरिपल  
प्रकाशक: ब्लूस्ववरी मूल्य: 999 रुपये  
हार्डकवर



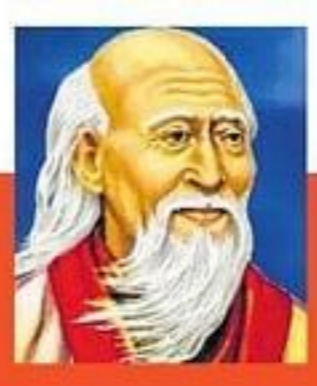
इंडोनेशिया ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर क्यों रखा? दुनिया को शून्य का पता कैसे चला? कंबोडिया के जंगलों में एक ही देवता का विशाल मंदिर क्यों है? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आखिर गुलाम कैसे हो गया?

ब्रिटेन के इतिहासकार, ऐतिहासिक ब्रांडकास्टर और फोटोग्राफर विलियम डेलरिपल अपनी नई पुस्तक *द गोल्डन रोड, हाउ एन्वांट इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ल्ड* में उन विचारों का जिक्र करते हैं, जिनसे भारत ने पूरी दुनिया को आकार दिया। दस अध्यायों में लिखी करीब 600 पृष्ठ की यह किताब वैश्विक इतिहास, कला और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता के प्रभावों का बड़ा खुबसूरती के साथ बखान करती है। यह न केवल प्राचीन इतिहास, बल्कि मध्यकाल से लेकर आधुनिक भारत को छूकर कहानी बताती है।

इसे लिखने के लिए विलियम डेलरिपल ने भारत में पूरे पांच वर्ष बिताए। किताब बताती है कि दुनिया भर के लोगों के पास स्थानीय मान और शून्य आधारित संख्या प्रणाली का ज्ञान कैसे पहुंचा? इंडोनेशिया ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर क्यों रखा? कंबोडिया के जंगलों में एक ही देवता का विशाल मंदिर क्यों है? जैसे-जैसे किताब के पन्ने पलटते चले जाएंगे, तो भारत को और गहराई से जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। डेलरिपल बताते हैं कि एशिया के लिए भारत का स्थान बढ़ी था, जो स्थान

रोम के लिए यूनान का हुआ करता था। भारत के विचार चीन समेत लगभग पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया और ज्वालामय अरब दुनिया में फैले हुए थे। यह वह हिस्सा था, जिसे इंडोसफीयर कहा जाता है या काव्यात्मक रूप में कहें, तो 'गोल्डन रोड' हिंदू कुश से लेकर प्रशांत महासागर तक को जोड़ती थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र है, तो प्रथम अफगान युद्ध की गाथाओं का रोमांचक चित्रण भी है। इसमें मलद्वी विश्वविद्यालय और उसके महान पुस्तकालय का भी जिक्र है। 'गोल्डन रोड' भारत से समुद्र, पहाड़ों और रेगिस्तानों द्वारा अलग किए गए

दोस्तों तक सांस्कृतिक प्रसारण की जटिल व्यवस्था में गहरी दिलचस्पी जगाती है। किताब यह भी बताती है कि कैसे भारतीय नाविकों ने उच्च गति वाले मोटरखे के समुद्री समकक्ष तैयार करने के लिए मानसून के अपेक्षाकृत पूर्वानुमानित पैटर्न का उपयोग करना सीखा। यह वह दौर था, जब भारत और अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच लोग इतनी तेजी से यात्रा कर सकते थे कि अफगानिस्तान में धार्मिक चतलने वाले अंडों के कारवां को भी शर्म आ जाए। 'गोल्डन रोड' में एक चीनी विश्व जुआनजंग का भी वर्णन है, जिसने 6,000 मील की यात्रा कर 17 वर्ष भारत में विताकर बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल की। किताब का मुख्य विषय उत्तर मध्य काल यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के इर्द-गिर्द घूमता है, जब हिमालय द्वारा मानसून की खोज की गई थी और जो लाल सागर और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से व्यापार को गति प्रदान करता था। ऐतिहासिक घटनाओं को डेलरिपल ने कहाँ के रूप में पेश कर किताब को पठनीय बना दिया है।



Hindi@mithelesh

मिथिलेश बरिया

## गोल चबूतरा



भूख रिरतों को भी लगती है, प्यार कभी-कभी परोस कर तो देखिए...

## गजल भर्त तिवारी

### घर में ही आज हम मेहमान हो गए

बम फैक्ट्री मालिक, भगवान हो गए, उनके रहस्यो-कर्म पे इन्सान हो गए।

उसका जमीर तो पहले से था बिका, तुमको ये क्या हुआ जो हैवान हो गए।



पहले न थी दिखी, कैसी है ये दरार, घर में ही आज हम, मेहमान हो गए।

परदे में हैं अदल और दिल है लापता, यारों के चेहरे हाय अनजान हो गए।

तन्हा जो रह गए, वो दीवाने हो गए, सब कुछ गंवा के 'भरत', अनजान हो गए।

## शूटिंग के दौरान मस्ती के पल



फिल्म 'आदमी और इन्सान' की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री ममता, अभिनेता धर्मदर और फिरोज खान मस्ती के पलों में। तस्वीर 1969 की है।

■ भगलपुर से दिवेक दास

## ग्रामोफोन

### आशा के लिए बनी धुन, गाया सलमा ने

साल 1982 में आई फिल्म 'निकाह' हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें मुख्य किरदार निभाया था- सलमा आगा, राज बख्तर और दीपक पारशर ने। सलमा आगा को फिल्म 'निकाह' इत्काफ से मिली। दरअसल, एक दिन सलमा, नोशाद साहब के घर एक गाने के सिलसिले में पहुंची थीं। वहीं उनकी मुलाकात वी.आर. चोपड़ा से हुई। चोपड़ा साहब को सलमा की आवाज और अंदाज इस कदर भाया कि उन्हें वहीं 'निकाह' फिल्म का ऑफर दे दिया। सलमा आगा ने ही इस फिल्म का गीत 'दिल के अरमां आंचुओं में बह गए' गाया।

हसन कमल के लिखे इस गीत की धुन संगीतकार रवि ने आशा भोसले के लिए तैयार की थी, लेकिन सलमा आगा ने निर्माता-निर्देशक वी.आर. चोपड़ा से कहा कि वही इस गीत को गाएंगी। आखिरकार रवि को मानना पड़ा, लेकिन सलमा उस रोज में नहीं गा पा रही थीं, इसलिए उसमें थोड़े बदलाव किए गए और अंत में यह गीत सलमा आगा ने ही गाया। यह गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसके लिए सलमा आगा को सर्वश्रेष्ठ पारवर्गायिका का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।

■ निशा कश्यप, दिल्ली

रावण पर भगवान राम की विजय बताती है कि जब हम ईमानदारी से लक्ष्य पाना चाहते हैं तो परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाती हैं। लेकिन क्या हम बिना दुर्भाव के अपनी कमियां दूर कर लक्ष्य पाना चाहते हैं?

## पुतला दहन से आगे का सबक

### अपने अंदर के 'रावण' का दहन

**द** शहरा बुगई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह रावण पर भगवान राम की जीत की याद में मनाया जाता है और हम रावण का पुतला दहन करते हैं। लेकिन यह पर्व यहीं तक सीमित नहीं है। इसके गहरे निहितार्थ हैं, जिन पर हमको चिंतन-मनन करना चाहिए और सबक लेते हुए स्वस्थ समाज बनाने में योगदान करना चाहिए। पहली सीख है

अहंकार नहीं करने का, जब इसने पुलस्त्य ऋषि के पौत्र और विश्वा ऋषि के पुत्र, परम शिव भवत, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर

विद्वान, महाबलशाली रावण को नहीं छोड़ा तो साधारण मनुष्य की क्या बिसात है? चाहे जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। संगीत प्रेमी रावण की वीणा सुनने मृग तक आ जाते थे, लेकिन स्वयं रावण ने कभी किसी की नहीं सुनी और हमेशा सर्वज्ञ होने के अहंकार में रहा। शिव तांडव स्तौत्र, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रावणीयम जैसी पुस्तकों का रचनाकार रावण स्वयं स्त्री अस्मिता को भूल गया। लालसाएं असौमित्र हैं। इनसे बचकर आत्मसंतुष्टि के साथ आगे बढ़ें। दूसरी तरफ राम सबको साथ लेकर चलते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वानर, ऋक्ष, जटायु और यहां तक कि गिलहरी का भी सहयोग लेते हैं। साक्षात् भगवान का अवतार होने के बाद भी साधारण और सर्व सुलभ रहे। हमेशा अहंकार शून्य रहे। यही जीवन का सत्य है कि कोई छोटा-बड़ा नहीं होत, सबकी अपनी अहमियत होती है। अयोध्या से लौटने पर सर्वप्रथम माता कैकेयी के पास जाते हैं, जिन्होंने उनके वनवास का प्रस्ताव दिया था। किसी से कोई दुर्भाव नहीं। सभी को जीवन में यही सकारात्मक सीख अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

■ डॉ. भनोज कुमार शर्मा, बुलंदशहर



## स्वच्छ भारत का सपना

**प्र** धानमंत्री नरेंद्र मोदी विल्कुल सही कहते हैं कि देश जितना साफ होगा, उतना ही चमकेगा, क्योंकि गंदगी ही ज्यादातर बीमारियों की जड़ है और अगर देश अस्वच्छ रहेगा तो अस्वस्थ भी रहेगा। यदि देश अस्वस्थ होगा तो सब अस्त-व्यस्त रहेगा। चाहे आम लोगों का जीवन हो या देश का विकास। आज बीमारियों से निपटने के लिए सरकार को बड़ा बजट खर्च करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति उपचार पर औसतन 65 हजार रुपये खर्च करता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पहले जिस वैश्विक महामारी कोरोना ने दुनिया को आफत में डाला था, उसके कारणों में लोगों का गलत खानपान और अस्वच्छ भोजन भी शामिल था। स्वच्छता हमारे मन में होनी चाहिए। जब तक हम

शारीरिक और खानपान को स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने आसपास की सफाई पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। खाने से पहले हाथ धोने जैसी छोटी-छोटी आदतें हमें स्वच्छता की ओर अग्रसर करती हैं। हमें दिखावा से बचना होगा। आज बहुत से नेता झाड़ू के साथ फोटो तो खिंचा लेंगे, लेकिन हकीकत में वे कुड़े ढेर के पास गाड़ी लगाकर उतर रहे होते हैं। इस खोखलेपन से बाहर आना होगा। जागरूकता से इतर आज भी बहुत से सोशलजिक स्थानों पर कूड़ादान और बाथरूम नहीं हैं। यह तो सरकारों की ही जिम्मेदारी है। नेताओं को फोटो से आगे बढ़ इन पर ध्यान देने की जरूरत है।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

## इबकी चिड़ियां भी सचहवीय रहें

दिल्ली से योगेश कुमार गोयल, गोहाटी से अभिलाषा गुप्ता, गिर्जापुर से सलित सावित्री, अमरोहा से डॉ. महताव अमरोहवी, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, गाजियाबाद से ललित शंकर, फिरोजाबाद से विजित, इंदौर से महेंद्र जैन, पटना से सरिता प्रसाद, शाजापुर से एमएम राजावतराज, इंदौर से अमृतलाल मास्व

## हमें लिखें

abhiyan@amarujala.com

## अपराधी कौन और सहयोगी कौन?

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इसाइल और हमास, दोनों को युद्ध अपराधों का दोषी माना है। अक्सर अपराधों के मामले में अपराधी के पास सहयोगी होते हैं। तो फिर वे कौन लोग हैं, जिन्होंने एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इसाइल की मदद की है?

**ह** मास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इसाइल के नागरिकों पर क्रूर हमला किया। इसमें 1,100 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से तीन चौथाई आम लोग थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए इसाइल ने गाजा से लगे हमास के नियंत्रण वाले फ्लोस्तीनी क्षेत्र पर बमबारी की। तब लगा था कि इसाइल कुछ समय बाद बमबारी बंद कर देगा, लेकिन यह बर्बर अभियान पूरे एक साल से जारी है। इसाइली सेना के हमलों में 50,000 से अधिक फ्लोस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के दस लाख से अधिक निवासी अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। गाजा में तबाही मचाने के बाद अब इसाइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया है। वहां भी उसने इस बात की कड़ी परवाह नहीं की है कि हमले में अंतर्कावदी मारे जा रहे हैं या निर्दोष नागरिक। खास लोगों को खत्म करने की कोशिश में उसने सैकड़ों लेबनानी नागरिकों को मार डाला है और हजारों को बेघर कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इसाइल और हमास, दोनों को युद्ध अपराधों का दोषी माना है और यह विल्कुल उचित भी है। पिछले अक्टूबर में हमास द्वारा किए गए नरसंहार को किसी भी ऐतिहासिक संदर्भ में न तो माफ किया जा सकता है और न ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। बदला लेने की कोशिश में उसने अंधाधुंध कार्रवाई और बमबारी की है। स्कूलों और अस्पतालों को नष्ट किया है। हजारों फ्लोस्तीनीयों को मारने के अलावा भोजन, पानी और बिजली को अपूर्ति को रोककर या प्रतिबंधित कर अनिगन्त लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है।

गाजा में संघर्ष की कवरेंज में मुख्य रूप से दो प्रतिस्पर्धी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है- इसाइल और हमास। यह कालम उन समूहों या राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्होंने संघर्ष पैदा करने और उसे कायम रखने में भूमिका निभाई है। अक्सर अपराधों के मामले में अपराधी के पास सहयोगी होते हैं। तो फिर वे कौन लोग हैं, जिन्होंने एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इसाइल की मदद की है? हमास का प्रमुख सहयोगी ईरान और लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह है। प्रमुख पश्चिमी मीडिया नियमित रूप से इसका नाम लेकर उसे शर्मिंदा भी करता है। इसके बावजूद यह इसाइल के सहयोगियों की पहचान करने से कतरता है। निस्संदेह इसाइली सरकार के इन कृत्यों के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। उसने इसाइल को लगातार सैन्य मदद दी है, उसे गाजा (और अब लेबनान) पर हमला जारी रखने के लिए जरूरी हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों के खिलाफ वोटो या मतदान करके इसाइल को राजनयिक संरक्षण की भी पेशकश की है। अमेरिका की मिलीभगत के इन्कार का उदाहरण पिछले सप्ताह मैंने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साक्षात्कार में



रामचंद्र गुहा

जाने-माने इतिहासकार

विरोध" द्वारा सक्रिय किया गया था। इस प्रदर्शन में बाहर के बिना बुलाए कुछ एजेंट जरूर थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों में से अधिकांश इसी विश्वविद्यालय के छात्र और संकाय सदस्य हैं। इसके अलावा गाजा में महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में अपने पूर्वजों की पक्षपातपूर्ण प्रतिबद्धता के खिलाफ कई यहूदी छात्र भी शामिल हुए। हिलेरी क्लिंटन का इंटरव्यू लेने वाले फरीद जकारिया भी उनके सामने अपने तथ्यों को नहीं रख पाए। हिलेरी क्लिंटन को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि न्यूयॉर्क से दूर भी एक दूसरी एजेंसी है, जिसे समर्थन मिलता है और फंडिंग प्राप्त होती है। यह इसाइल है, जिसे अमेरिका का वरदहस्त प्राप्त है। मुझे ऐसा लगा कि अगर हिलेरी क्लिंटन ने अपनी ही टिप्पणियों को ध्यान से सुना होता तो शायद उनमें आत्मचिंतन की क्षमता अधिक होती। मुझे इस बात पर संदेह है कि वाशिंगटन में एक लंबा समय गुजरने के बाद वह अपनी सरकार को किसी भी चीज के लिए दोषी ठहराएंगी।

वर्तमान विवाद से पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों और सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में इसाइल को अपनी मौन सहमति दी है। पूरे पश्चिमी तट पर के आसपास हो रहे यहूदियों के विस्तार की वजह से वाशिंगटन को कभी हल्की फटकार तो लगती है, लेकिन कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वह डेमोक्रेटिक प्रशासन हो या फिर रिपब्लिक, दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने इसाइली सेना के समर्थन से फ्लोस्तीनी की जमीन पर बसने वाले यहूदियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। दशकों से बस रह इन यहूदियों ने फ्लोस्तीनी राज्य के निर्माण को असंभव बना दिया। इसमें अमेरिका और इसाइल, दोनों बराबर के दोषी हैं। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के आपराधिक उल्लंघनों में

इसाइल का प्रमुख भागीदार रहा है। हालांकि इसमें अन्य देश भी सहयोगी हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं और सही मायनों में देखा जाए तो हम भी कम दोषी नहीं हैं। हम हमास द्वारा इसाइल पर किए गए हमलों को पहली बरसी को मनाते हैं, पर जब हम इसाइल के हाथों मारे जा रहे निर्दोष फ्लोस्तीनीयों को लेकर विचार करते हैं तो हमें अमेरिकियों की तुलना में कुछ हद तक अधिक आत्मजागरूक और आत्मआलोचनात्मक होना चाहिए। हमें अपनी सरकार को भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि उसने कम से कम दो तरीकों से इसाइली अभियान को सहायता प्रदान की। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम और इसाइल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के आह्वान वाले प्रस्तावों का समर्थन न करना और दूसरा, युद्ध की वजह से खस्ताहाल हुई इसाइल की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रवासी मजदूरों को भेजना।

वर्तमान भारतीय सरकार द्वारा इसाइल को समर्थन देने की दो प्रमुख वजहें हैं। इनमें से एक व्यक्तिगत है, नरेंद्र मोदी और बैंगमिन नेतन्याहू के बीच दशकों पुरानी दोस्ती। दूसरा यह है कि मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखना है। पिछले महिने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में मध्य-पूर्व संकट पर चर्चा हो रही थी, तब भारत की ओर से कुछ खोखले वादे ही पेश किए गए। दूसरी ओर, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा, "मैं इसाइली सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि रक्तपात बंद करो, पीड़ा बंद करो, बंधकों को घर लाओ और कब्जा खत्म करो। नेतन्याहू अब इस युद्ध को रोकें।" ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा, "अब लगभग 300 दिन हो गए हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के अलावा 152 अन्य देशों ने युद्ध विराम के लिए मतदान किया था और आज मैं उस बात को फिर से दोहराता हूँ। लेबनान अलग गाजा नहीं बन सकता।" गौर करने वाली बात है कि स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया न केवल लोकतांत्रिक देश हैं, बल्कि इसाइल के मुख्य आर्थिक साझेदारों के घनिष्ठ संबंध भी हैं। इसके बावजूद उनके नेताओं में यह दूरदर्शी साहस है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, दोनों में स्पष्ट रूप से अभाव है।

मध्य-पूर्व में इसाइल को एकमात्र लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली लोकतंत्र है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। गाजा में मानवता के खिलाफ अपराधों को जारी रखने के लिए इन देशों ने जो किया है, उसे देखते हुए ये सभी दावे खोखले लगते हैं। जैसा कि प्रताप भानु मेहता ने संक्षेप में कहा है, "यहां तीन लोकतंत्र हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं- इसाइल अपने संघर्ष की क्रूरता से, अमेरिका उसे सहायता देकर और मिलीभगत से तथा भारत अपनी टालमटोल से, जो मिलीभगत के दायरे में ही आता है।"



## सिनेमा को मिली आवाज...

1927 में आज के ही दिन अमेरिका में पहली बोलती फिल्म 'द जैज सिंगर' रिलीज हुई थी। इससे पहले फिल्मों में आवाज नहीं होती थी। केवल मूक सिनेमा चलता था। ज्यादा से ज्यादा परदे के पीछे से कलाकार संगीत और आवाज देते थे। 'द जैज सिंगर' ने सिनेमा और संसार जगत में एक नई क्रांति की नींव रखी। खास बात यह थी कि यह एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसमें साउंड पर कमाल का काम किया गया था। इसने सिनेमा को लेकर लोगों की धारणा ही बदल दी थी। फिल्म के निर्माता वॉनर ब्रदर्स और निर्देशक एलन क्रॉसलैंड थे। फिल्म 1922 में छपी सैमसन राफेलसन की लघुकथा पर आधारित थी, जो कि फिल्म के मुख्य किरदार अल जॉलसन के असल जीवन पर ही आधारित थी। एक

स्टेज प्ले में अल जॉलसन के अभिनय से प्रभावित होकर राफेलसन ने यह कहानी लिखी थी। फिल्म से पहले यह 1925 में एक नाटक के रूप में प्रदर्शित हुई थी। नाटक को खूब पसंद किया गया। इसके बाद

ही वॉनर ब्रदर्स ने फिल्म बनाई। नाटक में मुख्य किरदार जेसेल ने अदा किया था, जो कुछ मतभेदों के चलते फिल्म से अलग हो गए थे। फिल्म की कहानी एक यहूदी युवा के इर्द-गिर्द थी, जो गायक बनने के लिए अपने घर से भाग जाता है और बाद में वह गायक के रूप में प्रसिद्धि पाता है। एक घंटे 19 मिनट की फिल्म के निर्माण में करीब पांच लाख डॉलर का खर्च आया था, लेकिन इसने आठ गुना कमाई करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था।

सबसे पहले 1896 में फिल्म को आवाज देने की कोशिश हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद भी लगातार प्रयोग जारी रहे। करीब तीन दशक बाद 'द जैज सिंगर' के रूप में पहली बोलती फिल्म बनी। भारतीय सिनेमा की बात करें तो पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' थी। अर्दशिर ईरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 मार्च, 1931 को मुंबई के मेजॉस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई थी।

■ पीडी गढ़वाल से सौरभ भंडारी

## शहीदों की शान में एक माह का मेला

जोधपुर के खेजडली, मैनुपुरी के बेवर और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फिरींगी हुकूमत की चूलें हिला देने वालों की याद में देशभर में कई स्थानों पर विशाल मेले लगाने हैं। इन अनूठे मेलों में हापुड़ का शहीद मेला सबसे लंबी अवधि का माना जाता है, जो पूरे एक माह देशभक्ति की अलख जगाता है। हर साल 10 मई से 10 जून तक लगने वाला यह मेला आजादी के लिए हंस्ते-हंस्ते फांसी का फंदा चुमने वाले वीर सपूत जबरदस्त खां और उनके छोटे भाई उल्फत खां की शहादत को समर्पित है, जिन्हें 14 सितंबर, 1857 को रामलीला मैदान के बाहर पीपल के पेड़ पर फांसी दी गई थी।

भंडा पट्टी निवासी दोनों भाइयों के बलिदान का गवाह वह पीपल का पेड़ है। यह 1896 में फिल्म की आवाज ही शहीद स्मारक बना है। चौधरी जबरदस्त खां उन 85 सिपाहियों में शामिल हैं, जिन्होंने मेरठ में 1857 की क्रांति का विगुल फूँका था। बगावत से

## चंद्रमोहन शर्मा



## खुला आकाश

चौधरी जबरदस्त खां और उल्फत खां की शहादत की याद में मेले की शुरुआत 1975 में हुई। कुछ लोगों ने हापुड़ में उसी जगह शहीद दिवस मनाया, जहां दोनों भाइयों को फांसी दी गई थी।

अफसरों ने दोनों क्रांतिकारी भाइयों को सजा-ए-मौत दे दी। इस शहादत की याद में मेले की शुरुआत 1975 में हुई। पत्रकार कैलाश आजाद ने अपने साहित्य के साथ रामलीला मैदान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे 10 मई को शहीद दिवस मनाया। अगले साल 10 मई, 1976 को शहीद मेला लगा। तब से यह विलसिला चल आ रहा है। मेले में शहीदों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, शहादत की दास्तां का नाट्य मंचन किया जाता है। विडंबना है कि इस मेले को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है। हापुड़ के लोगों में देश की खातिर मर-मिटने का यह जज्बा 1942 की अग्रस्त क्रांति में भी दिखा, जब जुलूस निकाल रहे क्रांतिकारी राम स्वरूप, गंगनलाल शर्मा, गिरधारी लाल और मांगेलाल अंग्रेजी सिपाहियों की गोलियों में शहीद हो गए। जुलूस में शामिल लाला सेवामराम ने गोली लगने से घायल होने के बावजूद डाकघर पर तिरंगा फहराया था। चारों शहीदों की याद में अतरपुरा चौपला पर शहीद स्मारक बनाया गया है। इसके पीछे पुलिस चौकी है, जिस पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं।

# 6 विमर्श

जनसत्ता | 6 अक्टूबर, 2024

# कल्पमेधा

# बिखरती उम्मीदें, टूटते दिल

यह ताजा खबर है, लेकिन कुछ अलग तरह की। यह कानून तोड़ने, सिर फोड़ने या घर ढहाने से जुड़ी खबर नहीं है। यह वह 'ब्रेकिंग न्यूज' भी नहीं है, जो पहले कई बार दुहराई जा चुकी है।

जब राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, हिंसक अपराधों के बढ़ते ग्राफ को दर्ज करता है, तो वह कानून तोड़ने से संबंधित खबर होती है। जब उन्मादी समूह किसी युवा जोड़ے को पीटते या किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो वह सिर और हड्डियां तोड़ने की खबर होती है। जब अधिकारी कथित अतिक्रमण को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, तो वह घर तोड़ने की खबर होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री विपक्ष- खासकर कांग्रेस- को टुकड़-टुकड़ें गैंग या शहरी नक्सली कहते हैं, तो इस 'ब्रेकिंग न्यूज' को सुन कर लंबी उबासी आती है।

### हवा हवाई

जो सबसे महत्वपूर्ण 'ब्रेकिंग न्यूज' मैंें आपसे साझा करने जा रहा हूं, उसे सुन कर आपका दिल और उम्मीदें टूट जाएंगी। केवी कामथ महोदय प्रतिष्ठित बैंक व्यवसायी हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई को भारत के अग्रणी निजी बैंक के रूप में स्थापित किया; न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक) के पहले अध्यक्ष थे; वे वर्तमान में नेशनल बैंक फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनवीएफएआईडी) के अध्यक्ष हैं। हाल ही में एक पुस्तक समीक्षा में, उन्होंने उस मार्ग का पता लगाया है, जिसे भारत को 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपना लेना चाहिए।

एक प्रमुख अखबार में लिखे अपने एक लेख में, कामथ महोदय ने लेखक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की खूब बड़बड़ कर सराहना की है। उन्होंने लिखा है, 'अपने अंतर्निहित विषय को ढ़ढ़तापूर्वक रखने के लिए... कि

भारत को अतीत की निराशावादी बेड़ियों से मुक्त होने और ठोस सोच के आधार पर साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।' कामथ महोदय ने लेखक से सहमति जताते हुए कहा है कि अगर 12.5 फीसद प्रति वर्ष (अमेरिकी डालर में) की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर बनी रहती है, तो 'हर छह वर्ष में दोगुना होती हुई 2023 की 3.28 लाख करोड़ डालर जीडीपी 2047 में बढ़ कर वह 55 लाख करोड़ डालर, यानी लगभग सोलह गुना तक हो जाएगी। यह पूरी तरह से संभव है।' मैंें इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और इस तरह का सतत विकास लक्ष्य बनाए रखने के लिए मैंेंने तर्क दिया है।

### पूछ में डंक

कामथ महोदय की समीक्षा में 'डंक' अंतिम छठवें पैराग्राफ में है। वे 'चार स्तंभों' की सूची बना कर अपनी बात शुरू करते हैं, जो शताब्दी वर्ष में भारत को आकार देंगे। वे हैं: विकास पर वृहद-आर्थिक ध्यान, सामाजिक और आर्थिक समावेशन, निजी क्षेत्र द्वारा नैतिक धन सृजन और निजी निवेश द्वारा प्रज्वलित एक पवित्र चक्र। आइए, वर्तमान सरकार के संदर्भ में इन 'स्तंभों' का परीक्षण करें।

विकास पर वृहद-आर्थिक ध्यान: वृहद-आर्थिक विकास पर निरंतर ध्यान के संकेतक राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति और ब्याज दर, चालू खाता घाटा

दूसरी नजर पी चिदंबरम

छठे दस वर्षों में बैंक धोखाधड़ी और कारपोरेट पतन दिवालियापन संहिता बैंक कर्मजमाप्री को वैध बनाने और तथाकथित विफल कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने का एक साधन बन गई है।

पूंजीवाद, पूंजी गहन उद्योगों में सार्वजनिक निवेश, कारपोरेट कर में कमी, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर कर, उच्च ईंधन की कीमतें, अपर्याप्त न्यूनतम मजदूरी, किराएदार किसानों की उन्पेक्षा, गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवाओं के प्रति पूर्वाग्रह (उदाहरण के लिए, वंदे भारत ट्रेन बनाम रेलवे में द्वितीय श्रेणी और अनारक्षित कोच) और अन्य नीतियों ने आवादी के शीर्ष एक फीसद और निचले 20 फीसद के बीच आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है। कामथ महोदय द्वारा पहचाना गया दूसरा स्तंभ डगमगाता हुआ और कमजोर है।

निजी क्षेत्र द्वारा नैतिक धन सृजन: पिछले दस वर्षों में बैंक धोखाधड़ी

# संकल्प और स्वच्छता

गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री दिखे हाथ में झाड़ू लिए आम जनता को स्वच्छ भारत आंदोलन के लिए नए सिरे से प्रोत्साहित करते हुए। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर दिन सफाई पर ध्यान देना होगा, साल में केवल एक दिन के लिए नहीं। मतलब सिर्फ स्वच्छ भारत दिवस पर झाड़ू उठाना काफी नहीं है। मैंेंने जब उनको देखा टीवी पर और उनकी बातें सुनीं तो कुछ दर्द के लिए हैरान रह गई। काश, प्रधानमंत्रीजी आप मेरे साथ दिल्ली से हरियाणा गए होते पिछले सप्ताह और आपको दिखते वे कचरे के पहाड़, जो रास्ते में पड़ते हैं और जो इतने ऊंचे हैं कि दूर से असली पहाड़ों की तरह दिखते हैं। उनको देखते, तो शायद आप भी जान गए होते कि स्वच्छ भारत अभियान कई सालों से खोखला नारा बन कर रह गया है। इन कचरे के पहाड़ों से रोज निकलते हैं जहरीले रसायन, जो दिल्ली की हवाओं में उतना ही प्रदूषण फैलाते हैं जो इस मौसम में किसानों के पराली जलाने से फैलता है। कुछ दिन पहले अखबारों में तस्वीरें छपीं पराली के जलने की और कुछ क्षण के लिए हममें से कुछ मीडियावालों ने तकलीफ जताईं अपने लेखों में। कहा हमने कि शुरू हो गया है फिर से देश की राजधानी की वायु में इतना जहर फैलना कि बच्चे बीमार रहते हैं सर्दियों के मौसम में और दमा के मरीजों का तो हाल न पूछो क्या हो जाता है। बिल्कुल इस तरह की बातें, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में हम कहते हैं हर साल यही बातें, जब दिवाली करीब आने लगती है और उत्तर भारत के लोगों के लिए संदेश लाती है कि गरम कपड़ों को संदूकों में से निकालने का समय आ गया है।

सवाल यह है कि हम क्यों नहीं साथ में यह भी पूछते हैं हर साल कि क्यों ऐसा होता है हर साल? क्यों नहीं हमारे शासक जान गए हैं कि उपाय है पराली जलाने को रोकने का। कई बार किसान कह चुके हैं कि मशीनें हैं जो पराली उठा सकती हैं उनके खेतों से, ताकि उसको जलाना न पड़े, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं इन मशीनों को खरीदने के लिए, इसलिए यह काम सरकारों को ही

करना होगा। क्यों नहीं कुछ करती हैं सरकारें? क्या वजह यह है कि दवाव नहीं डालते हैं हम इतना कि चुनावों में वायु प्रदूषण अहम मुद्दा बन जाए? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत को स्वच्छ रखने का काम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं हो सकता, लेकिन दस साल से देश की गाड़ी को चला रहे हैं नरेंद्र मोदी खुद और रहते भी हैं दिल्ली में, जहां सर्दियों के मौसम बिना कि विकसित होना असंभव है जब तक हमारे शहर, हमारी नदियां, हमारा वायु इतना गंदा रहता हो कि जीना मुश्किल हो जाए।

सच यह भी है, कि गंदगी और गरीबी का कोई रिश्ता नहीं है। मैंेंने पहले भी यहां लिखा है और बार-बार लिखूंगी कि श्रीलंका हमसे गरीब है, लेकिन वहां गंदगी नहीं दिखती है। कम्पूचिया हमसे गरीब है, लेकिन उस देश में भी गंदगी नहीं दिखती है। दूसरे देशों की बातें छोड़ें, हमारे अपने देश में इंदौर साफ है इतना कि मैंें जब भी जाती हूं, हैरान रह जाती हूं, साफ-सुथरे बाजार, साफ-सुथरी गलियां देखकर।

मैंें प्रदूषण की चादर छा जाती है सारे शहर के ऊपर और तभी उठती है जब मौसम बदल जाता है होली के बाद। प्रधानमंत्रीजी आपने क्यों नहीं अभी तक देश की राजधानी में वायु प्रदूषण बंद करने के लिए कोई ठोस उपाय ढूंढा है? क्यों नहीं आपको दिखे हैं कचरे के वे ऊंचे पहाड़? क्यों नहीं आपको दिखा है कि यमुना का पानी आज भी उतना ही गंदा है जैसे पहले होता था, बावजूद इसके कि आपको शासनकाल में करोड़ों रुपए इस नदी के पानी को साफ करने में खर्च किए गए हैं?

माना कि काफी हद तक गलती आम लोगों की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा गलती आप जैसे राजनेताओं की है, जिन्होंने इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना आप देते हैं चुनावों में जीत हासिल करने पर। स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआती सालों में तो इसने इतना परिवर्तन लाया देहातों में कि खुले में

शौच करनेवालों की संख्या अस्सी फीसद से ज्यादा कम हो गई है। राजनेता जब नेतृत्व दिखाते हैं किसी काम को करवाने पर, अक्सर देखा जाता है कि जनता इस नेतृत्व को स्वीकार करती है दिल लगाकर। समस्या यह है कि स्वच्छ भारत पर ध्यान जबसे प्रधानमंत्री का कम हुआ है, तबसे जनता ने भी ध्यान नहीं दिया है। नतीजा यह है कि हम विकसित भारत का सपना देखते तो हैं, लेकिन ये सोचे

बिना कि विकसित होना असंभव है जब तक हमारे शहर, हमारी नदियां, हमारा वायु इतना गंदा रहता हो कि जीना मुश्किल हो जाए।

सच यह भी है, कि गंदगी और गरीबी का कोई रिश्ता नहीं है। मैंेंने पहले भी यहां लिखा है और बार-बार लिखूंगी कि श्रीलंका हमसे गरीब है, लेकिन वहां गंदगी नहीं दिखती है। कम्पूचिया हमसे गरीब है, लेकिन उस देश में भी गंदगी नहीं दिखती है। दूसरे देशों की बातें छोड़ें, हमारे अपने देश में इंदौर साफ है इतना कि मैंें जब भी जाती हूं, हैरान रह जाती हूं, साफ-सुथरे बाजार, साफ-सुथरी गलियां देखकर। इंदौर साफ किया जा सकता है तो देश के बाकी शहर भी साफ हो सकते हैं। इंदौर साफ हुआ तब, जब वहां की नगरपालिका ने कचरा फेंकने वालों को दंडित करना

शुरू किया। ऐसा होना चाहिए हर शहर में, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए हमें कि उन अधिकारियों को भी दंडित करना होगा, जिनकी लापरवाही के कारण बने हैं देश की राजधानी में कचरे के वे ऊंचे पहाड़।

दंडित होते हैं सरकारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक किसी सरकारी अफसर को लापरवाही करने के लिए दंडित नहीं किया गया है। जब देश की राजधानी को ही हम साफ वायु-पानी नहीं दे सकते हैं तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के बाकी शहर साफ हो जाएं? सबसे कड़वा सच यह है कि स्वच्छता और विकास का गहरा रिश्ता है कई तरह से। इसलिए जब तक स्वच्छता पर हमारे शासक गंभीरता से काम नहीं करने लगते हैं, हमको भूल जाना चाहिए विकसित भारत का सपना। सपना है आज, और कल भी सपना ही रहेगा।

खुले आसमान के नीचे जमीन पर चाय पीने की एक जगह दिल्ली (विश्वविद्यालय के हिंदू कालेज में थी। यह अत्यंत ही आकर्षक स्थान जय सिंह का ढाबा था। यह एक 'लघु सभागार' की तरह था। छात्र समूहों में राजनीति से लेकर सिनेमा, स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय मसलों पर तर्क-वितर्क होते रहते थे। यह

अकेला उदाहरण नहीं है। देश के प्राय: सभी विश्वविद्यालयों और शहरों/महानगरों में ऐसे कुछ चिह्नित स्थान होते थे। अभी भी कुछ बचे हुए हैं। छोटे लंबूट में बड़ी बातें होती थीं। कोलकता, पुणे, चेन्नई, बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 'लघु सभागार' आपको मिल जाता था। पर अब वे समाप्ति की ओर हैं। जय सिंह के ढाबे का जो हश्र हुआ, वही सबके साथ हो रहा है।

ये सभी भौतिकता की बलि चढ़ रहे हैं। उनके स्थान पर चाय-काफी की महंगी दुकानें खुल रही हैं, जहां अच्छी आरामपेह कुर्सियां, वातानुकूलित कमरे, अंग्रेजी बोलने वाले चाय परोसक होते हैं। बजट बढ़ा है, तो बात भी स्वेंकेंद्रित हो गयी। हंसने-बोलने, समय बिताने की जगह अच्छी है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। पहली स्थिति में सब कुछ अनौपचारिक है। मन-मस्तिष्क भौतिकता में कैद नहीं है। पर दूसरी स्थिति में हम मात्र उपभोक्ता हैं। हमारा व्यवहार हमारी वाणी और वार्तालाप भी औपचारिकता के करीब रहता है।

चकाचौंध की संस्कृति जब पेर पसरती है, तब हम उसके गुलाम हो जाते हैं। वह हमारी मौलिकता छीन लेती है। उसे हम अपने ही जीवन के अनुभवों से कुछ हद तक समझ सकते हैं। हम सामूहिकता से दूर होकर व्यक्तिवादी बनते जाते हैं। जीवन में जीने के साधनों में साझेदारी घटती जाती है। अपनी संतुष्टि के लिए नए-नए उपकरणों की तलाश में लगे रहते हैं।

यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है। पूरी दुनिया में नई आर्थिक संस्कृति ने अपना दुस्भाव डाला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक प्रगति गलत है। पर सवाल सीधा है। यह प्रगति हमारी मानसिक उन्नति, सामाजिक सरोकार और साझापन को बढ़ाता या हमें अपने आचरण को उसके अनुकूल ढालने के लिए बाध्य करता है। हमारा समाज अनौपचारिक प्रकृति, प्रयुक्ति और प्रवाह वाला है। इसे जितना औपचारिकता के सांचे में ढालेंगे, व्वांकुलता बढ़ेगी, परंपरागत संस्थाएं चरमराएंगी और सामाजिक प्राणी की जगह हम उपभोक्ताओं की भीड़ बनते चले जाएंगे।

विश्वविद्यालय माल की तरह, पुस्तकालय क्लब की तरह और परिसर बाजार की तरह बन जाए तो चेतना का सृजन बाजार की संस्कृति के अधीन हो जाता है। यह सब नियोजन वे करते हैं, जो बड़े माल, पुल, सड़क, 'आडिटोरियम' या सभागार बनाते हैं। उस प्रक्रिया से छात्रों-शिक्षकों को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार शहर के नियोजन में लोगों की मूल प्रकृति पर विचार नहीं किया जाता है। नवउदारवाद इसी का नाम है। सवाल उठता है कि हम चूक कहां रहे हैं? इसी का निदान हमारी मौलिकता बचा सकती है। मनुष्य स्वभाव से विकेंद्रीकरण के साथे में रहना चाहता है। यह छोटे-छोटे समूह, लघु परंपराओं और उत्सवों में प्रकट होता है। भारत का स्वभाव रहा है। इसी को भारत के विमर्श में विविधता कहा जाता है। केंद्रीकरण इस स्वभाव पर सीधा हमला होता है। सुकरात और चाणक्य, दोनों के सामने भौतिकता का विकल्प था, पर वे सादगी पसंद थे। महलों की जगह कुटिया में रहते थे। वे याद किए जाते हैं, पर उस काल के धनानेदों, भौतिकवादियों का नाम खोजने पर भी नहीं मिल पाता है।

विचार का केंद्र वैभव से दूर होता है, क्योंकि वैभव भी उसी विचार के तहत विमर्श का हिस्सा होता है। ऐसे केंद्र मूल प्रश्नों पर अनौपचारिक-औपचारिक निरंतर विमर्श करते हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य चेतना सृजन है। नवउदारवाद इससे भयभीत रहता है। उसे 'कार्य संस्कृति' वाला मनुष्य

हर सुधार का कुछ न कुछ विरोध अनिवार्य है। परंतु विरोध और आंदोलन, एक सीमा तक समाज में स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं।

— गांधी

एक शाम एक विपक्षी नेता के वचन: वहां नाच-गाना हो रहा था। जवाब में एक योगी-वचन: इनका तो परिवार ही नाचने-गाने वाला रहा है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिला, कर कर लंबे हाथ! फिर तमिलनाडु से एक दिन एलान आया कि उदयनिधि उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और अगले दिन जो कहा, वह कर दिखाया। जलने वाले कहने लगे कि यह वंशवाद है, तो जवाब आया कि वंशवाद कहां नहीं है! फिर एक दिन विनेश फोगाट: हर चैनल पर वही वही सवाल और जवाब, फिर भी तय कि इस चुनाव ने एक नया 'आइकन' दिया! उसके बाद आई इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के हीरो नसरल्लाह के मारे जाने और उसकी 'शहादत' का बदला लेने की ईरानी धमकियों की खबरें! इजराइल का गोला गिरा बेरूत में, लेकिन दो दलों के नेताओं के आसू बरसे कश्मीर में और शोक प्रदर्शन लखनऊ में। पाक का समर्थक 'दुनिया का यह सबसे कुख्यात आतंकवादी' नसरल्लाह कुछ के लिए 'किंग' और कुछ के लिए आतंकवादी। फिर भी वह दर तक चर्चा में छाया रहा। कुछ कहे कि वह 'शहीद' था, कुछ कहे, यह इनका 'पैन इस्तामिज्म' है। इन दिनों कुछ एंकरों को 'तीसरे विश्वयुद्ध' की आहटें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। इनको लगता है कि विश्वयुद्ध न हो, 'गली क्रिकेट' हो! इसके बाद आई एक प्रवक्ता और एक एंकर के बीच एकदम 'तू तू मैं मैं'! चर्चा में जैसे ही एक एंकर ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक नेता',

वैसे ही पक्ष प्रवक्ता ने धर पटका कि आप इस तरह से हमारे नेता का अपमान नहीं कर सकते।

फिर दर तक होता रहा कि 'तुम असभ्य' कि 'तुम असभ्य'! प्रवक्ता कहे कि आप प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी करेंगे तो प्रवक्ता होने के नाते मैंें स्वीकार नहीं करूंगा। 'तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई', विपक्षी कहिन कि मैंेंने नाम कब लिया, तो जवाब आया कि 'वन लीडर', क्या ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं था? दूसरा एंकर येन केन 'शांति जाप' जैसा करता रहा, लेकिन सुने कौन? बहरहाल, अंत में प्रवक्ता जी 'शेरो शायरी' पर उतर आए। फिर उधर से भी 'शेर' आए और इस तरह दोनों शेर 'रवीफ काफिया' वाले शेरों के आगे चुप हुए। फिर एक दिन मामूम हुआ कि इन दिनों अपनी राजनीति में 'सामान्य शिष्टाचार' की भी जगह नहीं बची। जब एक बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष जी की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर आई तो प्रधानमंत्री ने सामान्य शिष्टाचारवश

बाखबर सुधीश पचौरी

उनका हाल-चाल पूछ लिया, तो तुरंत करारा जवाब मिला कि मैंें तब तक नहीं करूंगा, जब तक मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। काश, इस 'तू तू मैंें' के बीच कोई कहता कि 'रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ' तो ये तुर्शी शायद कुछ कम होती।

इन दिनों अक्सर पक्ष-विपक्ष के नेताओं के मुंह में दही जमता रहता है। अरे भाई, यह मुहावरा हुआ पुराना, अब लाओ कोई नया मुहावरा। लेकिन ये बाहर नहीं हो जाते। काश, इस 'तू तू मैंें' के बीच कोई कहता कि 'रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ' तो ये तुर्शी शायद कुछ कम होती।

कई एंकर अक्सर पूछते रहते हैं कि हर चुनावी मौसम के आसपास बाबा राम रहीम को 'पैरोल' कैसे मिल जाता है? अरे भाई! बाबा जी की 'भूमिका' को देखकर 'पैरोल' दिया जाता है। इसलिए पहले उनकी 'भूमिका' देखो, फिर 'भूमिका' के आगे लिखे 'पै शब्द पर ध्यान दो। सब समझ में आ जाएगा!

और कारपोरेट पतन में बढ़ोतरी हुई है। दिवाला और दिवालियापन संहिता बैंक कर्मजमाफी को वैध बनाने और तथाकथित विफल कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने का एक साधन बन गई है। आइबीसी के तहत वसूली दर सिर्फ 32 फीसद है। सफल समाधान आवेदकों ने अप्रत्याशित लाभ कमाया है। दखल देने वाले न्याय, धीरे-धीरे नियंत्रण और दमनकारी कर प्रशासन ने नैतिक व्यवसायियों का मनोबल गिराया है; युवा उद्यमी विदेश में व्यापार करना या पलायन करना ज्यादा पसंद करते हैं। 4300 भारतीय करोड़पति भारत छोड़ चुके हैं (रश्चिर शर्मा, टाइम्स आफ इंडिया)। प्रतिस्पर्धा आयोग ने वास्तव में एकाधिकार और अल्पाधिकार को बढ़ावा दिया है। एअरलाइंस, बंदरगाह, हवाई अड्डे, दूरसंचार, तेल रिफाइनरी और सौर ऊर्जा जैसे उद्योगों में बहुत कम प्रतिस्पर्धा है। सीमेंट, स्टील, बिजली और खुदरा क्षेत्र में तेजी से एकीकरण हो रहा है, और यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी या घटेगी। ये रूझान प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं हैं, जो निजी क्षेत्र द्वारा नैतिक धन सृजन सुनिश्चित करने का समय-परीक्षीत तरीका है।

निजी निवेश द्वारा प्रज्वलित पुण्य चक्र: सरकार की अपील, रियायतें, चापलूसी और धमकियों के बावजूद निजी निवेश सरकारी निवेश से पीछे है। चूंकि सरकार को व्यवसाय पर भरोसा नहीं है, इसलिए व्यवसाय को सरकार पर भरोसा नहीं है। 'शाटगन' सहमेल- संदिग्ध तरीकों से व्यवसायों का अधिग्रहण- ने माहौल को खराब कर दिया है। सन 2000 से सिंगापुर में 8000 से अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं (एचसीआई, सिंगापुर)। जांच एजंसियों के अतिक्रमण ने व्यापारियों में भय फैला दिया है। सितंबर 2022 में, वित्तमंत्री ने भारतीय व्यवसायों से पूछा कि ऐसी क्या चीज है, जो उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने से रोक रही है?

कामथ महोदय इन मुद्दों पर हमें निदेश देने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं।

# वैचारिक विपन्नता का विस्तार

चाहिए जो पुस्तकालय से लेकर माल तक लाभ हानि की चौहद्दी में रहे। जबसे हमने केंद्रीकृत बातों के प्रति समर्पण किया है, तबसे समाज की आंतरिक ऊर्जा का क्षरण शुरू हो गया है। बहुत पीछे याज्ञवल्क्य या शंकराचार्य के युग में जाने की जरूरत नहीं है। साठ-सत्तर के दशक में छोटी-छोटी पत्र-पत्रिकाएं निकलती थीं। सीमित लेखकों और सीमित पाठकों के ये बौद्धिक औजार व्यापक परिणाम देते थे। लोकवाणी, क्रांतिवाद, मुक्ति संग्राम, तरुण क्रांति खूब पढ़ा जाता था। लोग स्वयं या समूह के योगदान से कुछ प्रकाशन करते थे, जो मन को आंदोलित करता रहता था। जयप्रकाश नारायण का 'एकरीमैन', शंकर पिल्लै का 'शंकर वीकली', राजमोहन गांधी का 'हिम्मत', पीलू मोदी का 'मार्च आफ द नेशन', मौनू मसाना का 'फ्रीडम फर्स्ट', एडी गोरवाला का 'ओपिनियन',

संदर्भ राकेश सिन्हा

विचार का केंद्र वैभव से दूर होता है, क्योंकि वैभव भी उसी विचार के तहत विमर्श का हिस्सा होता है। ऐसे केंद्र मूल प्रश्नों पर अनौपचारिक-औपचारिक निरंतर विमर्श करते हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य चेतना सृजन है। नवउदारवाद इससे भयभीत रहता है। उसे 'कार्य संस्कृति' वाला मनुष्य चाहिए, जो पुस्तकालय से लेकर माल तक लाभ हानि की चौहद्दी में रहे।

रमेश धापर का 'सेमिनार', जार्ज फर्नांडिज का 'प्रतिपक्ष', ये कुछ प्रकाशन थे। सैकड़ों में प्रसारण था। लाभ-हानि के उद्देश्य से वे नहीं चलते थे। आर्थिक प्रगति के दौर में लोग प्रशिक्षित होते रहते थे। ये सभी जय सिंह के ढाबे की तरह ही अपने-अपने तरीके से खुला मंच थे।

जब पेट भरने को पैसा नहीं था, तब लोग विचार सृजन करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जमीन पर विचार के सिपाहियों ने राष्ट्रवाद की उर्वरा भूमि सृजित की थी। चंदा कर पत्रिकाएं निकलती थीं। 'हिंदी प्रदीप' के संपादक बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था- 'ग्राहकगण, आपलोग भी इस पत्र का आयुष्य चाहते हों तो द्रव्य से सहायता कीजिए- प्रवाल आपलोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो इतिश्री हो गई है।' सुंदरलाल का कर्मयोगी नौ महीने अस्तित्व में रहा, तीन संपादकों को जेल जाना पड़ा। इलाहाबाद का 'स्वराज्य', गोरखपुर का 'स्वदेश', तिलक का 'केसरी', विचार प्रवाह होते हों तो द्रव्य से सहायता सैकड़ों में थी। विपन्नता में वैचारिक संपन्नता थी। आज संपन्नता में वैचारिक विपन्नता है। इसी वैचारिक विपन्नता की लपट और न फैले, दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के छात्र चिंतित हैं। चाय के खोखे की जगह कहीं चकाचौंध वाली कैटीन न खुल जाए। अगर चेतना सृजन की प्रक्रिया राजनीतिक अखाड़ेबाजी तक सीमित हो जाएगी, तब गंभीर प्रश्न और गंभीर विचार का तुल्य होना स्वाभाविक ही है। वही प्रश्न: हम क्या कर रहे हैं? हम विचार सृजन और विचार प्रवाह में पूर्व के विकेंद्रीकृत स्वभाव को फिर से जगाएं। यही रास्ता नव बौद्धिकता का मार्ग प्रशस्त करेगा।

फिर एक दिन यह खबर भी चैनलों में छाई रही कि ईरान ने इजराइल पर एक सौ अस्सी मिसाइलें दागीं, जिनमें से अधिकांश को इजराइल के 'आयरन डोम' (लौह कवच) ने बेकार कर दिया। कुछ गिरीं, लेकिन बहुत नुकसान न कर सकीं। इसके बाद इजराइल की धमकी चैनलों में टंगी रही कि हम इसका बदला लेंगे, कब और कहां, यह हमें तय करेगे। अमेरिका एक बार फिर इजराइल के पक्ष में आया। कई यूरोपीय देश भी इजराइल के साथ दिखे और इस तरह तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा चैनलों में गरम होती दिखीं। फिर खबर आई तमिलनाडु स्थित सदगुरु के ईशा फाउंडेशन पर पुलिस छापे की और फिर सुप्रीम कोर्ट का उस पर 'स्थगन', चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि इसके पीछे भी बाबा के सनातनत्व के विरोधियों का हाथ रहा। और अंत में कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता के पकड़े से छह हजार करोड़ रुपए ेके प्रतिबंधित खतरनाक मादक पदार्थ टिकाईं जाने की खबर, भाजपा का हमला और जवाबदेह पक्ष की बला टालने की कोशिशें।

फिलिस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी में सक्रिय आतंकी गुट हमाल के इजराइल में उत्सव मना रहे बेकसुरों पर हमले के प्रतिशोध में सबक सिखाने के लिए इजराइल द्वारा शुरू जंग जब लेबनान स्थित चरमपंथी गुट हिज्बुल्ला के कमांडरों व गुट को खत्म करने व यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में तब्दील हुई, तो ईरान ने अपने प्यादे के समर्थन में इजराइल पर 181 बैलेस्टिक मिसाइलों दाग कर सीधी जंग का आगाज कर दिया। इसके बाद से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमी प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल ने ईरान पर जवाबी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन वह चुप बैठने वाला देश नहीं है, प्रतिक्रिया जरूर करेगा, पर कब व कैसे इस पर विचार जरूर है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है और अमेरिका इजराइल के पक्ष में कूदता है तो चीन, रूस के ईरान के पक्ष में आने की आशंका है, ऐसे में विश्व खूद छिड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई जैसे इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है, उससे इजराइल के आतंकी गुटों के खिलाफ जंग को इस्लाम बनाम यहूदी जंग में बदलने की कोशिश प्रतीत होती है। पश्चिम एशिया में अस्तित्व के लिए संघर्षरत इजराइल की ईरान से युद्ध की आशंका पर आजकल का यह अंक...

# जंग की ओर ईरान-इजराइल की दुश्मनी



पश्चिम एशिया

प्रभात कुमार राय

विदेश मामलों के जानकार

अयातुल्ला खामनेई की तकरीर स्पष्ट तौर पर इंगित कर रही है कि इजराइल और ईरान के मध्य सैन्य संघर्ष और अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अयातुल्ला ने कहा है कि दुनिया के तमाम मुल्कों के मुसलमानों को अपने समस्त मतभेदों को विस्मृत करके अब अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए। अपनी तकरीर में अयातुल्ला ने आगे कहा कि इजराइल एक शैतानी सत्ता है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अमेरिका की मदद से ही इजराइल कायम है और वह ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा। इजराइल पर किसी भी वक्त आक्रमण अंजाम देने के समस्त अधिकार उन्होंने ईरान की सेना को सौंप दिए हैं। तेहरान की मस्जिद में एकत्र हुए लाखों ईरानियों के समक्ष तकरीर करते हुए पश्चिमी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही इस अफवाह पर भी अयातुल्ला खामनेई ने लगातार आवाज दी, जिसके तहत बताया गया था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी बंकर में जाकर छुप गए हैं।

**अमेरिकी राष्ट्रपति को खत लिखा**

7 अक्टूबर 2023 को हमाल और इजराइल के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। हमाल तंजीम द्वारा सीधे हमला करके लगभग 1200 इजराइली नागरिकों का कत्ल कर दिया गया था और तकररीबन 300 इजराइलियों को अगवा कर लिया गया था। हमाल के इस आक्रमण का प्रतिशोध लेने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने हमाल के गद्द गाजा में अनेक हमले अंजाम दिए हैं। इजराइली सैन्य हमले में गाजा पट्टी में तकररीबन 40 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा में हमले के बारे में गाजा में कार्यरत रहे सौ से अधिक अमेरिकन डॉक्टरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक खत लिखा है। इस खत में लिखा है कि गाजा में अमेरिका के हथियारों से बेगुनाह महिलाओं और बच्चों का निर्भय कत्ल अंजाम दिया जा रहा है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले अमेरिका के लिए इजराइल की हिमायत करना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। सैन्य संघर्ष प्रारंभ होने के तकररीबन एक साल पश्चात् ईरान द्वारा इजराइल की सरजमा पर एक अक्टूबर 2024 को 181 सुपरसोनिक मिसाइल दाग दी गई। अयातुल्ला खामनेई ने इस जंग को एक खतरनाक मोड़ तक पहुंचा दिया है।

ईरान के शिया नेता अयातुल्लाह खामनेई अब हमाल बनाम इजराइल जंग को मुसलमान बनाम यहूदी जंग का खतरनाक आयाज प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड के देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2024 को भी ईरान द्वारा इजराइल पर 110 मिसाइलें दागी गई थीं। लेकिन अप्रैल के

## विश्वयुद्ध की ओर सरकता मध्य-पूर्व अस्तित्व की जंग लड़ रहा इजराइल



इजराइल-ईरान

रहीस सिंह

वरिष्ठ पत्रकार

इजराइल सीधे ईरान द्वारा 181 बैलेस्टिक मिसाइलें दागने के बाद 4 अक्टूबर को जंग ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई करीब चार वर्ष बाद जब सार्वजनिक मंच पर आए तो उन्होंने इस्लामी देशों को संदेश देने के उद्देश्य से दो बातें कहीं, पहली यह कि ईरान के दुश्मन वही हैं जो फलस्तीनी शासन और लेबनान समेत दूसरे मुस्लिम देशों के भी दुश्मन हैं। यानि अब वे शिया और सुन्नी के बीच स्पष्ट हो चुकी विभाजक रेखा को मिटाना चाहते हैं। हालांकि विभाजक रेखा अब खाई का रूप ले चुकी है इसलिए इसे पाट पाना नामुमकिन सा है। उन्होंने जो दूसरी बात कही वह यह कि हमारे सशस्त्र बलों ने जो किया वह 'डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स' की नीति रखने वाले जार्जिनट शासन के चौंका देने वाले अपराधों के लिए कम से कम सजा थी। इस तरह से उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया को वैध और उचित ठहराया। उधर हिज्बुल्ला ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की प्रतिज्ञा लेते हुए स्पष्ट किया है कि गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान तथा उसके लोगों को रक्षा के लिए वो लगातार समर्थन करता रहेगा। जबकि इजराइली डिफेंस फ़ोर्स (आईडीएफ) की तरफ से कहा गया है कि "हमारी जंग लेबनान के लोगों से नहीं बल्कि हिज्बुल्लाह से है।" इससे यह नहीं दिखता कि अभी भी प्रॉक्सी युद्ध की संभावनाएं अधिक हैं क्योंकि ईरान और इजराइल सधा हुआ युद्ध लड़ना चाहते हैं अथवा वे युद्ध के साथ बचने के रास्ते भी तलाश रहे हैं? तब क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि मध्य-पूर्व का टकराव तीसरे विश्वयुद्ध में बदल सकता है? पिछले दिनों इजराइली प्रधानमंत्री ने यूएन जनरल असेंबली में कहा था कि लक्ष्य पूरा होने तक हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विषय में अभी यह पूरी तरह से तय नहीं है कि वह सीधे लड़ेगा अथवा प्रॉक्सी युद्ध को ताकत देगा। हालांकि उसका सीधे लड़ना मुश्किल होगा क्योंकि सैन्य इनवेजन के जरिए वह लड़ नहीं सकता और हमाल युद्ध में वह इस्लाम के सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में अभी किन्हीं परिणामों तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ इजराइल को लें, तो सवाल यह उठता है कि उसका असली दुश्मन कौन है? उसकी दुश्मन हिज्बुल्ला और हमाल नहीं हैं बल्कि ईरान है। जैसा कि कभी इजराइली प्रधानमंत्री बेनेट कह चुके हैं कि तेहरान ऑक्टोपस का सिर है, तो

लेबनान में हिज्बुल्ला, गाजा में हमाल और यमन में हूती उसके हाथ हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान के प्रॉक्सी से निरंतर युद्ध करके इजराइल खुद को थका डालने का रिस्क ले रहा है? वैसे इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य इनवेजन शुरू कर दिया है, यह संभवतः उसे हित में नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि वियतनाम युद्ध अमेरिका के हित में नहीं रहा था। हालांकि इजराइल एयर स्ट्राइक्स को हिज्बुल्ला के रॉकेट और मिलिट्री स्टैंडिशमेंट को ध्वस्त करना जरूरी मानता है, जो है भी क्योंकि हिज्बुल्ला लेबनानी नागरिकों को 'ह्यूमन शील्ड' की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने मिसाइल और रॉकेट्स को इनके यहां छुपा कर अटक करता है। लेकिन ईरान इसे इजराइल द्वारा किया गया 'मास मर्डर' मानता है जिसका बदला लेने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह इजराइल को कई



बार चेतावनी दे चुका है कि वह रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। अब देखना यह है कि वह इजराइल के खिलाफ 'ऑल आउट वार' का चुनाव करता है या फिर प्रॉक्सी वॉर के जरिए ही आगे बढ़ेगा? यह सवाल बार-बार आता है कि युद्ध के नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे? प्रथमदृष्टया तो इजराइल के पक्ष में हैं। पिछले नतीजे देखें तो इजराइल ने डिफेंस स्ट्रेटजी, रियल टाइम इंटेलिजेंस और हिज्बुल्ला पर बड़ी विजय प्राप्त करने में सफलता पायी है। ध्यान रहे कि 1992 से 2006 के बीच नसरल्ला और हिज्बुल्ला की प्रगति को देखते हुए इजराइल ने यह समझ लिया था कि हिज्बुल्ला को खत्म करना आसान नहीं है। इसलिए उसने हिज्बुल्ला को कमजोर करने के लिए उसके कमांडरों को मारने की रणनीति अपनाई। यह एक लंबी रणनीति थी जिसे आप 'मोइंग द ग्रास स्ट्रेटजी' नाम दे सकते हैं। इजराइल सतत रूप से इस पर कार्य करता रहा जिसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पेजर बम है, जिसमें लगभग 3000 के आसपास हिज्बुल्ला लड़ाके घायल हुए। इसी की वजह से इजराइल 'रियल



ईरान के शिया नेता अयातुल्लाह खामनेई अब हमाल बनाम इजराइल जंग को मुसलमान बनाम यहूदी जंग का खतरनाक आयाज प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड के देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2024 को भी ईरान द्वारा इजराइल पर 110 मिसाइलें दागी गई थीं। लेकिन अप्रैल के आक्रमण से पहले सारी दुनिया को ईरान द्वारा बाकायदा चेता दिया गया था कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजराइली हमले का जवाब देने के लिए ईरान द्वारा हमला अंजाम दिया जाएगा। दागी गई ईरानी मिसाइलों के प्रतिशोध में इजराइल ने ईरान के विरुद्ध तो कोई सैन्य कदम नहीं उठाया था, लेकिन लेबनान में हिज्बुल्ला तंजीम के ठिकानों पर अपने आक्रमणों को तेज कर दिया। ईरान समर्थित हिज्बुल्ला तंजीम लेबनान में तकररीबन अपने एक लाख जिहादियों के साथ विद्यमान है। गाजा में हमाल के विरुद्ध इजराइली आक्रमण शुरू होने के साथ ही साथ हिज्बुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर हमले अंजाम देना शुरू कर दिया था। हाल ही में इजराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा हिज्बुल्ला के कमांडर इन चीफ नसरल्लाह को हलाक कर दिया गया। यह प्रश्न है कि एक अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर 181 सुपरसोनिक मिसाइलों का प्रति उत्तर देने के लिए अब इजराइल की हुकूमत क्या कदम उठाएगी। अमेरिका कदापि नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान में कोई सीधा और बड़ा युद्ध प्रारंभ हो जाए और जिसमें इजराइल की हिमायत में अमेरिका को भी उतरना पड़ जाए।

आक्रमण से पहले सारी दुनिया को ईरान द्वारा बाकायदा चेता दिया गया था कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजराइली हमले का जवाब देने के लिए ईरान द्वारा हमला अंजाम दिया जाएगा। दागी गई ईरानी मिसाइलों के प्रतिशोध में इजराइल ने ईरान के विरुद्ध तो कोई सैन्य कदम नहीं उठाया था, लेकिन लेबनान में हिज्बुल्ला तंजीम के ठिकानों पर अपने आक्रमणों को तेज कर दिया। ईरान समर्थित हिज्बुल्ला तंजीम लेबनान में तकररीबन अपने एक लाख जिहादियों के साथ विद्यमान है। गाजा में हमाल के विरुद्ध इजराइली आक्रमण शुरू होने के साथ ही साथ हिज्बुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर हमले अंजाम देना शुरू कर दिया था। हाल ही में इजराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा हिज्बुल्लाह के कमांडर इन चीफ नसरल्लाह को हलाक कर दिया गया। यह प्रश्न है कि एक अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर 181 सुपरसोनिक मिसाइलों का प्रति उत्तर देने के लिए अब इजराइल की हुकूमत क्या कदम उठाएगी। अमेरिका कदापि नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान में कोई सीधा और बड़ा युद्ध प्रारंभ हो जाए और जिसमें इजराइल की हिमायत में अमेरिका को भी उतरना पड़ जाए।



ईरान के शिया नेता अयातुल्लाह खामनेई अब हमाल बनाम इजराइल जंग को मुसलमान बनाम यहूदी जंग का खतरनाक आयाज प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड के देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2024 को भी ईरान द्वारा इजराइल पर 110 मिसाइलें दागी गई थीं। लेकिन अप्रैल के आक्रमण से पहले सारी दुनिया को ईरान द्वारा बाकायदा चेता दिया गया था कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजराइली हमले का जवाब देने के लिए ईरान द्वारा हमला अंजाम दिया जाएगा। दागी गई ईरानी मिसाइलों के प्रतिशोध में इजराइल ने ईरान के विरुद्ध तो कोई सैन्य कदम नहीं उठाया था, लेकिन लेबनान में हिज्बुल्ला तंजीम के ठिकानों पर अपने आक्रमणों को तेज कर दिया। ईरान समर्थित हिज्बुल्ला तंजीम लेबनान में तकररीबन अपने एक लाख जिहादियों के साथ विद्यमान है। गाजा में हमाल के विरुद्ध इजराइली आक्रमण शुरू होने के साथ ही साथ हिज्बुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर हमले अंजाम देना शुरू कर दिया था। हाल ही में इजराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा हिज्बुल्ला के कमांडर इन चीफ नसरल्लाह को हलाक कर दिया गया। यह प्रश्न है कि एक अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर 181 सुपरसोनिक मिसाइलों का प्रति उत्तर देने के लिए अब इजराइल की हुकूमत क्या कदम उठाएगी। अमेरिका कदापि नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान में कोई सीधा और बड़ा युद्ध प्रारंभ हो जाए और जिसमें इजराइल की हिमायत में अमेरिका को भी उतरना पड़ जाए।

**इजराइल की सैन्य शक्ति के पीछे कौन**

सभी जानते हैं कि इजराइल वस्तुतः अमेरिका की रणनीतिक सहमति के बिना ईरान के विरुद्ध कोई बड़ा सैन्य कदम नहीं उठा सकता। रूस-यूक्रेन युद्ध में संलग्न अमेरिका नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में उसके लिए कोई नया सैन्य मोर्चा खुल जाए।

**जंग की चपेट में आएं मध्य पूर्व के देश**

मध्य पूर्व में अनेक अरब देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर आदि हैं, जोकि अमेरिका के निकट सहयोगी देश रहे हैं। इन देशों के शासक भले ही अमेरिका के साथ रहे हैं, लेकिन इन देशों का जनमानस इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा है। अमेरिकन कूटनीतिज्ञ बखूबी जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच बड़ी जंग अंजाम दी गई तो फिर ये जंग पूरे मध्य पूर्व के देशों को अपनी चपेट में ले सकती है और फिर उधर के सहयोगी अरब राष्ट्रों में शासक अमीर शेरों का तख्ता पलट भी संभव हो सकता है। इजराइल की आंतरिक राजनीति के अंदर अपने प्रबल विरोध के चलते प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि



विश्लेषण

सुनील अमर

वरिष्ठ पत्रकार

ल गभग एक साल पूर्व फिलिस्तीनी संगठन तथा गाजा पट्टी के शासक दल हमाल से इजराइल पर किए गए जिस हमले को अंग्रेजी में 'कॉन्फ्लिक्ट' यानी झड़प बताया गया था आज वह एक ऐसे युद्ध की शकल ले चुका है जिसमें इजराइल अब कम से कम सात मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। इस लड़ाई ने ऐसा राजनीतिक खूब अखिबार कर लिया है जिसमें मध्यपूर्व और एशिया के कई देश यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे किसकी तरफ रहें! यह लड़ाई नई नहीं है और ये दोनों देश अपने जन्म यानी सन् 1947 से ही लड़ रहे हैं।

**मुस्लिम देशों से घिरा है इजराइल**

यह जानना दिलचस्प होगा कि युद्ध की हालत में भी अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदों को ध्यान में रखते हुए तमाम देश किस तरह की भूमिका निभाते हैं। सीमाओं की बात करें तो इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। पूर्व में जार्डन, उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और इजराइल की जड़ कहे जाने वाले फिलिस्तीन के दो इलाके- दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी तथा पूर्व में पश्चिमी तट नाम का क्षेत्र है। इन सभी सीमावर्ती देशों में सैन्य संगठनों के अलावा इस्लामिक मिलिशिया का भी जाल फैला हुआ है। गत वर्ष सात अक्टूबर को जब हमाल ने हमला किया तो कारण यह बताया कि इजरायल ने उनके आदर्शों को बन्धक बनाया हुआ है, सीमाओं को बन्द करके तमाम तरह की आपूर्ति बाधित कर रखी है, विवादों के निस्तारण को तय अन्तरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं मान रहा है तथा गाजा पट्टी निवासियों के तमाम कष्टों का जिम्मेदार है। ध्यान रहे कि फिलिस्तीन गाजा पट्टी और पश्चिमी तट नाम को हिस्सों में बंटा हुआ है जिसमें गाजा पट्टी में वर्ष 2007 से हमाल को शासन है। इजरायल और हमाल की अगर तुलना करें तो हमाल की स्थिति मच्छर सीखी है। अपने दुःखों और हालात से आजिज आकर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमाल ने इजराइल पर हमला तो कर दिया लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत उसने चुकानी पड़ी है।

**वैश्विक संस्थाएं बनाएं दबाव**

इस्लामिक बन्धुत्व के नाम पर जो देश उसकी तरफ से लड़ाई में शामिल हो गए हैं वे भी उसके मौजूद कष्टों को दूर नहीं कर पाएंगे। इजराइल पर

यह जंग और अधिक विस्तार ले ले। नेतन्याहू पहले गाजा में हमाल तंजीम को खत्म करने पर अमादा रहे। फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा अर्थात् पीएलओ के विरुद्ध हमाल तंजीम का निर्माण करने में नेतन्याहू की विशिष्ट भूमिका रही थी। इसके बाद वेस्ट बैंक में पीएलओ को और फिर लेबनान में हिज्बुल्लाह तंजीम को खत्म करने के लिए इजराइल ने धावा बोल दिया। युद्ध उन्माद से त्रस्त रहे नेतन्याहू ने अमेरिका द्वारा पेश की गई युद्ध विराम की सलाह को कदाचित स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका जानता था कि अपनी साख बचाने के लिए ईरान यकीनन इजराइल पर हमला अंजाम देगा।

**अमेरिका की इजराइल को सैन्य मदद जारी**

अमेरिका ने इस बीच इजराइल को प्रदान की जाने वाली सैन्य सहायता रोक देने की भी बात रखी थी, किंतु इस पर अमेरिका ने ही अमल नहीं किया। आने वाले भविष्य में यदि ईरान और इजराइल के मध्य एक बड़ी जंग अंजाम दी जाती है तो फिर इस जंग का मध्य पूर्व में विस्तार होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी। यदि इजराइल को महाशक्ति अमेरिका की सरपरस्ती हासिल रही तो फिर ईरान को भी रूस और चीन दोनों महाशक्तियों की सरपरस्ती हासिल होगी। ईरान की इजराइल पर मिसाइल हमले को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि इजराइल के विरुद्ध ईरान की जंग भारत के लिए भी एक विकट चुनौती सिद्ध हो सकती है। भारत के कूटनीतिक ताल्लुकवात दोनों देशों ईरान और इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। ईरान भारत को तेल के आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में एक देश रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारणवश आयद किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को कूटनीतिक तौर पर अत्यंत संतुलित बनाए रखा है। हाल ही में जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में अचानक मौत हो गई, तब भी भारत सरकार ने देश में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था। वर्ष 1992 में भारत के कूटनीतिक संबंध इजराइल के साथ स्थापित हो गए थे। विगत दो दशकों में दोनों देशों के मध्य परस्पर ताल्लुकवात बेहद मजबूत हो गए हैं। इजराइल वस्तुतः भारत को आधुनिकतम हथियार और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले देशों में शीर्ष देश रहा है।

**भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाना जरूरी**

दोनों देशों ईरान और इजराइल के मध्य कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती सिद्ध हो रहा है। ईरान और इजराइल के मध्य यदि जंग छिड़ जाती है तो फिर दुनिया में तेल का विकट संकट उपरिस्थ हो जाएगा और भारत भी यकीनन इसका शिकार हो जाएगा। ईरान का चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह की मदद से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में पाकिस्तान के मार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। सन् 2015 में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए हाथ मिलाए थे। ईरान और इजराइल के मध्य यदि युद्ध शुरू हो जाता है तो ईरान की प्राथमिकता चाबहार जैसे प्रोजेक्ट से हटकर युद्ध पर केंद्रित हो जाएगी। दुर्भाग्य से ईरान बनाम इजराइल युद्ध का विस्तार अगर मध्य पूर्व में हो जाएगा तो वहां पर कार्यरत 90 लाख भारतीयों पर इसका नकारात्मक असर होगा। उनको मध्य पूर्व के देशों से निकालकर भारत में पुनर्वास करना होगा।

**परवान चढ़ सकता है इस्लामिक जिहाद**

हाल ही में अयातुल्ला खामनेई ने दुनिया के तमाम मुसलमानों से इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया है। अयातुल्ला खामनेई का यह आह्वान यदि वास्तव में अस्तरदार सिद्ध हो गया तो फिर से इस्लामिक जिहाद के नाम पर ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और अल बगदादी सरीखे अनेक आतंकवादी सरगना उठ खड़े होंगे। इतिहास फिर से एक बार अमेरिका को इस ऐतिहासिक खता के लिए अतलत देना कि अमेरिका ने इजराइल को मर्यादा में न रखकर फिर से विश्व पटल पर इस्लामिक जिहाद को परवान चढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरुद्ध जंग करते हुए अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन की क्रयादत में लाखों जिहादियों की तस्वीरें और परिवर्षित अंजाम दी गई थी। जिसका नतीजा वस्तुतः वैश्विक जिहाद के रूप में सारी दुनिया को भुगतान पड़ा। जिहाद के हाथों अमेरिका ने भी बहुत गहरे जख्म खाए थे। इस्लामी जिहाद के विरुद्ध भारत भी सन् 1989 से कश्मीर में निरंतर जूझ रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध की तरह से ही भारत की संभावित इजराइल-ईरान जंग को प्रारंभ नहीं होने देने की कोशिश करना चाहिए। दोनों देश ही भारत के निकट मित्र देश रहे हैं। भारत की वाणी अवश्य समझी और सुनी जाएगी। भारत का संदेश है युद्ध समस्या का हल नहीं है, आतंकवाद सबके दुश्मन हैं।

अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं ही दबाव बना सकती है लेकिन इन संस्थाओं में अमेरिका का दबदबा है और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। गत दिनों उसने इजराइल को लगभग 2000 करोड़ रुपयों की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है तथा ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के साथ हैं। सऊदी अरब के सुरक्षा सम्बन्धी समझौते इजरायल के साथ हैं, लेकिन मन से वह फिलिस्तीन के साथ है इसलिए कूटनीतिक तौर पर वह बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। क्रतर यद्यपि बहुत छोट्टा सा देश है लेकिन वहां अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा है, क्रतर का भाईचारा ईरान के साथ है और इसने हमाल के मारे गये नेता इस्माइल हेंनियाह को कदम रख रहा है। अमेरिका ने वहां अपना सैन्य अड्डा बना रखा



है जिस पर इसी साल जनवरी में ईरान समर्थित गुटों ने हमला कर तीन अमेरिकियों को मार दिया था। जार्डन भी किसी तरह अपना राजनीतिक तालमेल इजराइल से बनाए हुए है।

**हमाल की तरफदारी**

इजराइल का एक और पड़ोसी मिस्त्र है जिसने वर्ष 1979 से इजराइल के साथ मशरूफ कैम्प डेविड शान्ति समझौते की सन्धि कर रखी है, लेकिन इधर फिलिस्तीन की वजह से सम्बन्ध निम्न स्तर पर आ गये हैं और मिस्त्र में जनता तथा विपक्ष ने हमाल को तरफदारी की आवाज उठा रखी है। सीरिया और इराक एक समय में क्षेत्रीय शक्तियां रही हैं लेकिन वहां स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरान समर्थित समूहों ने दर्जनों बार हमला किया हुआ है। इजराइल का एक ताकतवर पड़ोसी तुर्की है लेकिन उससे भी सम्बन्ध ठीक नहीं हैं क्योंकि इसी साल जनवरी में तुर्की पुलिस ने 33 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर इजराइली जासूसी संस्था मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप था। तुर्की ने कहा कि मोसाद के ये जासूस अरोप देश में हमाल के लोगों की तलाश कर रहे थे। दूसरी तरफ ईरान है। क्षेत्र में अपनी संप्रभुता तथा इस्लामिक बन्धुत्व का झंडा बुलन्द रखने के

लिहाज से वह इस लड़ाई में शामिल होना अपना फ्रज समझता है। वैसे तो ईरान के साथ रूस, तुर्की, लेबनान, चीन और यमन हैं।

**ईरान को इन देशों का सहारा**

जहां तक रूस की बात है तो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के खिलाफ समान सोच रखने के कारण रूस और ईरान में दर्शनीय से अच्छे सम्बन्ध हैं। इस संयोग में राजनीतिक दृष्टिकोण तलाश जा सकते हैं कि रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के गत दिनों ईरान दौरे के बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। लेकिन दूसरी तरफ रूस इजरायल को भी साथे रखना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन से चल रही जंग में इजराइल यूक्रेन की मदद करने लगे। उधर, इजराइल भी रूस में रह रहे अपने यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए रूस को नाराज नहीं करना चाहता। इजराइल से मौजूदा लड़ाई को लेकर व्यवधान भी ईरान के साथ हुआ है। वैसे भी लेबनान के सम्बन्ध इजरायल से हमेशा ही लड़ाई और तनावनी के रहे हैं। रूस जैसा ही मामला चीन का भी है। वैसे तो चीन के इजराइल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं लेकिन अमेरिका की वजह से चीन भी ईरान को अपने पाले में रखना चाहता है। ईरान के साथ यमन भी है जिसके हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइली हमला जारी रखा है। इसी प्रकार वर्ष 1948 से ही इजराइल से अपनी लड़ाई को लेकर सीरिया स्वाभाविक ही ईरान के साथ है। संक्षेप में कहें तो एक ग्रुप है जिसका नाम है-एक्सिस ऑफ रेंजिस्टेन्स जिसमें हमाल, हिज्बुल्लाह, सीरिया की सरकार, यमन के हूती विद्रोही तथा सीरिया और इराक के अन्य लड़ाकू समूह शामिल हैं जो ईरान पोषित हैं व वे इसकी मदद कर रहे हैं।

**भारत गुट निरपेक्ष की स्थिति में**

भारत सरकार का अब तक का रवैया गुट निरपेक्ष वाला ही रहा है। भारत ने शुरू से ही दो राष्ट्र के सिद्धान्त पर फिलिस्तीन को मान्यता दे रखी है। इजराइल से भारत के सामरिक सम्बन्ध भी हैं तथा बहुत सारे भारतीय इजराइल में रहते भी हैं। ताजा हालात में भारत ने फिलिस्तीन को 70 टन राहत सामग्री और दवा आदि की सहायता भी दी है। इस युद्ध का एक और पहलू व्यवसाय का भी है जिसका लाभ हमेशा की तरह अमेरिका ले रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद पश्चिम के देश गैस आदि के लिए अमेरिका पर आश्रित हुए हैं तो यूक्रेन व इजराइल को हथियार तथा राहत सामग्री पहुंचाने के नाम पर अमेरिका का धन्या फल-फूल रहा है। विश्व में कहीं भी लड़ाई हो, अमेरिका उसमें अपना धन्या तलाश ही लेता है। नासमझ देश तो बस लड़ने में व्यस्त हैं।



# एक छोटे मुल्क की बड़ी सीख

शशि शेखर

उस वक्त हम हो की मिन्ह सिटी के युद्ध संग्रहालय में थे। वे लम्हे चकित कर देने वाले रोमांच के थे। वहां सिर्फ युद्ध का सजाओ-सामान न था, बल्कि कदम-दर-कदम मानवीय जिजीविषा और सामरिक रचनात्मकता का संगम पसरा हुआ था। वियतनामियों ने फ्रांस, अमेरिका और अपने गृहयुद्ध की यादों को काफी करीने से संजो रखा है। इन अजर-अजर गाथाओं को वे सिर्फ दूसरों को नहीं दिखाते, अपने दिल में भी ह्रदय बसाए रखते हैं।

गुलामी से स्थायी मुक्ति का अकेला रास्ता यही है। इस भवन तक पहुंचने से पहले ही हमें उन अमेरिकी तोपों और टैंकों के दर्शन होने लगते हैं, जिन्हें अमेरिकी सैनिक छोड़ भागे थे। मैंने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां देखे। युवा अपने बच्चों को और बुजुर्ग अपने नाती-पोतों को अनूठी समरगाथा से रू-बरू कराने वहां आए थे। संगृहीत तोप, गोले, हेलीकॉप्टर और अन्य आयुधों के आगे चर्मा विवरणों को वे बेहद ध्यान से देखते और इन्वीनान से बच्चों को बताते। मैं इतने मुल्कों में घूमा किया, पर ऐसा अंदाज इससे पहले कहीं नहीं दिखाई दिया।

वियतनाम में गुजरे वे चार दिन रह-रहकर हॉवर्ड फास्ट की माई ग्लोरियस ब्रदर्स का वह संवाद याद दिलाते, जो ईसा से पूर्व स्थापित हुए यहूदी मुल्क के हर भाषिंदे की जुबान पर था- हम एक हजार साल पहले मिश्र में गुलाम थे। आज तक इजरायल उसी राह पर चल रहा है। वियतनाम ने उसे सुथरे तरीके से अपना लिया है। वह इजरायल की तरह पड़ोसियों से जंग नहीं लड़ रहा। इधर, चीन से भी उसके रिश्ते सुधरे हैं। हालांकि, वहां का आम आदमी चीन के नाम पर मुंह बिचकाता है। चीन ने एक हजार साल उन पर हुकूमत की थी। शताब्दियां बीत गईं, पर वियतनाम के खुददार लोग चीनियों की दमन-गाथा को बिसरा नहीं पाते। पराधीनता के विरुद्ध भावनाओं का

ऐसा सामूहिक ज्वार मैंने कभी कहीं और नहीं देखा। वे महज अपनी आजादी से संतुष्ट नहीं हैं। उनमें जबरदस्त प्रगति-कामना भी है।

यही वजह है कि भूगोल में हमारे राजस्थान से छोटा होने के बावजूद उनकी तरक्की आंखें खोलने वाली है। युद्ध और गृहयुद्ध के दशकों लंबे दौर से गुजरकर वह 1976 में अपने पैरों पर खड़ा हो पाया, मगर अगले पच्चीस वर्ष गांवों से उबरने के थे। उसने गति पकड़ी इस सदी के आरंभ से और अभी चौबीस साल भी नहीं पूरे हुए, पर 99 फीसदी से ज्यादा घरों में बिजली है। वियतनाम में बिजली आंख-मिचौली भी नहीं खेलती और 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास साफ पीने का पानी है। यही नहीं, 87 प्रतिशत से भी अधिक वियतनामी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा रहे हैं। विश्व बैंक की रपट बताती है कि साल 2022 में महज 4.2 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह बचे थे।

यात्रा के दौरान हम 70 किलोमीटर दूर मेकांग डेल्टा देखने के लिए राजमार्ग से गए। 'एक्सप्रेस वेज' का ऐसा रूप मैंने अमेरिका में भी नहीं देखा। कहीं कोई गड्ढा नहीं, गति अवरोधक नहीं और आगे निकलने की जानलेवा होड़ भी नहीं। इससे पहले राजधानी की सड़कों को भी परखा था, कहीं कोई ट्रैफिक सिपाही नहीं, लेकिन जाम का नामोनिशान तक नहीं। मैंने एक बार भी वहां हॉर्न की ध्वनि नहीं सुनी। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में जगह-जगह लिखवाया नारा याद आ गया - अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम उस थोपे गए अनुशासन से कितना महान देश बना पाए? वियतनाम में स्व-अनुशासन जीवनशैली का मुकम्मल हिस्सा लगा।

कोई आश्चर्य नहीं कि दस करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के हिसाब से 1.350 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में यहां की विकास दर छह फीसदी से अधिक आंकी है। अगले वर्ष इसमें बढ़ोतरी का अनुमान



है। यही वजह है कि इस वर्ष के पहले आठ माह में ही उसे 14.15 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हासिल हुआ है। भारत आकार, आबादी और अर्थव्यवस्था में उससे कहीं बड़ा है, पर इस वर्ष हमें 2023 के मुकाबले कम विदेशी निवेश प्राप्त हो सका है।

यह हमारे लिए खतरे की घंटी बले न हो, पर चेतेने की बात जरूर है। वियतनाम आसियान का सदस्य है। इसके देशों की कुशल आबादी दुनिया के सामने असीम संभावनाएं पेश करती है। वियतनाम में शिक्षा को कितनी जरूरी दी जाती है, इसका अंदाज सिर्फ इस तथ्य से लग जाता है कि अकेले हो की मिन्ह

सिटी में 55 विश्वविद्यालय हैं। इसी चलन के चलते इन देशों ने पिछले 30 वर्षों में काबिल-ए-गौर तरक्की हासिल की है। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का दंभ भरने वाले पश्चिमी देशों का नकाब यहां भी हवा का झोंका बन जाता है। उन्हें ऐसे मुल्कों का राजनीतिक वातावरण रास आता है। इनमें से अधिकांश देशों में आर्थिक प्रगति को लोकतांत्रिक मूल्यों पर तरजीह दी जाती है। वियतनाम में एकदलीय व्यवस्था है। चीन की तरह वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। वहां बोलेने की आजादी है, पर सरेआम अपने देश के बारे में बात करने में लोग हिचकते हैं। माँस्को और बीजिंग की भाँति वहां के बाशिंदों को भी लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है।

मुझे इसका इल्म न होता, अगर फैन्सी सैमॉन मॉल में मैंने एक नौजवान से पूछ न लिया होता कि क्या आप खुद को कॉम्प्रेड मानते हैं? उसने इधर-उधर देख फुसफुसाकर बोला था- हम 'रेड कैपिटलिस्ट' हैं। मतलब? उसका उत्तर था ऊपर से हमारे नेता सोशलिस्ट हैं, पर अंदर से कैपिटलिस्ट कहीं हर ओर पसरे अनुशासन की असली वजह यही तो नहीं? चाहे जो हो, पर विलासिता की वस्तुओं से दमकते स्टोर्स भरे पड़े थे। दिल्ली और एनसीआर के कम ही मॉल ऐसे होंगे, जहां एक साथ इतने लज्जरी स्टोर हों।

कहते हैं, हर चमक-दमक के पीछे गहरी कालिमा छिपी होती है। वियतनाम में भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। वहां के युवा विवाह संस्था से मुंह मोड़ रहे हैं। एक 28 साल के नौजवान ने बताया कि हमारी शादी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। महंगाई इतनी है कि बच्चे कैसे पलेंगे? मैंने उससे पूछा कि आपके यहां तो शिक्षा 'फ्री' है, फिर कैसी दिक्कत? उसका उत्तर था, यह ठीक है कि बच्चे के लिए फीस की व्यवस्था नहीं करनी होगी, पर उसे पालने के लिए कई अन्य खर्च करने पड़ेंगे। वे कहां से आएंगे? वह गलत न था। मेरे लिए यह पहला मुल्क था, जहां मैंने पांच लाख का नोट देखा। भारतीय युद्ध में उसकी कीमत अमूमन दो हजार रुपये होती है।

हालांकि, वियतनाम अकेला इस बला का शिकार नहीं है। लगभग सभी देश इस सामाजिक संक्रमण की चपेट में हैं। मैं इससे चिंतित होने के बजाय अपने हमवतनों से इस छोटे मुल्क की बड़ी छलांग से सीखने की आकांक्षा रखता हूँ।

@shekharkahin  
@shashishekharkahin

चीन ने एक हजार साल उन पर हुकूमत की थी। शताब्दियां बीत गईं, पर वियतनाम के खुददार लोग चीनियों की दमन-गाथा को बिसरा नहीं पाते। पराधीनता के विरुद्ध भावनाओं का ऐसा सामूहिक ज्वार मैंने कभी कहीं और नहीं देखा। वे महज अपनी आजादी से संतुष्ट नहीं हैं। उनमें जबरदस्त प्रगति कामना भी है।

स्कैन करें  
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

जीना इसी का नाम है

सुबोनेन्वा लोंगकुमेर  
सामाजिक कार्यकर्ता

## खुद रहे अनाथ, पर सैकड़ों बच्चों के बन गए नाथ

यतीम बच्चों से परिजनों की हमदर्दी तो थी, मगर चार-चार किशोरों की जिम्मेदारी उठाना किसी एक परिवार के लिए मुमकिन न था। लिहाजा चारों भाई-बहन को उन्होंने तकसीम करने का रस्ता चुना। दुख ईंसान को जोड़ता है, मगर यहां एक ही दर्द के सभी साझेदार बंट गए।

कहते हैं, धरती के हर ईंसान का जीवन अपने आप में एक उपन्यास होता है, मगर इनमें से कुछ की ही कहानियां सलीके से दर्ज हो पाती हैं। कुछ के संघर्ष, उनकी उपलब्धियां किसी रोशनदान से कम नहीं होतीं। वे अनगिनत लोगों को सदकर्मों के लिए प्रेरित करती हैं और जमाना भी उन्हें झुककर सलाम करता है। आज ऐसी ही एक कहानी के नायक हैं सुबोनेन्वा लोंगकुमेर। नगालैंड के मोकोकचुंग जिले में एक गांव है कांग्सुंग, सुबोनेन्वा इसी गांव में पैदा हुए। नगालैंड समेत पूर्वोत्तर के सुबोनेन्वा में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर इसलिए है कि वहां के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों ने भी बहुत पहले शिक्षा की अहमियत जान ली थी। कांग्सुंग गांव के लोग तो सुबोनेन्वा के पिता ओ यंगर लोंगकुमेर की मिसालें दिया करते थे, जिन्होंने सन् 1977 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री हासिल की थी और एक श्रम अधिकारी बन गए थे। सुबोनेन्वा की मां भी छठी तक पढ़ने वाली चंद महिलाओं में एक थीं।

लोंगकुमेर परिवार खुशहाल था। चार भाई-बहन में सुबोनेन्वा दूसरे हैं। जब वह नौ साल के थे, तभी पिता की कैसर से मौत हो गई। मां को पिता की कंपनी के अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई थी, मगर तीन हजार रुपये की तनखाह में पांच सदस्यों के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया। मां तनाव में रहने लगी थीं। पिता को गए बमुश्किल तीन साल हुए होंगे कि एक दिन अचानक मां ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। 12 साल की उम्र में ही सुबोनेन्वा अनाथ हो गए। बहन और एक भाई तो उनसे भी छोटे थे।

चारों भाई-बहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हुआ है? सुबोनेन्वा और उनके भाई-बहन पर पिता के बीमार पड़ने से जो गम की बरसात शुरू हुई, वह बरसती चली जा रही थी। उनका परिवार जिस नया जनजाति का हिस्सा है, उसमें तीन दिन तक शोक मनाया जाता है। परंपरा के मुताबिक मां की मौत के चौथे दिन सभी रिश्तेदार जुटे, ताकि परिवार की संपत्ति को विरासत और बच्चों के भविष्य के बारे में कोई फैसला किया जा सके। यतीम बच्चों के साथ परिजनों की हमदर्दी तो थी, मगर चार-चार किशोरों

की जिम्मेदारी उठाना किसी एक परिवार के लिए मुमकिन न था। लिहाजा चारों भाई-बहन को उन्होंने आपस में तकसीम करने का व्यावहारिक रास्ता चुना। दुख तो ईंसान को जोड़ता है, मगर यहां एक ही दर्द के सभी साझेदार बंट गए। सुबोनेन्वा उस समय सातवीं कक्षा में थे। जिस चाचा के यहां उन्हें पनाह मिली, वहां उन्हें भोजन और कपड़े तो मिल जाते, मगर पढ़ाई का खर्च उठाने को चाचा राजी न थे। बल्कि जल्द ही सुबोनेन्वा से यह अपेक्षा की गई कि चाचा के ढाबे में काम करके वह



अपने गुजारे का खर्च जुटाएं। सुबोनेन्वा पढ़ना चाहते थे, मगर कोई रिश्तेदार हाथ नहीं बढ़ा रहा था।

कई बार रक्त संबंधियों से ज्यादा बाहर के लोग अपने साबित होते हैं। पिता के एक पुराने दोस्त को जब यह बात पता चली, तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुबोनेन्वा और उनके बड़े भाई की मैट्रिक तक पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अगले चार वर्षों तक उन्होंने न सिर्फ उन दोनों की स्कूल फीस भरी, बल्कि उनके लिए एंटी-कॉलेज और स्कूलों पोशाकें भी खरीदीं। मगर चाचा के यहां रहने के बदले में सुबोनेन्वा को

काफी श्रम करना पड़ता। वह ढाबे पर पानी भरते, लकड़ियां लेकर आते, मेहमानों के लिए खाना पकाते और भी कई दूसरे काम निपटाते। इसके बाद स्कूल जाने का नंबर आता। मैट्रिक के बाद बड़े भाई की नगालैंड पुलिस में नौकरी लग गई, तो बड़ा सहारा मिला। उनकी आर्थिक मदद से सुबोनेन्वा ने साल 2000 में ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उन्हीं दिनों उन्हें दीमापुर के एक गैर-सरकारी संगठन 'वर्ल्डविजन इंडिया' के बारे में पता चला। यह संगठन शिक्षा के जरिये बाल श्रमिकों के पुनर्वास में जुटा था। सुबोनेन्वा खुद यह दर्श भोग चुके थे। उन्होंने उस संगठन में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया।

सुबोनेन्वा बाल श्रमिकों को पढ़ाना चाहते थे, मगर वर्ल्ड विजन इंडिया ने दो बार उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि वे इसकी योग्यता नहीं रखते। अलबत्ता, उसने 2,000 रुपये मासिक तनखाह पर ड्राइवर की नौकरी का प्रस्ताव जरूर दिया। सुबोनेन्वा चाचा के यहां लौटकर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अगले पांच वर्षों तक वह बतौर स्वयंसेवक इसमें सक्रिय रहे। इस दौरान वह सड़क के लावारिस बच्चों से बातें करते, उनमें अच्छी जिंदगी जीने के सपने जगाते और संगठन के स्कूल में आने को प्रेरित करते। आखिरकार संगठन ने सुबोनेन्वा को शिक्षक बना दिया। सुबोनेन्वा स्कूल से जुड़े अन्य प्रबंधकीय काम भी सीखते गए।

मगर जब एनजीओ की फंडिंग बंद हो गई और 2005 में उसने वहाँ से किसी अन्य जिले में जाने का फैसला कर लिया, तो सुबोनेन्वा बेचैन हो उठे। उन्हें उन 300 बच्चों के भविष्य की चिंता सोने नहीं देती, जो इस स्कूल में पढ़ रहे थे। बहुत अनुरोध-मनुहार के बाद वह स्कूल उन्हें चलाने की इजाजत दी गई। अपनी पुरानी कार बेचकर सुबोनेन्वा ने शिक्षकों की कुछ तनखाह अदा की। इस तरह 'कम्युनिटी एजुकेशनल

आज सुबोनेन्वा दो स्कूलों के चेयरमैन हैं। उनकी देख-रेख में आठ अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। सुबोनेन्वा अब तक करीब 2,000 बाल श्रमिकों और यतीम बच्चों की जिंदगी शिक्षा के जरिये रोशन कर चुके हैं। उनके स्कूल से निकले सैकड़ों बच्चे आज सरकारी, निजी नौकरियों में हैं।

सेंटर सोसायटी' की शुरुआत हुई। साल 2008 में नगालैंड सरकार ने इसे गैर-सरकारी संगठन की मान्यता दी। आज सुबोनेन्वा दो स्कूलों के चेयरमैन हैं। उनकी देख-रेख में आठ अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। सुबोनेन्वा अब तक 2,000 बाल श्रमिकों व यतीम बच्चों की जिंदगी शिक्षा के जरिये रोशन कर चुके हैं। उनके स्कूल से निकले सैकड़ों बच्चे आज सरकारी, निजी नौकरियों में हैं, कई विशेष-विद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं।

प्रस्तुति: चंद्रकांत सिंह

बेगम अख्तर  
संगीतज्ञ गायिका

## संगीत की शक्ति से संवर गई जिंदगी

अनेक बेटियों- गणिकाओं या तवायफों ने भी संगीत को सहेजा। गुलामी के दिनों में देश के राजा-रजवाड़े जब कमजोर हुए, तो इन बेटियों का भी स्तर घटा। उनकी जिंदगी में चकाचौंध के चंद द्वीप तो थे, पर सागर जैसे अथाह बदनम अंधेरों से घिरे हुए।



अपने देश में ऋषियों ने संगीत को अपनी तपस्या की आंच पर तपाया और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिखाते चले गए। ईश्वर आराधना के लिए बना संगीत मनोरंजन का भी साधन बनकर अलग-अलग हाथों-कानों-गलों तक पहुंचा। इतिहास के अनेक पड़ावों पर इसी देश की अनगिनत बेटियों- गणिकाओं या तवायफों ने भी संगीत को सहेजा। गुलामी के दिनों में देश के राजा-रजवाड़े जब कमजोर हुए, तो इन बेटियों का भी स्तर घटा। उनकी जिंदगी में चकाचौंध के चंद द्वीप तो थे, पर सागर जैसे अथाह बदनम अंधेरों से घिरे हुए। ऐसे ही माहील में एक थीं मुश्तरीबाई अपनी बेटे के लिए एमेशा बेचैन। कभी तकदीर का मातम कभी दुनिया का गिला... ए मोहब्बत त्वरे अंजाम पे रोना आया।

मां चाहती थी कि बेटे संगीत से कहीं दूर चली जाए, तो कोई उम्दा हमसफर मिल जाए, इस जंजाल से निकल जाए। किस्मत देखिए, बेटे ने संगीत से ही दिल लगा लिया। खैर, मजबूर मां ने संगीत सीखने के लिए एक उस्ताद का इंतजाम किया। बेटे सीख रही है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख ले। फैजाबाद, लखनऊ, गंगा भटकते जिंदगी बीतने लगी। बेटे भी थोड़ा-बहुत गाने-बजाने लगीं। बेचैन मां दुआ करती थीं कि बेटे को कोई दरबार नहीं, कोई अच्छा मंच मिल जाए।

संयोग की बात है, उन्हीं दिनों बिहार के भूकंप पीड़ितों के राहत कोष के लिए कोलकाता में बड़ा संगीत आयोजन हुआ। कई दिग्गज कलाकार वादिके बावजूद नहीं पहुंचे। महफिल जम न रही थी। श्रोताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच आयोजकों ने प्लान कर दिया कि अब आपके सामने आ रही है युवा गायिका अख्तीरबाई फैजाबादी। सामने हजारों की भीड़ देख बेटे अर्थात् अख्तीरबाई घबरा गईं, तब उस्ताद ने हौसला बढ़ाया, मां ने गर्व भरी आंखों से बल दिया, तब बेटे ने गाया- तूने बुत-ए हरजाई कुछ ऐसी अदा पाई, ताकता है तेरी सूरत हर एक तमाशाई...। लोग झुमने लगे। गजल, दादरा, तुमरी की फरमाइश शुरू हो गई। करीब ढाई घंटे चला गायन, मतलब बेटे ने अपना पहला ही सार्वजनिक मंच जीत लिया। आयोजकों की खुशी का ठिकाना न था। संयोग देखिए, वहां स्वतंत्रता सेनानी संरंजनी नायडू मुख्य अतिथि थीं। वह इतनी खुश हुईं कि देश की उभरती गायिका बेटे को एक सुंदर साड़ी ओढ़ाकर सम्मानित किया।

जब सब बेटे का सम्मान करने को लालायित थे, तब मां

की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां समझ गईं, हुनरमंद बेटे ने मुख्यधारा की दुनिया का दरवाजा खोल लिया है और अब कभी उसे पीछे नहीं लौटने देना है। बेटे ने पकड़ें दमदार दस्तक दी थी। किस्मत चमक उठी थी। उस जमाने में एक पारसी थियेटर कंपनी ने 700 रुपये महीना देने का अनुबंध कर लिया, तब सोने का भाव 16 रुपये तोला हुआ करता था। उस्ताद ने मना किया कि नाटक में अभिनय न करना, फिर संगीत में न लौट पाओगी, पर मां ने उत्साह बढ़ाया और बेटे के गायन-अभिनय से सुसज्जित नाटक नई दुल्हन कोलकाता में पूरे साल चलता। उंका बज गया। नाटक और सम्मान के साथ लखनऊ वापसी हुई। ग्रामोफोन रिकॉर्ड और फिल्मों में भी नाम चल पड़ा। बेटे की आवाज में जादू था- कोयलिया मत कर पुकार, लगत करेजवा कटर...। मधुर-मदमस्त आवाज ने हर रसिक को भिगो दिया, हमरी अटरिया पर आओ संवरिया, देखा देखी बलम होइ जाए।

बेटे का समाज बहुत ऊंचा और बड़ा होता गया, वह शोहरत की सीढ़ियां चढ़ती गईं और थोड़ी दूरी रखते हुए मां हमेशा बेटे के पीछे साये की तरह डटी रहीं। खैर, एक दिन बेटे को नवाबी खानदान का शानदार बैरिस्टर शौहरत भी नसीब हुआ, नाम हो गया बेगम अख्तर, पर संगीत, फिल्म से नाता तोड़ना पड़। रस्मो-रिवाज के ऐसे ताले लगे कि एक नामी कोयल महलनुमा घर में कैद हो गई। यह कैद तब खत्म हुई, जब मां दुनिया छोड़ गईं। मां की कब्र थामकर बेगम अख्तर घंटों रोती थीं और याद करती थीं- मेरे दाग-ए-दिल से है रौशनी इसी रौशनी से है जिंदगी, मुझे डर है ए मरे चारागर ये चयता तू ही बुझा न दे।

बहरहाल, बेगम को मां के गम में तबाह होते देख शौहरत साहब भी पिघल गए। संगीत के तुफान को भरला कौन रोक पाया है? करीब सात साल बाद रेडियो स्टेशन पर गाने से वापसी हुई थी- अब के सावन घर आ जा... उर उर कगवा ले जहवो संदेशवा... अब के सावन घर आ जा...। बताते हैं कि उस दिन रिकॉर्डिंग सुनते हुए वह खूब रोई थीं। यह दुनिया 7 अक्टूबर को मॉलिका-ए-गजल बेगम अख्तर (1914-1974) का जन्मदिन मनाती है। इस देश में उन्हें सुन-सुनकर न जाने कितने लोग शायर, गायक हुए जा रहे हैं और वह सुनाए जा रही हैं- वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो...।

प्रस्तुति: ज्ञानेश उपाध्याय

## रचना से बड़ी रचनाकार की लीलाएं

गए वे दिन, जब अरसे तक कविता, कहानी लिखने के बाद ही कोई चर्चा में आता। लेखक रचना पर बरसों काम करते। प्रकाशित होती, तो बड़े-बड़े 'रिव्यू' होते। आलोचक मूल्यांकन करते और रचना 'क्लासिक' हो जाती। जितनी मेहनत होती, लेखक का उतना ही बड़ा प्रभाव-मंडल होता। रचना, रचना होती।

कोई देर रात तक पीता, फिर आधी रात में फोन करके अपनी उपेक्षा के लिए रोता रहता, उसके बाद भैरवी सुनाने लगता। कोई रात को ज्यादा पीकर किसी नाली नाले में गिरकर चोट खाता, लेकिन अगली शाम कॉफी हाउस में अपने गिरने की वीरता का गायन-वादन करता मिलता। बहुत से रचनाकार इसी तरह आधी रात के रचनाकार कहलाने लगते।

लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, तब से साहित्य की सूरत और सीरत, दोनों ही बदल गई। रचना का मंगलाचरण दंगलाचरण में बदल गया। साहित्य में 'बिचिंग, डिबिंग और लिचिंग' की नई विधाएं आ बैठीं। अभी निंदा और अभी स्तुति; अभी मेरा सबसे दुलारा दोस्त और अगले

तिरछी नजर

सुधीरा पवौरी हिंदी साहित्यकार

ही पल सबसे बड़ा हरामी, समझौतापरस्त, बिका हुआ, चाटूकार, गिरहकट, उठाईगीर, चोर, डकैत; कि मेरा मुंह न खुलवा, नहीं तो तेरी सात पुरतों को नंगा कर दूंगा जैसे आप वचनों में जितना चर्चा रस बरसने लगा, उतना रचना में बरसता। लोग 'गॉसिप' सुनते और मुझे लेते। इसने मेरा 'आइडिया' मारा, उसने उसकी कविता-कहानी मारी, उसने उसका पता काटा, उसका नाम अमुक लिस्ट से कटवाया, उसने उसका नाम कूट दिवली आया, तो साले टोंगे तुड़वाकर हाथ में दे देंगे। उसने उसका मकान मार लिया, उसने पहली को छोड़ दूसरी कर ली, उसने उसको जातिवादी कहा, उसने उसे 'कम्यूनल, संघी और हिंदुत्ववादी' कहा...इन दिनों ऐसे ही चर्चा रस बरसते दिखते हैं।



रचना पीछे हो गई। रचना से बड़ी रचनाकार की लीलाएं हो गईं। सब सोशल मीडिया का जादू। उसने एक ऐसा सोशल साइबर रचनाकार गढ़ा, जो एकदम फ्री स्टाइल कुशलीबाज है और बिंदस है। सोशल मीडिया के अंध जनतंत्र में असली चोरी-चोरी करेडो रचनाकारों की भीड़ का ध्यान खींचने की है। ध्यान तभी खिंचता है, जब जुबान में तुर्शी हो, वह तीखी-कड़वी हो। इस तरह होल खोल और टोपी उछाल की भाषा ही सबसे बड़ी साहित्यिक भाषा हो गई। जितनी गाली, उतनी ताली। साहित्य की जगह साहित्यकार के ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, मान मत्सर ने ले ली। अब न कहीं कविता है, न कहानी है और न आलोचना है। वह लेखक की ईर्ष्या-द्वेष से युक्त कोई कट्टरतंत्र है, जो दो दिन अमर रहनी है।

फिर उसकी जगह जवाबी कट्टरता आ जानी है। पढ़ने वाले मजे लेते हैं। यही असली साहित्य है। कोई कोशिश करे, तो साहित्य कोश की तरह एक नया 'गाली कोश' तैयार कर सकता है।

उसने उसे ठोक दिया, उसने उसके साथ मंच पर बैठने से मना कर दिया, उसने शुक्लजी को ब्राह्मणवादी कह दिया, उसने प्रेमचंद को कायस्थ कह दिया, उसने उसकी खटिया खड़ी कर दी, उसने उसकी बोलती बंद कर दी, इनकी चर्चा ही साहित्य है। यही नए मानक हैं। लिखो न लिखो, चर्चा में दिखो। चर्चा ही रचना है। चर्चा रस साहित्य का नया रस है। कीचड़ है, तो चर्चा है। लीचड़ है, तो चर्चा है। वरना आप लाख लिखते रहें कविता, कहानी, आलोचना, आप दो कौड़ी के भी नहीं।

कभी कहा गया था- काव्यशास्त्र विनोदने कालो गच्छति धीमताम्। व्यसनं च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। अर्थात् ज्ञानी काव्यशास्त्र का विनोद करते हुए अपना समय काटते हैं, जबकि मूर्ख या तो सोने में या कलह करने में या व्यसन में व्यस्त रहते हैं। इन दिनों तो यह कलह रस ही कला रस है। इस कलह रस को देख अकबर का लाहाबादी का शेर याद आता है: बूट ड्रासन ने बनाया, मैंने इक मजमूं लिखा! मुल्क में मजमूं न फैला, और जूता चल गया!

कटाक्ष  
राजेंद्र घोड़पकर

